R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth
पाक्षिक
अक्स
वर्ष : 23 । अंक : 21
01 से 15 अगस्त 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

संसद में हंगामा है बरपा...कामकाज अधर में लटका

सिंदूर, वोटर, धनखड़ जनता की नहीं फिकर

सदन में कार्यवाही कम, हंगामा अधिक होने की बनी परंपरा

हंगामा करके करोड़ों टैक्स मनी बर्बाद कर रहे माननीय

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

इस अंक में

राजपाट

8 | नए प्रदेशों की मांग तेज

देश में एक बार फिर से नए राज्यों को बनाने की मांग उठ रही है। इनमें दो प्रदेशों की मांग ऐसी है जो मप्र से संबंधित हैं। पहला भील प्रदेश और दूसरा चंबल प्रदेश। 18 जुलाई को राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में मप्र...

डायरी

10-11 | 6-7 महीने प्रभार पर...

उज्जैन संभागायुक्त संजीव गुप्ता रिटायर हो गए हैं। अब उनकी जगह नए संभागायुक्त की नियुक्ति की जानी है। सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि ऐसे अधिकारी को संभागायुक्त बनाया जाए, जिसके नेतृत्व में...

भर्राशाही

14-15 | अपने ही जाल में...

मप्र के सबसे धनाढ्य विधायक संजय पाठक इन दिनों जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। दरअसल, संजय पाठक ने नियम-कायदों को ताक पर रखकर सहारा समूह के साथ ही आदिवासियों की जमीनों को अपनी कंपनियों के नाम करवाया है, उससे वे...

युवामंच

18 | अब एकल परीक्षा से...

मप्र के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार अब मिशन मोड में काम करेगी। गौरतलब है कि सरकार ने ढाई लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती का टारगेट रखा है। इसके लिए सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली चयन परीक्षा में मोहन सरकार बड़ा परिवर्तन करने...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

इस समय संसद और राज्यों की विधानसभाओं में मानसून सत्र चल रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि माननीय जनहित से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान का रास्ता निकालेंगे, लेकिन संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हंगामा बरपा हुआ है। यही हाल मप्र की विधानसभा सहित अन्य राज्यों की विधानसभा में देखने को मिल रहा है। हंगामे के कारण कामकाज अधर में लटके हुए हैं और जनता की फिकर किसी को नहीं है।

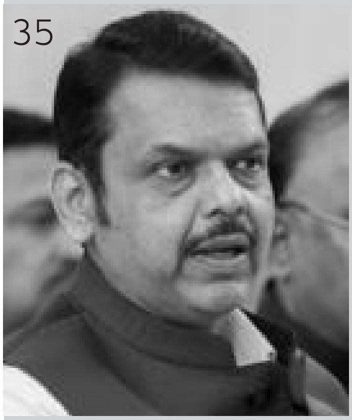
35

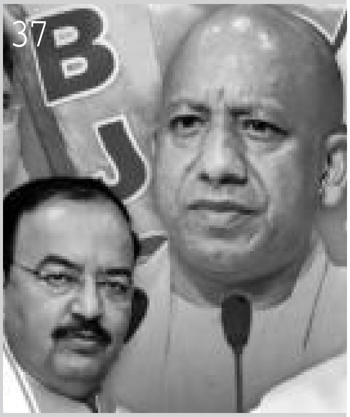
37

44

45

राजनीति

30-31 | रिटायरमेंट का सवाल

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि नेताओं को 75 की उम्र में रिटायर हो जाने और युवाओं के लिए जगह खाली करने के बारे में सोचना चाहिए। आप यह मत सोचने लग जाइए कि उन्होंने कोई अवांछित बात कह दी है। वैसे कोई प्रतिक्रिया देने में सावधानी बरतना लाजिमी है, क्योंकि...

राजस्थान

36 | गरीबों का राशन...

राजस्थान के 83 हजार सरकारी कर्मचारी-अधिकारी 5 साल में गरीबों का करोड़ों रुपए का गेहूं खा गए। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे अपात्रों से 82 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई है। योजना को आधार से लिंक करने के बाद जब पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने...

बिहार

38 | तय हो गया बिहार...

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुफ्त योजनाएं, विकास और कानून-व्यवस्था प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरे हैं। नीतीश कुमार मुफ्त बिजली और रोजगार के वादे कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं...

6-7	अंदर की बात
40	विदेश
41	महिला जगत
43	कहानी
44	खेल
45	फिल्म
46	व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-21, पृष्ठ-48
1 से 15 अगस्त, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना अनूप यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

मप्र में लव और ड्रग्स जिहाद

किसी ने क्या खूब कहा है...

कोई दाना कोई दीवाना मिला, शहर में हर शख्स बेगाना मिला
मैं उसे पहचान तो लेता मगर, जब मिला वो बन के अफ्साना मिला

कुछ इसी तरह की स्थिति इन दिनों मप्र में बन रही है। मप्र में हाल के दिनों में हिंदू युवतियों और महिलाओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के संगठित मामले सामने आ रहे हैं। न केवल राजधानी भोपाल, बल्कि छोटे शहरों में भी एक ही पैटर्न पर आधारित रेप के मामले उजागर हो रहे हैं। सभी मामलों में आरोपियों के मुस्लिम और पीड़िताओं के हिंदू होने के कारण इन घटनाओं को कथित तौर पर लव जिहाद गैंग का नाम दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश की सियासत गरमा गई है। प्रदेश में मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करने और अंतरंग पलों के वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले सामने आए हैं। वहीं जुलाई में ही राजधानी में लव और ड्रग्स जिहाद का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें ड्रग्स, अश्लील वीडियो और ब्लैकमेल का बड़ा खुलासा हुआ है। राजनीतिक संरक्षण में लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद का खेल किस तरह खेला जा रहा है, उसका खुलासा राजधानी में हुआ है। गत दिनों भोपाल में कॉलेज छात्राओं से जुड़े रेप और ब्लैकमेलिंग केस से चर्चा में आए शाहवर उर्फ मछली और उसके भतीजे यासीन को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके पास से तीन ग्राम एमडी ड्रग, एक देशी पिस्टल बरामद हुई है। यासीन के मोबाइल में युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो भी पाए गए हैं। यासीन की स्कॉर्पियो पर विधानसभा का पास और प्रेस लिखा स्टिकर चिपका मिला। इसका इस्तेमाल वह अपनी छवि को प्रभावशाली दिखाकर लोगों को डराने में करता था। पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ युवतियों को पहले नशे की लत लगाई, फिर उन्हें ही ड्रग्स सप्लाई के काम में लगाया दिया। युवतियों के माध्यम से ड्रग्स की डिलीवरी करवाई जाती थी, ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। वहीं इंदौर में एक राइफल शूटिंग एकेडमी में **छात्राओं से रेप और अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। आरोप एकेडमी के कोच मोहसिन खान पर है। उसने यहां निशानेबाजी सिखाने के नाम पर छात्राओं और युवतियों से छेड़छाड़ की** और उनके वीडियो भी बनाए। हिंदू संगठन का दावा है कि आरोपी के मोबाइल में 100 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले हैं। दरअसल, मप्र में लव और ड्रग्स जिहाद का एक सुनियोजित नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस के अनुसार, ये लोग स्कूल-कॉलेज, कोचिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से जालसाज युवतियों और सिंगल महिलाओं को निशाना बनाते हैं। ये लोग महंगी लाइफस्टाइल, लग्जरी गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दिखावा करते हैं। कई बार उनके गिरोह में सहयोगी महिलाएं भी शामिल होती हैं। शुरू में जालसाज शालीन और सहयोगी व्यवहार कर युवतियों का विश्वास जीत लेते हैं। फिर उन्हें पब, रेस्टोरेंट, होटल या ढाबों पर ले जाकर नशे की लत लगवाते हैं। नशे की हालत में उनका यौन शोषण किया जाता है। इन जगहों पर छुपे कैमरों से अश्लील फोटो और वीडियो बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए होता है। पीड़िताओं को गिरोह के अन्य सदस्यों से यौन संबंध बनाने और अपनी सहेलियों को लाने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ मामलों में जबरन शादी, धर्मांतरण, मानव तस्करी और देह व्यापार जैसे अपराधों में भी धकेला जाता है। मप्र में मेफेड्रोन यानि एमडी की तस्करी के मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बीते 1 साल में करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स की खेप इस क्षेत्र में पकड़ी जा चुकी है। ज्यादातर मामलों के तार राजस्थान से जुड़े हुए हैं। बीते वर्ष भोपाल में हुई बड़ी कार्रवाई में राजस्थान के शोएब लाला का नाम आया था, जो भोपाल में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद पूरे प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी आज भी जारी है।

- राजेन्द्र आगाल

सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो

बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा आज का नहीं है। ये दशकों से चला आ रहा है। इससे न सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी डगमगाती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से यहां रह रहे हैं, वे यहां के लोगों के लिए सुरक्षित हैं।

● **नीतू साहू,** ब्यावरा (म.प्र.)

नई नीति लाए सरकार

एनएफएचएस की रिपोर्ट के अनुसार मप्र में प्रजनन दर तेजी से कम हो रही है। अगर यही स्थिति रही तो मप्र में 2047 तक यूथ से ज्यादा बुजुर्ग दिखेंगे। यानी मप्र बुजुर्गों का प्रदेश हो जाएगा। ऐसे में प्रदेश सरकार को नई नीति लानी होगी, जिससे भविष्य की इस समस्या से कुछ हद तक निजात मिल सके।

● **सुभाष शिवहरे,** भोपाल (म.प्र.)

शिक्षा का स्तर सुधरे

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। 2023-24 के लिए तैयार की गई इस रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में मप्र सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार है। सरकार को शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।

● **हरीश कुमार,** इंदौर (म.प्र.)

सुविधा जुटाने की होड़ में खो रहा भविष्य

बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसमें हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान ही नहीं होता बल्कि हजारों-लाखों घर तबाह हो जाते हैं। आज सुविधा जुटाने की होड़ व पागलपन इस हद तक जा पहुंचा है कि हम जीवन के मूल्यों और आधारों से भी कहीं आगे आ चुके हैं। हम गलतियों को न तो सुधारने के पक्ष में हैं और न ही यह समझने के लिए तैयार हैं कि अत्यधिक सुविधाएं संकट का ही पर्याय होती हैं। भोगवादी जीवनशैली हमेशा पृथ्वी को नुकसान ही पहुंचाएगी, यह हम सबकी समझ में आ जाना चाहिए। मनुष्य ये भूल गया कि प्रकृति पर उसका नियंत्रण नहीं है। एक ओर बारिश का बढ़ता असंतुलन और दूसरी ओर धुंध व प्राण वायु की दुश्वारी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। शायद यह कि प्रकृति जब भी बिगड़ेगी तो सबको ले डूबेगी।

● **मनीष सिंह,** राजगढ़ (म.प्र.)

मजदूरों के साथ न्याय!

मनरेगा को कमजोर करने में सबसे बड़ा कारण लगातार बजट में कमी और समय पर आवंटन राज्यों तक न पहुंचना ही है। मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि केवल आर्थिक आवश्यकता का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के फैसले से जमीनी स्तर पर मांग के बावजूद मजदूरों को मनरेगा में काम के लिए बेहिसाब तरीकों से हतोत्साहित किया जाएगा।

● **प्रभु नारायण,** बैतूल (म.प्र.)

दबंगों के अत्याचार पर गौर करे सरकार

अंग्रेजों ने 100 साल हम पर राज किया, देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग जाति प्रथा के गुलाम बने हुए हैं। आए दिन छुआछूत की खबरें आती रहती हैं। बुंदेलखंड में आज भी दलितों को पानी के लिए संघर्ष के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गांव के दबंग दलितों को सरकारी कुआं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है। समय बदल गया है, लेकिन छुआछूत, गरीबों-दलितों पर दबंगों का अत्याचार जैसी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। सरकार को इस मामले में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जिससे लोग सम्मान से जी सकें।

● **अभिराज धानक,** टीकमगढ़ (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

एमवीए में बदलेगा सियासी गणित!

महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय के चुनाव होने हैं। इसको लेकर लगभग सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी हैं। चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों गठबंधनों में नया समीकरण बनता दिख रहा है। एक ओर जहां महायुति में भाजपा असमंजस में है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। दोनों भाइयों के साथ आने के बाद से ही इस बात पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या महाराष्ट्र का सियासी गणित बदलेगा या उसी तरह रहेगा जैसा पहले था। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़ा बयान दिया है। चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस का रुख यह है कि हमारा गठबंधन शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) के साथ है। चव्हाण ने राज ठाकरे का नाम लिए बगैर इशारा करते हुए कहा कि अगर गठबंधन के साथी ऐसे लोगों के साथ अपना गठबंधन करना चाहते हैं जो मूल रूप से कांग्रेस की विचारधारा और अम्बेडकर ने संविधान में जो लिखा है उसकी विचारधारा का विरोध करते हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले भी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ चुकी है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पार्टी मुंबई, पुणे और नागपुर के निकाय चुनावों को अलग लड़ने का फैसला करती है।

खत्म हो गया इंडिया अलायंस?

बीते लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी पार्टियों ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को पटखनी देने के लिए इंडिया अलायंस नाम से गठबंधन बनाया जिसमें कुछ हद तक विपक्ष को कामयाबी भी मिली। लेकिन चुनाव परिणामों के बाद कई सहयोगी पार्टियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। आलम यह है कि अब यह गठबंधन रसातल में नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इससे लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को बचाना मेरी और ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं है। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उमर ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन की मजबूती की पहली जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। हमें अफसोस है हम मिलते नहीं हैं। इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस खत्म हो गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस गठबंधन में सबसे बड़ा दल है। कुछ समय पहले गठबंधन के वजूद को लेकर अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछा गया था कि यह गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था? इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने बिहार चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले हरियाणा और दिल्ली चुनाव में भी इंडिया अलायंस में खटपट देखी गई थी।

भाजपा को मिलेगी पहली महिला अध्यक्ष?

देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल साल 2023 में ही खत्म हो गया था लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली चुनाव के चलते भाजपा का संगठन चुनाव टलता चला गया। बिना संगठन चुनाव के भाजपा अध्यक्ष का चुनाव भी संभव नहीं था इसलिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया था। अब वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और पार्टी के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में पार्टी अपने नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है और जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की कमान पहली बार महिला को सौंपी जा सकती है। जिसमें निर्मला सीतारमण, डी. पुरंदेश्वरी, वानती श्रीनिवासन और स्मृति ईरानी का नाम शामिल है। यहां तक कहा-सुना जा रहा है कि पार्टी के भीतर महिला नेतृत्व की दिशा में आम सहमति भी बन गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा को पहली महिला अध्यक्ष मिलेगी? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी अब महिला नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सशक्त संदेश देना चाहती है। इससे भाजपा के महिला सशक्तिकरण नारे को न केवल बल मिलेगा, बल्कि आगामी लोकसभा परिसीमन लागू होने के बाद 33 फीसदी महिला आरक्षण के मद्देनजर एक बड़ा रणनीतिक कदम भी होगा।

कांग्रेस से दूर होते थरूर

कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का नाम अक्सर कांग्रेस के विद्रोही नेता के तौर पर लिया जाता है। इस बीच उन्होंने ऐसा बयान दे डाला है जो सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर मंथन और बेचैनी की वजह बन गया है। थरूर ने साफ कहा है कि देश की राजनीति कांग्रेस की वामपंथी और मध्यमवर्गीय सोच से निकलकर अब एक अधिक मस्कुलर नेशनलिस्ट दिशा में जा चुकी है जहां करिश्माई और केंद्रीयकृत नेतृत्व की मांग है। थरूर के इस बयान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि थरूर का संकेत है कि वे खुद भी इस बदलाव को स्वीकारते हैं और उसकी ओर कदम बढ़ा चुके हैं। उन्होंने न तो भाजपा का नाम लिया और न ही प्रधानमंत्री मोदी का लेकिन जो बात छिपाई गई वह शब्दों के चुनाव से खुद-ब-खुद जाहिर हो रही है। थरूर का यह बयान उस समय आया है जब वह पहले ही इमरजेंसी को काला अध्याय बता चुके हैं और कांग्रेस आलाकमान इस पर चुप है।

करवट बदलेगी सियासत?

बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के षड्यंत्र वाले बयान से भाजपा में काफी हलचल मच गई थी। यह मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि फिर से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वसुंधरा राजे के स्वागत में लगाए गए नारों ने पार्टी के भीतर खलबली मचा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री प्रोफेसर सांवरलाल जाट की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जयपुर से अजमेर जा रही थीं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और नारे लगाए कि हमारी सीएम कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो, केसरिया में हरा-हरा, राजस्थान में वसुंधरा। इन नारों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह घटनाक्रम राजस्थान की सियासत में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? असल में गहलोत के बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई गई यह मांग सियासी माहौल को और गरमा रही है।

साहब का काम में मन नहीं

2010 बैच के एक आईएएस अधिकारी की कार्यप्रणाली इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, साहब को प्रदेश के एक सबसे कमाऊ विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है, जैसे साहब का मन विभागीय काम में तनिक भी नहीं लग रहा है। वैसे साहब जब विभाग में नए-नए आए थे, तो उन्होंने कायदे-कानून दिखाकर अपनी दबंगई दिखाई और जमकर कमाई भी की। साहब ने विभाग में नियम विरूद्ध तबादले सहित कई ऐसे काम कर डाले हैं, जिससे वे संदेह के घेरे में आ गए हैं। वर्तमान में साहब प्रशिक्षण पर गए हुए हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने ट्रेनिंग से लौटने के बाद एक महीने की छुट्टी पर जाने का आवेदन दे दिया है। जिसको लेकर उनके साथियों का कहना है कि उनका मन काम में नहीं लग रहा है। वहीं कुछ लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि साहब ने विभाग में अपने हिसाब से जमावट करके इतनी कमाई कर ली है कि अब वे चाहते हैं कि विभाग से उन्हें अलग कर दिया जाए। इसकी वजह यह है कि अगर अनियमितता का कोई मामला सामने आता है तो साहब उसमें घिर सकते हैं। वैसे साहब का मन विभाग में क्यों नहीं लग रहा है, यह तो वही बता सकते हैं, उधर, उनकी अनुपस्थिति में एडिशनल चार्ज इंदौर के एक महत्वपूर्ण विभाग के विभागाध्यक्ष को दिया है।

साहब हटे नहीं... हटाए गए

कुछ समय पहले तक अपने आपको दबंग नौकरशाह मानने वाले एक आईएएस अधिकारी गिड़गिड़ाने को मजबूर हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब को बड़ी उम्मीद के साथ महामहिम के दरबार में उच्च पद पर पदस्थ किया गया था। लेकिन वहां भी वे सबकी नापसंद बन गए। इसलिए उन्हें वहां से हटा दिया गया। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि साहब जिस सर्वोच्च जगह पर एसीएस के पद पर पदस्थ थे, वहां के सर्वोच्च व्यक्ति ने खुद सीएम और सीएस से उनकी शिकायत की थी। बताया जाता है कि शिकायत के बाद उनके खिलाफ डीई भी होने वाली थी, लेकिन उनका तबादला कर दिया गया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि महामहिम के सामने पहुंचकर साहब गिड़गिड़ाए भी थे कि उनकी गलती क्या है? सूत्र बताते हैं कि 1992 बैच के उक्त आईएएस अधिकारी शासन-प्रशासन के पैमाने पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। वे जबसे वहां पदस्थ हुए थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। उन्हें महीनेभर पहले ही बोल दिया गया था कि अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर तैयार रहें। जैसे ही मौका आया, सरकार ने उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर एक छोटे से विभाग में भेज दिया।

मंशा पर फिर गया पानी

प्रदेश में कई विभाग ऐसे हैं, जिनमें जाने के लिए अधिकारियों में होड़ मची रहती है। ऐसे ही एक कमाऊ विभाग में जाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। अगर किसी के पास राजनीतिक रसूख हो, तो वह तो इस मौके का फायदा उठाने से तनिक भी पीछे नहीं रहना चाहता है। इसी कड़ी में एक पुलिस अधिकारी ने कमाऊ विभाग की मलाई खाने के लिए जोड़तोड़ किया और अपनी ए+ नोटशीट भी लिखवा ली, लेकिन फिलहाल उनकी मंशा पर पानी फिर गया है। सूत्रों का कहना है कि जिस पुलिस अधिकारी की यहां बात हो रही है, वे मालवांचल के एक मंत्री के भाई हैं। भाई की चाहत पर मंत्रीजी ने उन्हें कमाऊ विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजने की पूरी जुगाड़ लगा ली। मंत्रीजी के जुगाड़ का असर यह हुआ कि उनके भाई को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए सरकार के मुखिया ने ए+ नोटशीट भी लिख दी गई। लेकिन जब मामला प्रशासनिक मुखिया के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे रोक दिया। बताया जाता है कि प्रशासनिक मुखिया अपने हाथ से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, जिससे सरकार की साख पर आंच आए। दरअसल, मंत्रीजी के भाई वर्तमान में एडिशनल एसपी हैं। वे जिस विभाग में जाने की जुगाड़ लगाए बैठे हैं, उस विभाग की काली करतूतों के कारण अभी हाल ही में सरकार की जमकर फजीहत हुई है। ऐसे में शायद ही उनकी दाल गल पाए।

हाथियों की मौत का ईनाम

अभी हाल ही में भारतीय वन सेवा के 1988 बैच के अधिकारी को नया वन बल प्रमुख बनाया गया है। लेकिन इनकी पदस्थापना के आदेश आते ही प्रशासनिक वीथिका में चर्चा होने लगी है कि क्या सरकार ने इन्हें 10 हाथियों की मौत का ईनाम दिया है। दरअसल, उक्त आईएफएस अधिकारी जब उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, तब वहां पिछले साल नवंबर महीने में 10 हाथियों की मौत हो गई थी। मामला जब तूल पकड़ा तो सरकार ने आनन-फानन में उन्हें वहां से हटा दिया। लेकिन 8 माह बाद सरकार ने उन्हें वन बल प्रमुख बना दिया है। सूत्रों का कहना है कि वैसे तो इस पद के लिए सबसे प्रबल और योग्य दावेदार दूसरे आईएफएस अधिकारी थे और उनका ही नाम चल रहा था। लेकिन 1988 बैच वाले साहब अन्य सभी दावेदारों पर भारी पड़े और बड़ा पद हथियाने में कामयाब हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो व्यक्ति एक टाइगर रिजर्व में सुरक्षा बहाल नहीं कर पाया, वह पूरे प्रदेश में कैसे काम कर पाएगा? इसको लेकर चर्चा और चिंताएं दोनों व्यक्त की जा रही हैं।

बड़ी जुगाड़, बन जाएगा काम

विंध्य क्षेत्र के एक जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ एक आईपीएस अधिकारी महाकौशल क्षेत्र के एक बड़े जिले की कप्तानी करने की जुगाड़ लगा रहे हैं। बताया जाता है कि साहब की बड़ी मंशा है कि उक्त जिले की कप्तानी करने का उन्हें मौका मिले। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए साहब ने बड़ी जुगाड़ लगाई है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि उनका काम बन जाएगा। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि साहब की धर्मपत्नी आईएएस अधिकारी हैं और वे भी उक्त जिले के पास के एक जिले में कलेक्टर हैं। बताया जाता है कि साहब ने अपनी धर्मपत्नी के माध्यम से अपनी मनोकामना पूरी करने की जुगाड़ लगाई है। सूत्रों का कहना है कि साहब की आईएएस धर्मपत्नी ने पति को महाकौशल के बड़े जिले की कप्तानी दिलाने के लिए अपनी ही बिरादरी के बड़े अधिकारी से गुहार लगाई है। कहा जा रहा है कि जब आईएएस लॉबी किसी काम के पीछे लग जाती है तो उसे पूरा कराकर ही मानती है। ऐसे में माना जा रहा है कि साहब की मनोकामना जल्द पूरी होगी...।

नए प्रदेशों की मांग तेज

देश में एक बार फिर से नए राज्यों को बनाने की मांग उठ रही है। इनमें दो प्रदेशों की मांग ऐसी है जो मप्र से संबंधित हैं। पहला भील प्रदेश और दूसरा चंबल प्रदेश। 18 जुलाई को राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में मप्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में आदिवासी इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम में सभी ने एक स्वर में नए भील प्रदेश की मांग की। इस भील प्रदेश में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ-साथ मप्र के 13 जिलों, यहां तक कि आर्थिक राजधानी इंदौर को भी शामिल करने की बात कही गई। क्षेत्रफल और जिलों की संख्या के हिसाब से तो मप्र, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है लेकिन आदिवासियों की संख्या के हिसाब से पहले नंबर पर है। ये पहली बार नहीं है, जब आदिवासियों ने अलग भील प्रदेश की मांग उठाई है। मानगढ़ में इसे लेकर कई सालों से ये आयोजन होता आ रहा है। क्या मप्र का आदिवासी समुदाय भी अलग भील प्रदेश चाहता है, क्या इस समुदाय से आने वाले प्रदेश के नेता भी ऐसा ही सोचते हैं, अगर भील प्रदेश बना तो उस प्रदेश की क्या तस्वीर हो सकती है?

भील प्रदेश की मांग का इतिहास 108 साल पुराना है। उस समय राजस्थान, गुजरात और मप्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रियासती शासकों और सामंतों का राज था। ये शासक अंग्रेजों के साथ मिलकर आदिवासियों का जमकर शोषण करते थे। आदिवासियों से बेगार लेना, उन पर भारी लगान लगाना, उनकी जमीनों पर कब्जा करना और उनके जल-जंगल-जमीन के अधिकारों का हनन करना आम बात थी। 17 नवंबर 1913, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर वार्षिक मेला और गोविंद गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए लाखों की संख्या में आदिवासी भगत एकत्रित हुए थे। अंग्रेज सरकार ने इस शांतिपूर्ण सभा को विद्रोह मान लिया। 16 नवंबर 1913 की शाम तक, अंग्रेज सिपाहियों ने मेवाड़ भील कोर, राजपूत रेजिमेंट, वेलेजली राइफल्स और जाट रेजिमेंट की सेना के साथ मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। कर्नल शटन के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने 17 नवंबर 1913 की सुबह लगभग 8:30 बजे से निहत्थे आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें और मशीन गन थीं। इस नरसंहार में महिलाओं और बच्चों सहित 1500 से अधिक भील आदिवासी शहीद हो गए। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919) से भी पहले हुई थी और उससे भी अधिक भीषण थी। इस घटना को आदिवासी जलियांवाला के रूप में भी जाना जाता है।

देश की आजादी के बाद से भील समुदाय अनुसूचित जनजाति के विशेषाधिकारों के साथ एक अलग राज्य की मांग करता रहा है। भील प्रदेश की मांग कर रहे 3 करोड़ आदिवासी मप्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के करीब 49 जिलों में निवास करते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी से बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत का कहना है कि आदिवासियों के विकास के लिए भील प्रदेश का बनना बहुत जरूरी हो गया है। इन राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों पर किसी ने दशकों से ध्यान नहीं दिया है। ये क्षेत्र सभी मामलों में सबसे पिछड़े हुए हैं। मौजूदा राज्यों की राजधानियां जैसे भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई आदिवासी इलाकों से काफी दूर हैं। जिससे इन क्षेत्रों पर कम ध्यान दिया जाता है और संसाधनों का बंटवारा भी ठीक से नहीं हो पाता। रोत कहते हैं कि आदिवासी विकास के लिए आवंटित पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वास्तविक प्रगति नहीं हुई इसलिए एक अलग भील प्रदेश, जिसकी अपनी राजधानी और शासन होगा, उसी से उन मुद्दों का समाधान निकल सकता है, जिनका सामना आदिवासी समुदाय दशकों से कर रहा है। जिनमें भूमि संबंधी समस्याओं का हल, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का सही से लागू होना, आरक्षण का उचित क्रियान्वयन, कुपोषण से निपटना और आदिवासियों के पलायन को रोकना शामिल है।

कम आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों (जैसे इंदौर) के संबंध में रोत स्पष्ट करते हैं कि उन्हें शामिल करने का निर्णय एक समिति द्वारा किया जाएगा। केवल उन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जहां 50-70 प्रतिशत आबादी आदिवासी है और वे खुद भील प्रदेश में शामिल होने को तैयार हैं। मप्र के इकलौते आदिवासी निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार का कहना है कि वे मानगढ़ धाम नहीं गए थे। वे इस आंदोलन से अपने आप को अलग रखते हैं। उनका कहना है कि मैं भील प्रदेश की मांग मप्र विधानसभा में उठाऊंगा। मानगढ़ में राजस्थान के आदिवासी नेता अपनी राजनीति चमकाते हैं। अभी मैं जनजागरण का काम कर रहा हूं। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखे हैं। वहीं भिंड जिले के अंतर्गत फूप में चंबल प्रदेश की मांग के लिए किसान नौजवान मंच परिवार ने जनजागरण महापंचायत का आयोजन किया। सर्व समाज के साथ दिमनी के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह तोमर भिड़ौसा ने चंबल को अलग प्रदेश का दर्जा दिलाने की मांग रखी।

21 जिलों को मिलाकर बनेगा चंबल प्रदेश

चंबल प्रदेश बनाने के लिए 7 जिले उप्र, 7 राजस्थान और 7 मप्र के जोड़े जाएंगे। 21 जिलों की 6 करोड़ की आबादी से मिलकर प्रदेश बनाने की मांग की जाएगी। पूर्व विधायक रविंद्र तोमर ने बताया कि आबादी के हिसाब से चंबल को अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। केंद्र में प्रस्ताव रखा जाएगा। इतना ही नहीं सिंध, चंबल, आसन सहित आदि नदियों की बेजान पड़ी भूमि पर इंडस्ट्रीज लगाई जाए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित बड़े शहरों में उद्योग लगाए जा रहे हैं। इसी तरह हमारे यहां भी चंबल में उद्योग विकसित किए जाएं। महापंचायत में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी रिटायर होकर पेंशन नहीं लेगा तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। चंबल प्रदेश में जिन जिलों को शामिल करने की मांग उठ रही है उनमें मप्र के गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और भिंड जिला, राजस्थान के धौलपुर, करौली, सवाई माधौपुर, कोटा, बारा और झालावाड़ जिला तथा उप्र के आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी और ललितपुर जिला आदि शामिल हैं।

● जितेंद्र तिवारी

स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 की अलग-अलग श्रेणियों में मप्र के शहरों का शानदार प्रदर्शन रहा। देशभर के लिए स्वच्छता का मॉडल बन चुका इंदौर स्वच्छ शहरों की सुपर लीग में अव्वल आकर स्वच्छता का सुपर स्टार बन गया। केंद्र सरकार ने पहली बार सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी बनाई है। इसमें वे शहर शामिल किए गए, जो दो साल से स्वच्छता में टॉप-3 में आ रहे थे। मप्र के सात अन्य शहरों को भी विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया।

मप्र का स्वच्छता सर्वे-2024 की अलग-अलग श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन रहा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटी कैटेगरी में इंदौर एक बार फिर नंबर वन बना है। वहीं, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की लीग में उज्जैन चौथे पायदान पर रहा। इसी तरह, 20 हजार से कम आबादी की कैटेगरी में बुधनी ने पांचवां स्थान हासिल किया। वहीं, सामान्य स्वच्छता रैंकिंग में अहमदाबाद पहले और भोपाल दूसरे स्थान पर रहा। जबलपुर नंबर 5 और ग्वालियर 14 नंबर पर रहा। 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में देवास ने देशभर में टॉप रैंकिंग पाई। जबकि 20 हजार से कम आबादी की श्रेणी में मप्र का ही शाहगंज तीसरे स्थान पर रहा।

स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 में इंदौर एक बार फिर देशभर में स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे आगे रहा। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में इंदौर को देशभर में पहला स्थान मिला है। यह अवॉर्ड 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दिया गया। मप्र के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवॉर्ड दिया। इंदौर को अवॉर्ड मिलते ही शहर में जश्न मनाया जाने लगा। आतिशबाजी और रंग-गुलाल उड़ाकर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने इस उपलब्धि को सेलिब्रेट किया। साल 2021 से 2023 के बीच जो शहर टॉप-3 में रहे, उन्हें सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है। सामान्य स्वच्छता रैंकिंग में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली कैटेगरी में अहमदाबाद नंबर वन रहा। दूसरे नंबर पर भोपाल और तीसरे नंबर पर लखनऊ रहा। भोपाल की 6 साल बाद टॉप-3 में वापसी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर मालती राय को इस कैटेगरी का अवॉर्ड दिया। दूसरे नंबर का पुरस्कार मिलने पर भोपाल में भी जश्न का माहौल है। नगर निगम सभापति किशन सूर्यवंशी ने स्वच्छता मित्रों को मिठाई खिलाई और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग में उज्जैन ने देशभर में चौथा स्थान हासिल किया। इस श्रेणी में नोएडा को पहला, चंडीगढ़ को दूसरा और मैसूर को तीसरा स्थान मिला।

स्वच्छता में मप्र की चमक

इंदौर जैसा मॉडल अब 10 शहरों में

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के कम से कम 10 शहरों को इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वर्तमान में 338 शहर ओडीएफ डबल प्लस और 24 शहर वॉटर प्लस प्रमाण-पत्र पा चुके हैं। इंदौर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, जबकि भोपाल को दूसरा स्थान मिला है। उज्जैन संभाग के 66 में से 56 शहरों ने अपनी रैंक सुधारी है, जिससे साफ है कि स्वच्छता अब स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता बन चुकी है।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में 50 हजार से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देवास को पहला स्थान मिला है। राष्ट्रपति ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर गीता अग्रवाल को ये पुरस्कार दिया। देवास को इस बार फाइव स्टार रेटिंग मिली है। साथ ही दूसरी बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है। 20 हजार से कम आबादी वाली श्रेणी की सुपर स्वच्छ लीग में बुधनी ने देशभर में पांचवां स्थान पाया है। इस कैटेगरी में महाराष्ट्र का पंचगनी पहले, पाटन दूसरे, बनहला तीसरे और विश्रामपुर चौथे स्थान पर रहे। मप्र का महू सबसे स्वच्छ छावनी बना। मप्र के महू को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार महानिदेशक जीएस राजेश्वर को प्रदान किया गया। राजधानी भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में देश का दूसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। भोपाल ने इस बार तीन स्थान की छलांग लगाई है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिया। पुरस्कार लेने के लिए भोपाल की महापौर मालती राय और निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण दिल्ली पहुंचे। भोपाल अहमदाबाद से केवल 12 अंक पीछे रहकर शीर्ष स्थान से चूक गया। घर-घर कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रसंस्करण, आवासीय और व्यावसायिक स्वच्छता, झीलों के रखरखाव और सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने के बावजूद, भोपाल नगर निगम कचरा स्थलों के सुधार और स्रोत पृथक्करण में पिछड़ गया।

भोपाल शहर में होने वाले कचरे का कलेक्शन और फिर उसका निपटारा करने का प्रबंध किया गया है। भोपाल में हर दिन 517 डीटीडीसी व्हीकल, 719 सीएनजी व्हीकल और 202 रोड स्वीपिंग व्हीकल तैनात हैं। जो पूरे दिन में शहरभर का गीला-सूखा कचरा समेटकर उसे कचरा निष्पादन केंद्र तक पहुंचाते है। कलेक्शन मैकेनिज्म के साथ समानांतर रूप से वेस्ट प्रोसेसिंग का इंतजाम किया गया है। इसके लिए भोपाल में हर दिन उत्सर्जित कचरे के प्रकारों और उसकी मात्रा का पहले आंकलन किया जाता है। 250 नए सीएनजी डोर-टू-डोर वाहन, 6 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग वाहन जैसे इंतजाम इसी साल से किए गए। जिससे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन 100 प्रतिशत हो सके। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में भोपाल को 7 स्टार रैंकिंग भी मिली है। जबकि भोपाल ने देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी होने के साथ ही वाटर प्लस सिटी का गौरव भी बरकरार रखा है। रीड्यूज, रियूज, रिसायकल थीम पर हुए स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में भोपाल नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में निर्धारित 10 हजार अंकों में से 9567 अंक और सर्टिफिकेशन के लिए निर्धारित 2500 अंकों में से पूरे अंक प्राप्त किए। इस प्रकार 12 हजार 500 अंकों में से भोपाल शहर ने 12 हजार 067 अंक अर्जित करते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

● सुनील सिंह

डायरी

6-7 महीने प्रभार पर उज्जैन संभाग

उज्जैन संभागायुक्त संजीव गुप्ता रिटायर हो गए हैं। अब उनकी जगह नए संभागायुक्त की नियुक्ति की जानी है। सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि ऐसे अधिकारी को संभागायुक्त बनाया जाए, जिसके नेतृत्व में सिंहस्थ कराया जा सके। सूत्रों का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह नंबर-1 पर हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 6-7 महीने के लिए उज्जैन संभागायुक्त का प्रभार किसी अन्य अधिकारी को दिया जा सकता है। इसके लिए या तो इंदौर के किसी अधिकारी को उज्जैन भेजा जा सकता है या फिर उज्जैन के ही किसी अधिकारी को प्रभार दिया जा सकता है। वहीं इन संभावनाओं को देखते हुए इंदौर का कलेक्टर बनने के लिए अफसरों के बीच जोड़-तोड़ शुरू हो गई है। इंदौर कलेक्टर के लिए सबसे ऊपर 2013 बैच के आईएएस अधिकारी प्रियंक मिश्रा का नाम है। इनके अलावा रोहित सिंह, अनुराग वर्मा, प्रतिभा पाल भी दावेदारी कर रही हैं। अब देखना यह है कि सरकार कब उज्जैन संभागायुक्त की नियुक्ति करती है। अगर आशीष सिंह उज्जैन संभागायुक्त बनते हैं तभी इंदौर कलेक्टर की नियुक्ति की बात आगे बढ़ेगी।

पंजीयन विभाग में नया खेल

पंजीयन विभाग में घूसखोरी और भ्रष्टाचार का मामला बराबर सामने आते रहता है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों ने घूस लेने का नया तरीका निकाल लिया है। सूत्रों का कहना है कि इसके तहत जितनी रकम की घूस देनी है, उतने का चेक ले लिया जाता है और जमीन दिखाकर उसकी रजिस्ट्री करा ली जाती है। बाद में उस चेक को फाड़कर फेंक दिया जाता है।

कोई खामी बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पूरा फोकस सुशासन पर है। उनकी लगातार कोशिश है कि शासन-प्रशासन में साफ-सुथरी छवि के लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले। मुख्यमंत्री की इस नीति का असर मुख्यमंत्री आवास पर भी देखने को मिल रहा है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास पर पदस्थ कोई भी अधिकारी थोड़ी सी भी हीला-हवाली या आनाकानी करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि सीएम हाउस में लगातार अफसरों को बदला जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी संख्या में प्रदेशभर से शिकायती पत्र आते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री की कोशिश है कि वहां ऐसे अफसर पदस्थ रहें, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

16 पदों के लिए डीपीसी

राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए डीपीसी की फाइल दिल्ली चली गई है। 2023 और 2024 के 8-8 यानी 16 पदों के लिए डीपीसी होगी। दरअसल, 2023 में जिन आठ पदों के लिए डीपीसी होनी थी, वह यूपीएससी को देर से प्रस्ताव भेजने के कारण नहीं हो पाई थी। अब दो वर्षों की डीपीसी एक ही साथ होगी। 16 पदों के लिए होने वाली डीपीसी में 15 अधिकारी आईएएस बन जाएंगे। इसकी वजह यह है कि 1995 बैच के पंकज शर्मा की उम्र अधिक हो गई है। वहीं कमल चंद्र नागर का लिफाफा भी बंद है। ऐसे में 1998 बैच के एमपी नामदेव, 1999 बैच के जयेंद्र कुमार और 2000 बैच के कैलाश बुंदेला और मनोज मालवीय में से अगर कोई आगे-पीछे होता है तो रोहन सक्सेना, कविता बाटला, सपना अनुराग जैन, आशीष पाठक में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है।

मनीष सिंह की वापसी

1997 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष सिंह की प्रदेश वापसी हो गई है। मनीष सिंह स्टडी लीव पर चल रहे थे। ऐसे में उनकी प्रदेश वापसी के बाद उनकी नई पदस्थापना होनी है।

दाग धोने की तैयारी

मप्र में जिस तरह लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद के मामले उजागर हो रहे हैं और आरोपियों के संबंध सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से जुड़ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रदेश में बड़ी राजनीतिक कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। आरएसएस इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। संगठन इस बात की तस्दीक कर रहा है कि क्या आरोपियों की सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के साथ कोई आर्थिक सांठगांठ है, या कुछ और। सूत्रों का कहना है कि भगवा पार्टी पर जिस तरह लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद के आरोपियों ने दाग लगाए हैं, उसे धोने के लिए कठोर कदम उठाया जाएगा। संघ इसके लिए सबूत जुटा रहा है।

वरुण कपूर बने जेल महानिदेशक

राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें 1991 बैच के वरुण कपूर को जेल महानिदेशक पदस्थ किया है। जीपी सिंह 31 जुलाई को जेल महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। साथ ही मो. शाहिद अवसार (1996) को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती पदस्थ किया है। साथ ही पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भौरी का प्रभार भी सौंपा गया है। तबादला आदेश में 2010 बैच के यूसुफ कुरैशी को उप पुलिस महानिरीक्षक सायबर से हटाकर उप पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ पदस्थ किया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जेल महानिदेशक जीपी सिंह के सेवानिवृत्त होने पर विशेष पुलिस महानिदेशक का एक पद रिक्त हो गया है। इस पद पर 1993 बैच के आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल सुरक्षा रवि गुप्ता को विशेष पुलिस महानिदेशक पदोन्नत किया है।

8 साल बाद भी स्विमिंग पुल अधर में

मप्र में सरकार विकास के लिए फंड की कमी नहीं कर रही है, लेकिन विकास कार्यों की हकीकत क्या है, इसका एक मामला बुरहानपुर में सामने आया है। बुरहानपुर में रेणुका उद्यान के समीप वर्ष 2017 में नगर निगम ने अटल बिहारी राज्यस्तरीय तरणताल का निर्माण किया था। तत्कालीन महापौर अनिल भोसले ने करीब 1 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से यह स्विमिंग पूल बनवाकर तैयार कराया था, लेकिन अब तक यह स्विमिंग पूल जनता के लिए शुरू नहीं हो पाया है। अब ये स्विमिंग पूल जर्जर हालत में है। इसे देखकर लगता है कि ये बड़ा गड्ढा है या फिर खंडहर। इसको लेकर नेपानगर की विधायक मंजू राजेंद्र दादू ने विधानसभा में सवाल भी लगाया है।

रेणुका उद्यान की जमीन पर बना अटल बिहारी स्विमिंग पूल खंडहर में तब्दील हो गया है। हालत ये है कि पहली नजर देखकर लगता है कि ये कोई खंडहर है। चारों ओर झाड़ियां उग आई हैं। इसका लोकार्पण तत्कालीन सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्व. नंदकुमार सिंह चौहान ने किया था। जिलेवासियों को उम्मीद थी कि जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इतनी मोटी रकम खर्च होने के बाद भी ये किसी काम का नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बनाए गए तरणताल में लाखों रुपए की सामग्री धूल खा रही है। आलम यह है कि लोहे के गेट जंग खाने लगे हैं। ताले बंद हैं और पूल में पानी पूरी तरह से गंदा और मटमैला हो चुका है। इसके अलावा वहां बड़े-बड़े पौधे भी उग गए हैं और टाइल्स उखड़ चुकी हैं। नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत उच्च न्यायालय में भी हुई थी, जिसमें नगर निगम को नोटिस भी मिल चुके हैं। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर नगर निगम ने उद्यान की जमीन पर स्विमिंग पूल का निर्माण कर दिया, और जहां स्विमिंग पूल बना है, वहां पानी ही नहीं है।

90 डिग्री वाले पुल मामले में दोषी के साथ अन्य भी हटे

भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री आरओबी ने देशभर में प्रदेश की किरकिरी कराई है। मामला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस ब्रिज को दोबारा सुधरने के बाद ही शुभारंभ की बात कही है। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के लिए जो लोग मुख्यतः दोषी हैं, उनके अलावा अन्य को भी लपेटे में ले लिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद इस ब्रिज की डिजाइन पास करने वाले और मॉनीटरिंग करने वाले 2 मुख्य अभियंता समेत 8 इंजीनियरों पर कार्रवाई हो चुकी है। उधर, सूत्रों का कहना है कि 90 डिग्री वाले आरओबी की भेंट अब लोक निर्माण विभाग के अफसर भी चढ़ेंगे। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिरकार 90 डिग्री वाले पुल का असली दोषी कौन है। 18 करोड़ रुपए की लागत से करीब 8 साल के लंबे अर्से के इंतेजार के बाद बनकर तैयार हुए इस ब्रिज की टॉप हाईट पर 90 डिग्री का खतरनाक टर्न दे दिया है, जिसने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। अब देखना यह है कि असली दोषी पर नकेल सरकार कसती है या नहीं।

अपने ही जाल में फंस गए अध्यक्ष

स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (सिया) के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान ने अफसरों को फंसाने के लिए जो जाल बुना था, वे खुद उसमें फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने इस मामले को उछाला है, उससे सरकार और संगठन भी उनसे नाराज हो गया है। बताया जाता है कि इसके लिए उन्हें फटकार भी लगाई गई है। दरअसल, सिया में पर्यावरण विभाग द्वारा दी गईं 237 पर्यावरणीय अनुमतियों का विवाद इस कदर गहरा गया है कि पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी को हटाने और उमा माहेश्वरी से एप्को संचालक का दायित्व छिनने के बाद से अब सवाल उठ रहा है कि अफसरों की बलि तो चढ़ गई, लेकिन इस पूरे मामले का दोषी कौन है। उधर, सिया चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान ने चुप्पी साध ली है। पर्यावरण अनुमतियों को लेकर दोनों अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारों से पत्र लिखने वाले सिया चेयरमैन मुख्य सचिव से मुलाकात करने के बाद से ही इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उधर, अनुमतियों से जुड़े मामले सर्वोच्च न्यायालय के अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और राज्य सरकार के पास लंबित हैं।

दरअसल, सिया के पास पर्यावरणीय अनुमति के लिए आवेदन पहुंचते हैं। प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी और एप्को डायरेक्टर उमा माहेश्वरी ने पर्यावरणीय अनुमति के लिए आए 700 आवेदनों में 450 को अनुमति देने की प्रक्रिया में शामिल किया। इनमें से 237 आवेदनों को पर्यावरणीय मंजूरियां गैर कानूनी तरीके से पिक एंड चूज पैटर्न पर जारी कर दी थीं। जिनमें करीब 200 अनुमतियां खदानों से संबंधित थीं। खास बात यह है कि पर्यावरण विभाग ने सिंहस्थ से जुड़े कार्यों की एक भी पर्यावरण अनुमति जारी नहीं की। सिया के चेयरमैन द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार को भेजी शिकायतों के अनुसार पर्यावरण अनुमति (ईसी) जारी करने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार और सिया के पास है। इनके अलावा कोई एनवायरनमेंट क्लीयरेंस जारी नहीं कर सकती। सिया चेयरमैन ने मुख्य सचिव को जो शिकायतें भेजी हैं, उनके अनुसार यदि नियम विरुद्ध दी गई पर्यावरण अनुमतियों के मामले में जांच आगे बढ़ी तो फिर अनुमतियां निरस्त करनी पड़ सकती हैं। गौरतलब है कि चौहान पर आरोप लगता रहा है कि वे अपना फायदा देखकर अनुमतियां देते रहे हैं। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि सरकार उनके कार्यकाल की जांच करा सकती है। अब देखना यह है कि इस मामले में सरकार का अगला कदम क्या होता है।

● राजेन्द्र आगाल

अधर में लटकी पुलिसकर्मियों की सीआर

मप्र में सुशासन को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली तैयार करने का निर्देश दिया है। इसमें पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं। विडंबना यह है कि निर्देश की समय सीमा समाप्त हुए 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन जिला इकाइयों में 15 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली अभी भी अधूरी है। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) की प्रशासन शाखा ने पिछले महीने सभी पुलिस इकाइयों को अपने कर्मचारियों की 2023-24 की वार्षिक सीआर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। इसके लिए 7 दिन की समय सीमा तय की गई थी। जिला पुलिस बल और अन्य इकाइयों द्वारा कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय सीआर की जानकारी जुटाने पर सच्चाई सामने आई, जिससे पुलिस बल के आला अधिकारी भी हैरान रह गए।

गौरतलब है कि पुलिसकर्मियों की सीआर (कंडक्ट रोल या वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पुलिसकर्मी के प्रदर्शन, आचरण और सेवाकालीन गतिविधियों का रिकॉर्ड रखता है। सीआर को तैयार करने की प्रक्रिया में, पुलिसकर्मी के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक मसौदा तैयार किया जाता है, जिसे फिर उच्च अधिकारियों द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया जाता है। मप्र में लगभग 15,000 पुलिसकर्मियों की पिछले वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) तय समय सीमा के 7 महीने बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। जिला इकाइयों में 15 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय सीआर अभी भी अधूरी है। इनमें से अधिकांश आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मी हैं। इस देरी का सीधा असर इन पुलिसकर्मियों की पदोन्नति पर पड़ सकता है।

राज्य सरकार सभी विभागों को वार्षिक गोपनीय सीआर के लिए एक रोस्टर जारी करती है। इस निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सीआर चार अलग-अलग चरणों में लिखी जाती है। पिछले वर्ष इसके लिए 31 दिसंबर की अंतिम तिथि निर्धारित थी। सामान्यत: आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक और निरीक्षक की वार्षिक गोपनीय सीआर उनकी तैनाती वाले जिलों में ही रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे पीएचक्यू भेजा जाता है। इस साल जब शासन ने विभागों में जारी कार्यवाहक प्रथा को बंद कर पदोन्नति देने की घोषणा की, तो पीएचक्यू ने सभी कर्मचारियों की सीआर भेजने को कहा। इसके बाद पता चला कि कई कर्मचारियों की सीआर अभी तक अधूरी है।

जनता की राय के आधार पर तय होगी पुलिस की सीआर

सुशासन दिवस के मौके पर पुलिस आयुक्त प्रणाली के तहत नगरीय पुलिस ने आम लोगों के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है। पहली योजना के तहत प्रत्येक थाने में एक रजिस्टर रखा गया है। थाने में किसी भी काम से पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम पता, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। संबंधित व्यक्ति से पुलिस द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार के बारे में पूछा जाएगा। उसके द्वारा दिए गए उत्तर रजिस्टर में अंकित कर रजिस्टर को कैसी है आपकी पुलिस प्रकोष्ठ में भेज दिया जाएगा। रजिस्टर में जनता जनार्दन द्वारा पुलिस सेवा की मॉनीटरिंग (गोपनीय चरित्रावली) के आधार पर सिपाही से लेकर थाना प्रभारी तक की ग्रेडिंग की जाएगी। थाने में रखे गए रजिस्टर में वहां पहुंचे व्यक्ति से पुलिस के उसके प्रति व्यवहार संबंध प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था में और बेहतरी लाने के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जनता-जनार्दन द्वारा दिए गए उत्तरों से न सिर्फ प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रेरणा मिलेगी, अपितु इस आधार पर थाने पर पदस्थ थाना प्रभारी सहित विभिन्न कर्मचारियों के द्वारा दी गई सेवाओं और व्यवहार का मूल्यांकन कर ग्रेडिंग की जाएगी।

इसका सबसे बड़ा कारण उनकी सीआर लिखने वाले अधिकारी का स्थानांतरण या सेवानिवृत्त हो जाना है। इसके अलावा, जिलों में तैनात आला अधिकारियों ने भी इस संबंध में अधिक रूचि नहीं दिखाई, जिसके कारण हजारों की संख्या में सीआर अभी भी लंबित हैं।

स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार का कहना है कि पिछले माह के अंत में सभी जिलों को निर्देश जारी कर एक सप्ताह में सीआर भेजने को कहा था। अधिकांश जिलों से सीआर नहीं मिलीं है। इनमें कुछ बाधाएं हैं। सभी इकाइयों को इसे ठीक कर जल्द सीआर भेजने को कहा गया है। उधर, पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद अब जिला इकाइयों में कर्मचारियों की सीआर को पूरा करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। नियमानुसार सीआर के लिए आवेदक स्वयं अपना प्रपत्र भरता है। इसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी इस बार पहली टिप्पणी दर्ज करता है। इस सीआर पर दूसरी टिप्पणी समीक्षक अधिकारी की होती है, जो प्रतिवेदक का वरिष्ठ होता है। इसके बाद चौथे चरण में सीआर स्वीकारकर्ता अधिकारी के पास जाती है। सीआर का एक अनिवार्य नियम है कि इस पर प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी वही होने चाहिए, जिनके अधीन कर्मचारी या अधिकारी ने काम किया हो। अधिकांश मामलों में प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारियों का अन्य जिलों में स्थानांतरण हो गया है, जबकि कुछ सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब जिला पुलिस की इकाइयों में पुलिस कर्मचारियों की आधी-अधूरी रखी वार्षिक गोपनीय सीआर उन अधिकारियों के पास भेजी जा रही है, जो अन्य जिलों में पदस्थ हो गए हैं। इसके अलावा, रिटायरमेंट के एक महीने तक अधिकारी सीआर पर टिप्पणी दे सकते हैं, इसलिए कुछ सीआर को ऐसे अफसरों के पास भी भेजा गया है जो एक माह पहले ही रिटायर हुए हों।

● **धर्मेंद्र कथूरिया**

निगम-मंडलों में जल्द होंगी नियुक्तियां

मप्र में अब निगम-मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच संभावित नामों को लेकर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इन नामों की सूची तैयार कर अनुमोदन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। अनुमति मिलते ही नियुक्तियों के आदेश जारी किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नामों को अंतिम रूप दिया है। इसमें पूर्व मंत्री, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद तथा विभिन्न जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रभावशाली चेहरों को शामिल किया गया है। फिलहाल राज्य में निगम-मंडल, बोर्ड और आयोगों के लगभग तीन दर्जन से अधिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए यह कवायद की जा रही है।

पिछले विधानसभा चुनाव में हारने वाले भाजपा के पूर्व मंत्रियों का राजनीतिक पुनर्वास कर उन्हें मुख्यधारा में लाने की तैयारी सरकार और संगठन ने कर ली है। इन नेताओं को जल्द ही निगम-मंडल आयोगों में पद देकर कैबिनेट मंत्री के दर्जे से नवाजा जाएगा। संगठन के आला नेताओं की इस मसले पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो चुकी है। जल्द ही पार्टी हाईकमान के सामने इस सूची को रखकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं पिछले डेढ़ साल से खाली पड़े अन्य निगम मंडल, आयोगों और प्राधिकरणों में भी जल्द नियुक्तियां किए जाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार में अभी निगम-मंडल और आयोगों के 45 से अधिक पद खाली पड़े हैं।

डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद एक आदेश जारी कर निगम-मंडल के पदाधिकारियों की उनकी पद से छुट्टी कर दी थी। लोकसभा चुनाव के बाद से इन निगम मंडलों में नियुक्ति की अटकलें चलती रही है पर संगठनात्मक कार्यक्रमों के चलते ये नियुक्तियां टलती रही हैं। संगठन सूत्रों की मानें तो जिलाध्यक्षों के निर्वाचन के बाद प्रदेश के आला नेताओं ने जिले के आला नेताओं से चर्चा कर निगम-मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्ति के लिए करीब चार दर्जन से अधिक नेताओं के नामों की सूची तैयार की थी पर इसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ पाया। यह सूची तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के कार्यकाल में तैयार की गई थी। हाल ही में इसी सूची पर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने मंथन किया है। इस सूची को लेकर एक और बैठक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश के साथ होनी है। इसके बाद इसे पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा। इसके बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से सभी वर्गों और क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जिससे आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सके। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले 45 निगम-मंडलों और बोर्डों में की गई पूर्ववर्ती नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। तब से अब तक इन संस्थाओं में कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है।

● **नवीन रघुवंशी**

इन पूर्व मंत्रियों की हो सकती है ताजपोशी

जिन पूर्व मंत्रियों का राजनीतिक पुनर्वास होने की संभावना जताई जा रही है उनमें नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, रामनिवास रावत, उमाशंकर गुप्ता का नाम शामिल है। नरोत्तम मिश्रा भाजपा की लगभग हर सरकार में असरदार मंत्री रहे। वे पिछला विधानसभा चुनाव दतिया से हारे थे। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से उनके बेहद करीबी रिश्ते हैं। भाजपा की न्यू जॉइनिंग टोली के प्रमुख सहित कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं समेत अन्य कार्यकर्ताओं को भाजपा में लाने का उन्हें श्रेय भी है। वहीं अरविंद भदौरिया शिवराज की पिछली सरकार में सहकारिता मंत्री रहे हैं। वे पिछला विधानसभा चुनाव अटेर से कांग्रेस के हेमंत कटारे से हारे थे। उन्होंने विद्यार्थी परिषद से भाजपा की सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। संघ से भी उनके करीबी रिश्ते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण निगम-मंडल में पद मिल सकता है। वहीं रामनिवास रावत कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने भाजपा का दामन थामा था, फिर भाजपा सरकार में वन जैसे महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री भी रहे, पर उपचुनाव में मिली पराजय के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। भाजपा अब उन्हें निगम-मंडल में पद देकर उनका सम्मान बरकरार रखने की तैयारी में है। वहीं, उमाशंकर गुप्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृहमंत्री हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के पीसी शर्मा से भोपाल के दक्षिण-पश्चिम विधानसभा से हारे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब निगम-मंडल में पद देकर वरिष्ठता का सम्मान करने की तैयारी है। इन पूर्व मंत्रियों के अलावा ऐसे नेताओं के नाम सूची में प्राथमिकता से रखे गए हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं और चुनाव में किन्हीं कारणों से पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। इसके अलावा वर्तमान में संगठन में प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के नाम भी सूची में हैं। इसके अलावा पूर्व संभागीय संगठन मंत्रियों को भी निगम-मंडलों में मौका दिया जाएगा। ये शिवराज सरकार में भी निगम-मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसके अलावा प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में जनभागीदारी समिति में भी स्थानीय नेताओं को एडजस्ट करने की तैयारी चल रही है। जिला संगठन से विधायकों से चर्चा के बाद इन समितियों के अध्यक्षों के नाम ले लिए गए हैं। गौरतलब है कि अब तक विधानसभा क्षेत्र स्थित कॉलेजों में विधायकों की पसंद के ही लोग जनभागीदारी समिति अध्यक्ष बनते आए हैं।

अपने ही जाल में फंसे पाठक

मप्र के सबसे धनाढ्य विधायक संजय पाठक इन दिनों जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। दरअसल, संजय पाठक ने नियम-कायदों को ताक पर रखकर सहारा समूह के साथ ही आदिवासियों की जमीनों को अपनी कंपनियों के नाम करवाया है, उससे वे अपने ही जाल में फंस गए हैं। पाठक के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि खनन कारोबार में लगे संजय पाठक का नाम लगातार विवादों में पड़ता रहा है, इससे भाजपा सरकार और संगठन दोनों की साख भी धूमिल हो रही है। इसलिए इनकी परेशानी और बढ़ने की संभावना है।

विधायक संजय पाठक ने अपना खजाना भरने के लिए जो जाल बुना था, अब वे खुद उसी में फंसते जा रहे हैं। ताजा मामला सहारा समूह की जमीनों का है।

सहारा समूह की 310 एकड़ बेशकीमती जमीनों की खरीद-फरोख्त में 72.82 करोड़ रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि 310 एकड़ जमीन का बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ था। उसे पहले 90 करोड़ रुपए में बेचा। इसमें भी 72.82 करोड़ का गबन कर लिया गया। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने एफआइआर दर्ज की है। जनवरी से अब तक 6 माह में जमीनों के खरीदार और विक्रेता पक्ष से सवाल-जवाब करने के बाद ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। बता दें, ये जमीनें विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार की शेयर होल्डिंग कंपनियों के जरिए खरीदी गई है। बताते हैं, इस एफआईआर के बाद विधायक संजय पाठक की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।

दरअसल, यह रकम निवेशकों को लौटाई जानी थी, लेकिन उसे आपराधिक साजिश के तहत हड़प लिया गया। एफआईआर में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के बेटे सीमांतो रॉय, जेबी रॉय, ओपी श्रीवास्तव और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने संजय पाठक को भले ही आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन इस घोटाले की फांस में वे पूरी तरह फंसे हुए हैं। क्योंकि नियमत: सहारा समूह की जमीनों का पैसा सेबी में जमा होना था, क्योंकि सहारा समूह में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को उक्त राशि दी जानी थी। लेकिन सबकुछ जानते हुए भी संजय पाठक ने जमीनों का सौदा किया और रकम सेबी में जमा नहीं कराई।

सेबी में जमा करनी थी राशि

संजय पाठक की कंपनियों के अधिवक्ता सिद्धार्थ शुक्ला ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि मेरे मुवक्किल सायनेप रीयल एस्टेट प्रा.लि. और नाइसा देवबिल्ड प्रा.लि. ने सहारा समूह से संबंधित कंपनियों की कटनी, जबलपुर एवं भोपाल में स्थित जमीनों का क्रय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पूर्ण अनुपालन व विधिवत और कानूनी रूप से किया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार विक्रेता अर्थात् सहारा समूह की यह जिम्मेदारी थी कि वह संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि सेबी-सहारा खाते में जमा कराएं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त भूमि-जमीनें कलेक्टर गाइडलाइन दरों पर ही बैंकिंग चैनल-चेक से भुगतान करके व टीडीएस काटकर ही क्रय की गई थी जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पूर्ण अनुरूप है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मेरे मुवक्किल किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी व गैर कानूनी कार्य में किसी भी प्रकार संलिप्त नहीं हैं। अगर किसी प्रकार की जांच इन सहारा ग्रुप से संबंधित कंपनियों के जमीनों के क्रय संबंधित कोई भी सरकारी एजेंसियां करती हैं या करना चाहती हैं तो मेरे मुवक्किल अपना पूरा सहयोग जांच में सबूत समेत प्रदान करेंगे।

दरअसल, सेबी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2012 और फिर 4 जून 2014 को आदेश जारी किए थे कि सहारा समूह अपनी अचल संपत्तियां बेचकर उनकी पूरी राशि सेबी के सहारा रिफंड खाते में जमा करे। ताकि यह निवेशकों को लौटाई जा सके। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि संपत्तियां सर्किल दर से कम कीमत पर नहीं बेची जाएं और खरीदार सहारा से जुड़ा न हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 2014 में सहारा ने भोपाल के मक्सी गांव में 110 एकड़ जमीन की कीमत सुप्रीम कोर्ट में 125 करोड़ रुपए बताई थी। बाद में इसे 47.73 करोड़ में बेच दिया गया। यह राशि सेबी के सहारा रिफंड खाते में जमा करने के बजाय हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खाते में डाली गई। सागर में 99.76 एकड़ जमीन मात्र 14.79 करोड़ में बेची गई, जिसकी राशि भी सहायक कंपनियों के खातों में ट्रांसफर हुई। कटनी, जबलपुर व ग्वालियर में भी संपत्तियों की बिक्री से मिली रकम सेबी को देने के बजाय उसमें 10.29 करोड़ की अवैध कटौती की गई। जिन कंपनियों के नाम पर भोपाल, जबलपुर, कटनी में जमीन खरीदी गई, वह विजयराघवगढ़ से विधायक संजय पाठक की मां, बेटे और परिजनों से जुड़ी हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि जमीन बेचने के लिए जिन अधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्तियां की गई थीं, वे फर्जी थीं। नियुक्त किए गए लोग दरअसल सहारा के ही कर्मचारी थे, और उनकी नियुक्ति किसी बोर्ड बैठक में नहीं हुई थी। जमीन खरीदी की सप्लीमेंट्री डीड के मुताबिक, खरीदारों को यह स्पष्ट रूप से पता था कि पैसा सहारा-सेबी के जॉइंट अकाउंट में भेजा जाना है। इसके बावजूद खरीदारों ने सारा पैसा सीधे सहारा समूह की शैल कंपनियों को दे दिया।

आदिवासियों के नाम पर खरीदी जमीन

यही नहीं संजय पाठक द्वारा मप्र के कटनी जिले के अपने चार आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर डिंडौरी जिले में गरीब बैगा आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी कर वर्ष 2009 से अभी तक लगभग 795 एकड़ जमीनें खरीदी कर इन जमीनों पर बॉक्साइड खदान स्वीकृत कराकर खनन करने की तैयारी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि भाजपा विधायक ने साजिश कर डिंडौरी के बैगा आदिवासियों की एक हजार एकड़ जमीन कटनी जिले के आदिवासियों के नाम पर खरीद ली।

रघुराज के पास 400 एकड़

रघुराज सिंह गौड़, पिता श्यामलाल गौड़, निवासी- ग्राम सुतरी तहसील बरही जिला कटनी के नाम पर डिंडौरी जिले की बजाग तहसील के ग्राम पिपरिया माल एवं ग्राम बघरेलीसानी में कुल 410 एकड़ जमीनें 2015 से अब तक विधायक संजय पाठक द्वारा खरीदी गई हैं। रघुराज सिंह गौड़ के नाम पर डिंडौरी जिले की बजाग तहसील के ग्राम पिपरिया माल में 365.88 एकड़ एवं ग्राम बघरेलीसानी में 44.12 एकड़ कुल 410 एकड़ जमीन, जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के ग्राम सरौली में 4.78 एकड़, कटनी जिले की बरही तहसील के ग्राम बरमानी में 9.60 एकड़ एवं ग्राम बिरुहली में 8.25 एकड़ सभी जिलों की कुल मिलाकर लगभग 432.65 एकड़ जमीन विधायक संजय पाठक द्वारा खरीदी गई हैं।

नत्थू के पास 370 एकड़

नत्थू कोल, पिता राममिलन कोल निवासी- मकान नंबर 22, वार्ड नंबर 11, ग्राम गोइंद्रा, तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी के नाम पर भी डिंडौरी जिले की बजाग तहसील के ग्राम पिपरिया माल, ग्राम सरईटोला एवं ग्राम हर्रा टोला में कुल 73.73 हेक्टेयर अर्थात् 184.32 एकड़ जमीनें विधायक संजय पाठक द्वारा खरीदी गई हैं। नत्थू कोल के नाम पर डिंडौरी जिले की बजाग तहसील के ग्राम पिपरिया माल, ग्राम सरई टोला एवं ग्राम हर्राटोला में 184.32 एकड़ जमीन, उमरिया जिले की मानपुर तहसील के ग्राम ताला में 44.22 एकड़, ग्राम मरदरी परासी में 9.44 एकड़ एवं ग्राम गोहड़ी परासी में 7.28 एकड़, जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के ग्राम कूम्ही में 25.30 एकड़, ग्राम प्रतापपुर में 0.81 एकड़, जबलपुर जिले की जबलपुर तहसील के ग्राम मोठार में 90.50 एकड़, कटनी जिले की बरही तहसील के ग्राम जगुवा में 5.60 एकड़, सिवनी जिले की कुरई तहसील के ग्राम अवरगनी रै. में 2.20 एकड़ सभी जिलों की कुल मिलाकर लगभग 369.70 एकड़ जमीन विधायक संजय पाठक द्वारा खरीदी गई हैं।

राकेश के पास 133 एकड़

राकेश सिंह गौड़, पिता मोलई, निवासी-ग्राम बरमानी तहसील बरही जिला कटनी के नाम पर डिंडौरी जिले की बजाग तहसील के ग्राम पिपरिया माल एवं ग्राम बघरेली सानी में लगभग 35.22 हेक्टेयर अर्थात् 88.04 एकड़ जमीनें विधायक संजय पाठक द्वारा खरीदी हैं। राकेश सिंह गौड़ के नाम पर डिंडौरी जिले की बजाग तहसील के ग्राम पिपरिया माल, में 83.52 एकड़ एवं बघरेलीसानी में 4.52 एकड़ कुल 88.04 एकड़ जमीन, उमरिया जिले की मानपुर तहसील के ग्राम ताला में 1.96 एकड़, ग्राम चिल्हारी में 4.64 एकड़, कटनी जिले की बरही तहसील के ग्राम जगुवा में 0.79 एकड़ एवं ग्राम बिरुहली में 8.50 एकड़, सिवनी जिले की कुरई तहसील के ग्राम अवरगनी रै. में 28.88 एकड़ सभी जिलों की कुल मिलाकर लगभग 132.88 एकड़ जमीन विधायक संजय पाठक द्वारा खरीदी गई हैं।

प्रहलाद के पास 200 एकड़

डिंडौरी जिले के कथित जमीन खरीदने वालों में चौथा नाम प्रहलाद कोल, पिता पद्दू कोल निवासी वार्ड क्रमांक 30, छकौड़ी लाल पाठक वार्ड जिला कटनी का है। प्रहलाद कोल के नाम पर डिंडौरी जिले की बजाग तहसील के ग्राम पिपरिया माल एवं हर्रा टोला में लगभग 44.80 हेक्टेयर यानि 112 एकड़ जमीन विधायक संजय पाठक द्वारा खरीदी गई हैं। प्रहलाद कोल के नाम पर डिंडौरी जिले की बजाग तहसील के ग्राम पिपरिया माल में 80.85 एकड़, ग्राम हर्राटोला में 29.90 एकड़ एवं ग्राम सरई टोला में 1.23 एकड़ कुल में 112.00 एकड़ जमीन, जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के ग्राम झींटी में 17.58 एकड़, ग्राम प्रतापपुर में 1.01 एकड़, ग्राम अगरिया में 0.86 एकड़, जबलपुर जिले की जबलपुर तहसील के ग्राम मोठार में 8.85 एकड़, ग्राम प्रतापपुर में 0.81 एकड़, कटनी जिले की बरही तहसील के ग्राम जगुवा में 0.247 एकड़, ग्राम बरमानी में 30.45 एकड़, ग्राम बिरुहली में 15.17 एकड़ एवं ग्राम गब्दी निपनिया में 6.17 एकड़, सभी जिलों की कुल मिलाकर लगभग 199.40 एकड़ जमीन विधायक संजय पाठक द्वारा खरीदी गई हैं।

● श्याम सिंह सिकरवार

सीलिंग एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन

अगर विधायक संजय पाठक की जमीनों को देखें तो उन्होंने सीलिंग एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, दो फसलों के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई 10 एकड़ होनी चाहिए। वहीं एक फसल देने में सक्षम भूमि और सुनिश्चित प्राप्ति फसल के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई 15 एकड़, शुष्क भूमि 30 एकड़ होनी चाहिए। जहां धारक पांच सदस्यों वाले परिवार का सदस्य है या कम है, वहां दो फसलों के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई 18 एकड़, एक फसल देने में सक्षम भूमि और सुनिश्चित प्राप्ति फसल के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई 27 एकड़, शुष्क भूमि 54 एकड़ होनी चाहिए। जहां धारक पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवार का सदस्य है वहां दो फसलों के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई 18 एकड़ और पांच से अधिक सदस्यों के लिए 3 एकड़ तथा अधिकतम 36 एकड़ तक होनी चाहिए। एक फसल के लिए सिंचाई या सुनिश्चित निजी सिंचाई 27 एकड़ और पांच से अधिक सदस्यों के लिए 4.50 एकड़ तथा अधिकतम 54 एकड़ तक होनी चाहिए। शुष्क भूमि 54 एकड़ और पांच से अधिक सदस्यों के लिए 9 एकड़ तथा अधिकतम 108 एकड़ होनी चाहिए। लेकिन संजय पाठक के पास इससे अधिक भूमि है, जो नियमों का उल्लंघन है।

मृतकों को जीवित दिखाकर हड़पे 20 करोड़

ग्वालियर-चंबल संभाग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम पर एक बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। आर्थिक अपराध शाखा की जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में मृत लोगों को जीवित दिखाकर उनके नाम पर बीमा पॉलिसी बनाई गई और फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्रों के जरिए करीब 20 करोड़ रुपए की बीमा राशि हड़प ली गई। अब तक 1,004 संदिग्ध बीमा क्लेम की पहचान की गई है, और यह आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। इस घोटाले में बीमा कंपनी के कर्मचारियों, पंचायत सचिवों और अन्य लोगों की मिलीभगत सामने आई है, जिसमें ग्वालियर और मुरैना के कई आरोपी शामिल हैं। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच को और गहरा करने की तैयारी कर रही है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे 2015 में शुरू किया गया था, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम (मात्र 436 रुपए सालाना) पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए, और मृत्यु होने पर क्लेम के लिए वैध दस्तावेज आवश्यक हैं। लेकिन ग्वालियर-चंबल संभाग में इस योजना का दुरुपयोग कर एक संगठित गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से ठगी को अंजाम दिया। ईओडब्ल्यू को फरवरी 2025 में ग्वालियर में एक शिकायत मिली थी, जिसमें संदिग्ध बीमा क्लेम की जानकारी दी गई थी। जांच शुरू होने पर पता चला कि इस घोटाले में मृत लोगों को जीवित दिखाकर उनके नाम पर बीमा पॉलिसी बनाई गई और फिर फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाकर बीमा राशि का क्लेम किया गया। अब तक की जांच में 1,004 संदिग्ध क्लेम सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश फर्जी पाए गए हैं। ईओडब्ल्यू का अनुमान है कि इस घोटाले की राशि 20 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है, और जांच आगे बढ़ने पर यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

इस घोटाले का संचालन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया, जहां लोगों की जानकारी की कमी का फायदा उठाया गया। गिरोह के सदस्य गरीब और अनपढ़ लोगों को निशाना बनाते थे। उन्हें ऋण या सरकारी योजनाओं में आर्थिक मदद का लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बैंक खाते जैसे दस्तावेज हासिल कर लिए जाते थे। इसके बाद, इन दस्तावेजों का उपयोग कर मृत लोगों के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी बनाई जाती थी। पंचायत सचिवों की मिलीभगत से फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र तैयार किए जाते थे, जिनका इस्तेमाल बीमा क्लेम के लिए किया जाता था। कई मामलों में, पहले से मृत लोगों को जीवित दिखाकर उनके नाम पर पॉलिसी बनाई गई, और फिर दोबारा फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाकर क्लेम हासिल किया गया। इस प्रक्रिया में बीमा कंपनियों के कर्मचारी और सर्वेयर भी शामिल थे, जो क्लेम की जांच में गड़बड़ी कर फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे।

मुरैना जिले में इस घोटाले की सबसे ज्यादा परतें खुली हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में 679 संदिग्ध बीमा क्लेम सामने आए, जिनमें से 5 मामलों में साफ तौर पर फर्जीवाड़ा पाया गया। इन मामलों में पहले से मृत लोगों को जीवित दिखाकर उनके नाम पर बीमा पॉलिसी बनाई गई थी। इसके बाद, पंचायत सचिवों की मदद से फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र तैयार किए गए, और बीमा राशि हड़प ली गई। मुरैना में पंचायत सचिव सूरजराम कुशवाह और मानसिंह कुशवाह सहित कई लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि पंचायत सचिवों को मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार होने के कारण उनकी भूमिका इस घोटाले में महत्वपूर्ण थी। बिना उनकी मिलीभगत के फर्जी दस्तावेज तैयार करना असंभव था। ग्वालियर में इस घोटाले में बीमा कंपनी के कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। ईओडब्ल्यू ने बीमा कंपनी के कर्मचारी विवेक दुबे, जिग्नेश प्रजापति और दीपमाला मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये कर्मचारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बीमा पॉलिसी स्वीकृत करने और क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने में शामिल थे। जांच में यह भी पता चला कि कुछ सर्वेयर फर्जी क्लेम की जांच में जानबूझकर लापरवाही बरतते थे, जिससे बीमा कंपनियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ।

ईओडब्ल्यू की कार्रवाई और जांच की प्रगति

आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई शुरू की है। अब तक 1,004 संदिग्ध क्लेम की जांच की जा चुकी है, और कई आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (दस्तावेजों में जालसाजी), 468 (जालसाजी के उद्देश्य से दस्तावेज बनाना), और 471 (फर्जी दस्तावेजों का उपयोग) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। ईओडब्ल्यू ने बैंकों, पंचायत कार्यालयों और बीमा कंपनियों से दस्तावेज जब्त किए हैं, और फोरेंसिक जांच के लिए इन्हें भेजा गया है। ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह एक संगठित अपराध है, जिसमें कई स्तरों पर मिलीभगत शामिल है। हम सभी संदिग्ध क्लेम की गहन जांच कर रहे हैं और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि इस घोटाले का दायरा मप्र तक सीमित नहीं हो सकता और अन्य राज्यों में भी इसकी जांच की जा सकती है। इस घोटाले ने न केवल बीमा कंपनियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि गरीब और अनपढ़ लोगों का विश्वास भी तोड़ा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था, लेकिन इस तरह के फर्जीवाड़े ने योजना की साख पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब सरकारी योजनाओं पर भरोसा करने से हिचक रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग हो सकता है।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

> मप्र कृषि प्रधान राज्य है। यहां की बड़ी आबादी का मूल व्यवसाय खेती-किसानी है। लेकिन विडंबना यह है कि हर साल फसलों की बुवाई के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त खाद नहीं मिल पाता है।

डिमांड-सप्लाई में जमीन-आसमान का अंतर

मप्र के कई जिलों में इन दिनों खाद की मारामारी है। किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। हरदा ऐसा इकलौता जिला नहीं है जहां किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों के साथ एक से दो दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा हो। बड़वानी, खंडवा, शिवपुरी, अशोकनगर, बुरहानपुर, खरगोन, नर्मदापुरम, विदिशा जैसे कई जिलों की लंबी फेहरिस्त है जहां खाद के लिए अन्नदाता को जूझना पड़ रहा है। कई जिलों में खाद वितरण के दौरान एसडीएम और अपर कलेक्टर को पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ रहा है। हालत ये है कि कई जगह किसान बारिश में भीगते हुए सुबह 4 बजे से सरकारी वितरण केंद्रों में लाइन में लग रहे हैं, लेकिन टोकन मिलने के बावजूद खाद नहीं मिल पा रही है।

समय पर खाद नहीं मिलने से सबसे ज्यादा असर बुवाई पर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि समय से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हरदा की किसान रुक्मणि बाई ने बताया कि हम कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं अब बोला जा रहा है कि जल्द ही खाद मिलेगी, लेकिन रोज-रोज चक्कर लगाने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। सीजन की सबसे ज्यादा बुवाई जून और जुलाई में ही होती है और समय पर खाद नहीं डाली गई तो फसलें खराब हो जाएंगी। नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। मप्र के अधिकांश जिलों में खरीफ सीजन की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है और अब किसानों को खाद की जरूरत है। किसानों को डीएपी और यूरिया खाद की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। सहकारी समितियों की बात की जाए तो यहां कई बार खाद का स्टॉक होने के बावजूद तकनीकी समस्या के चलते खाद नहीं बंट पाती। वहीं कई समितियों और गोदामों के आगे लंबी-लंबी कतारें लगी हैं। आलम ये है कि किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रहा है। कृषि विभाग की बात मानें तो बाजार और समितियों में वैकल्पिक खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। किसानों में खाद के विकल्प को लेकर जागरूकता की कमी देखी जाती है। खासकर सिंगल सुपर फास्फेट जैसी खाद को किसान नजरअंदाज कर रहे हैं। यह डीएपी का असरदार विकल्प साबित हो सकता है। इसी के साथ नैनो यूरिया लेने से भी परहेज कर रहे हैं। प्रदेश में खाद की मारामारी वाले जिलों की लंबी फेहरिस्त है। अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां खाद के लिए किसान रात से ही कतारों में लग जाते हैं। हाल ही में बड़वानी में खाद के लिए किसानों ने जमकर हंगामा किया था। खंडवा जिले के किसान भी खरीफ फसलों की बुवाई के बाद सारे काम छोड़कर खाद के लिए भटक रहे हैं। शिवपुरी में भी किसानों ने खाद के लिए हंगामा किया था। इसके अलावा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, विदिशा, नर्मदापुरम जैसे कई जिले हैं जहां खाद के लिए किसानों को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। 10 जुलाई को अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में खाद को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा था। किसानों ने करौंदी तिराहे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। किसानों का आरोप था कि 15 दिनों से हर दिन खाली हाथ लौट रहे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह भी धरने पर बैठे थे।

यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने हरदा में जमकर हंगामा किया। किसानों का कहना है कि वो 15 दिनों से खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं। किसानों ने खाद की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अपर कलेक्टर के आश्वासन के बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म किया। ग्राम बैड़ी के किसान राजेश कर्मा का आरोप है कि बड़े-बड़े किसानों को सेटलमेंट करके खाद मिल जाता है और छोटे-छोटे किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं और 11 बजे पता चला कि खाद वितरण नहीं होगा। हरदा के अपर कलेक्टर सतीश राय ने बताया कि जिले में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार मक्का फसल का रकबा बढ़ गया है। जिसके कारण इस वर्ष खाद की डिमांड बढ़ गई है। जिले में लगभग 25 हजार मीट्रिक टन खाद की जरूरत है और अभी तक 17 हजार मीट्रिक टन खाद आ चुका है।

● **अरविंद नारद**

यूरिया और डीएपी का विकल्प

कृषि वैज्ञानिकों की मानें तो एसएसपी एक फॉस्फेट युक्त उर्वरक है। इसमें 16 प्रतिशत फास्फोरस, 11 प्रतिशत सल्फर और कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है। एसएसपी का असर धीमे-धीमे होता है लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। एसएसपी के उपयोग से मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बनी रहती है जबकि डीएपी का अधिक इस्तेमाल मिट्टी को सख्त कर देता है। यह फसलों की जड़ों को मजबूती देता है और उनकी पैदावार में सहायता करता है। यूरिया और डीएपी का यह एक अच्छा विकल्प है। खाद संकट को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा खाद वितरण केंद्र की तस्वीरें साझा करते हुए कहा है कि लगता है कि भाजपा सरकार ने किसानों को परेशान करना ही अपना कर्तव्य समझ लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी खाद का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान परेशान हैं और सरकार विदेश में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही है। सागर में खाद वितरण केंद्र पर किसानों की लंबी-लंबी कतारों का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को न खेती की चिंता है और न किसानों की। डीएपी के बाद अब यूरिया भी लापता है।

अब एकल परीक्षा से भरे जाएंगे सभी विभागों के पद...

म प्र के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार अब मिशन मोड में काम करेगी। गौरतलब है कि सरकार ने ढाई लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती का टारगेट रखा है। इसके लिए सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली चयन परीक्षा में मोहन सरकार बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाएं अब बार-बार नहीं होंगी। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर वर्ष में एक बार परीक्षा होगी और सभी श्रेणी के पदों के लिए मेरिट के हिसाब से सूची बन जाएगी। प्रतीक्षा सूची भी एक ही रहेगी। इसके लिए पदों की संख्या सभी विभागों से वर्ष में एक बार पूछ ली जाएंगी और उसके आधार पर सितंबर में कैलेंडर निर्धारित हो जाएगा। जनवरी 2026 से चयन की यह प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में सामान्य प्रशासन विभाग जुटा है।

जानकारी के अनुसार, अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय शुक्ला ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक पर रिक्त पदों के संबंध में भर्ती को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षाएं कराने की बजाय सरकार एकल परीक्षा के माध्यम से रिक्त पद भरने की तैयारी कर रही है। इस परीक्षा के माध्यम से सभी विभागों के विभिन्न रिक्त पदों के लिए एक ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एक वर्ष में एक ही भर्ती परीक्षा कराए जाने के संबंध में प्रारंभिक दौर की चर्चा कर चुके हैं। इस संबंध में आगे सीनियर अधिकारियों के बीच कई दौर की चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मप्र सरकार ने पिछले साल 5 वर्ष में ढाई लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया था। पिछले 18 महीने में प्रदेश में 30 हजार सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती की गई है। इनमें मप्र लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से भरे गए 5600 पद भी शामिल हैं। शेष 24 हजार से ज्यादा क्लास-थ्री के रिक्त पद कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के जरिए भरे गए हैं। मप्र में विभिन्न विभागों में 1 लाख 4 हजार सरकारी पद रिक्त हैं। एक साल में इनमें से 27 हजार रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय शुक्ला ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक पर रिक्त पदों के संबंध में भर्ती को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो चरणों में डेढ़ लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त, 2022 को घोषणा की थी कि एक साल के भीतर 1 लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल ही रही थी कि शिवराज सिंह ने जून, 2023 में 50 हजार रिक्त पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी थी, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी करीब 67 हजार पदों पर भर्ती की जा सकी।

प्रदेश में खाली पड़े विभागों में क्लास-टू के पदों पर भर्ती के लिए मप्र लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगा। क्लास-थ्री के पद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, सीधी भर्ती या आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। क्लास-फोर के पद सीधी भर्ती या आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि एकल भर्ती परीक्षा से अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा की झंझट से मुक्ति मिलेगी। अलग-अलग विभागों की परीक्षा के लिए बार-बार आवेदन करने और फीस भरने की जरूरत नहीं रहेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करने और स्लॉट चुनने में दिक्कत नहीं होगी। सरकार की भी बार-बार परीक्षाएं आयोजित कराने पर बर्बाद होने वाले समय और पैसे की बचत होगी। यदि कोई उम्मीदवार चयनित पद नहीं लेता है, तो वेटिंग लिस्ट के कारण अगला उम्मीदवार तुरंत नियुक्त हो सकेगा। इससे रिक्तियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। एक ही परीक्षा और एक मेरिट लिस्ट से कानूनी अड़चनें दूर होंगी। गौरतलब है कि डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने जून, 2024 में स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पदों का सृजन कर उन पर भर्ती का निर्णय लिया था। ऐसे ही 22 अक्टूबर, 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायिका के 12,670 पद और सुपरवाइजर के 467 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार इन रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। ऐसे ही गत 9 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के लिए 49 हजार 263 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई थी। इन पदों पर भर्ती आने वाले वर्षों में की जाएगी।

प्रदेश में 16 जुलाई, 2025 की स्थिति में एमपी रोजगार पोर्टल पर 27 लाख 52 हजार 571 बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं। सरकार ने पोर्टल पर बेरोजगारों को आकांक्षी युवा नाम दिया है। इस वर्ष पोर्टल पर 5 लाख 79 हजार 78 युवाओं ने पंजीयन कराया है। खास बात यह है कि प्रदेश में परंपरागत विषयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं, इंजीनियरिंग, एमबीए और एमबीबीएस डिग्रीधारी युवाओं ने भी पोर्टल पर पंजीयन कराया है। इससे प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

● **लोकेश शर्मा**

नए फैसले से समय की होगी बचत

प्रदेश में द्वितीय और कार्यपालिक तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारी चयन मंडल परीक्षाएं कराता है। अभी जैसे-जैसे विभागों की ओर से पद उपलब्ध होते हैं, वैसे-वैसे भर्ती वाली ये दोनों एजेंसियां अपने कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं कराती हैं। इसमें न केवल समय लगता है बल्कि अभ्यर्थियों को बार-बार फीस देनी पड़ती है तो एजेंसियों को परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मानव संसाधन से लेकर अन्य व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था को परिवर्तित करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा के साथ विभागीय भर्ती नियम सहित अन्य प्रक्रियाओं में परिवर्तन का खाका तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार, जिस तरह संघ लोक सेवा आयोग एक परीक्षा कराता है और विभिन्न श्रेणी के उपलब्ध पदों के लिए मेरिट के हिसाब से चयन हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पारदर्शिता के लिए नियम से लेकर परीक्षा का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन रहेगा।

12 हजार एकड़ जंगल पर कब्जा

वन विभाग ने ड्रोन से किया दवा का छिड़काव

संयुक्त कृषक संगठन के सिंगोट तहसील अध्यक्ष मुकेश गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र के जंगलों में अतिक्रमण करने वाले लोग बाहरी हैं, और इन्हें कुछ राजनेताओं और वन विभाग के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। गुर्जर के अनुसार, जेसीबी मशीनों का उपयोग केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए किया जाता है, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वनकर्मियों पर जानलेवा हमले के बावजूद, अतिक्रमणकारियों पर केवल जमानती धाराएं लगाई जाती हैं। सरकार अतिक्रमण रोकने के लिए नाके और वॉच टावर बनाने में व्यर्थ खर्च कर रही है। गुर्जर का सुझाव है कि जंगल को सील करके अतिक्रमणकारियों की फसल पर ड्रोन से दवा का छिड़काव किया जाए। उनका मानना है कि दो-चार साल तक फसल बर्बाद होने से अतिक्रमणकारी स्वयं ही वहां से चले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार वन विभाग का समर्थन नहीं कर रही है, तो अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि सरकार को भी इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना पड़े। अतिक्रमणकारियों की पैरवी करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी बेन का कहना है कि, जो लोग सालों से खेती कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हमारे पास वन अधिकार से जुड़े दस्तावेज हैं। रही बात वनों की कटाई की तो जब से वन विभाग बना है, तब से ही कटाई हो रही है। लगातार जंगल कट रहा है। कटाई खुलेआम चलती रही है।

खंडवा में 400 जेसीबी से 12 हजार एकड़ वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के सालभर के अंदर ही यहां फिर से फसलें लहलहाने लगी हैं। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जब भी वन अमला पहुंचता है तो उन पर अतिक्रमणकारी पत्थर फेंकने लगते हैं। वन विभाग के कर्मचारियों को भागना पड़ता है। जुलाई 2024, 26 दिसंबर 2024 और 9 जून 2025...ये वो तारीखें हैं, जब खंडवा में भारी-भरकम पुलिस फोर्स और जेसीबी मशीनों के साथ जंगल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दो साल में 7 हजार, इसके बाद जून 2025 में 5500 एकड़ जमीन से अतिक्रमण साफ किया गया। कार्रवाई के दौरान यहां बबूल के बीज डाले गए। बारिश में पौधे लगाए गए ताकि वापस जंगल पनप सके, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने रासायनिक स्प्रे कर बबूल की रोप को मार दिया, पौधे उखाड़ दिए। फिर से खेत तैयार किए और फसल की बोवनी कर दी।

मुक्त कराई जमीन पर फिर से अतिक्रमण होता देख वन विभाग का अमला कार्रवाई करने पहुंचा और एक ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने वन अमले को घेरकर ट्रैक्टर छुड़ा लिया। मारपीट भी की। एक हफ्ते तक वन अमले और अतिक्रमणकारियों के बीच संघर्ष चलता रहा। अब वन अमले ने भी इस जमीन से दूरी बना ली है। हालांकि वन अमले ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पथराव करने का केस दर्ज कराया है। इस मामले में दो आरोपियों को जिलाबदर किया गया। दरअसल, कोरोनाकाल में ऑक्सीजन की कमी से लाखों जिंदगियों ने दम तोड़ दिया, उसी दौरान लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए जंगल माफिया ने अंधाधुंध कटाई कर जंगलों को साफ कर दिया। खंडवा में दस हजार एकड़ जंगल पर कब्जा कर खेत बना दिए गए। यह सिलसिला चार साल तक चला। प्रशासन सुध लेता तब तक चुनाव आ गए। माफिया गैंग को आदिवासी वोट बैंक का फायदा मिला। हालांकि, प्रशासन ने 2024-25 में माफिया की जंगल से बेदखली के लिए अभियान शुरू किया। गुड़ी रेंज में घने जंगलों से खेत बन चुकी दस हजार एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग को पुलिस और प्रशासन की मदद लेनी पड़ी। पुलिस और प्रशासनिक अमले के नेतृत्व में चार बार बड़ी कार्रवाई की गई। चारों बार 50-50 जेसीबी मशीनों को दो-दो दिन तक शामिल किया। यानी 400 जेसीबी और हर बार इतने ही पुलिस फोर्स के साथ जंगल से अतिक्रमण हटाया गया।

अतिक्रमण हटाने के बाद जंगल में फिर से अतिक्रमण पसर गया है। इन दिनों माफिया गैंग ने मक्का और मूंग फसल की बोवनी कर दी है। करीब पांच दफा फॉरेस्ट का स्टाफ कार्रवाई करने पहुंचा। अतिक्रमणकारियों ने गोफन से पथराव किए। एक बार तो घेर लिया, स्टाफ जान बचाकर भागा। खेत बन चुके जंगल में दूर-दूर तक फसल लहलहा रही थी। स्थानीय आदिवासी जंगल में अतिक्रमण के खिलाफ खड़े थे। कोरकू समाज के लोगों ने कहा- जंगल हमारे लिए भगवान है। हम लोग यहां के मूल निवासी होकर भी जंगल से जलाऊ लकड़ी तक नहीं लाते हैं। जबकि बाहर से आए अतिक्रमणकारियों ने पूरा जंगल उजाड़ दिया। वे लोग खेती कर रहे हैं। हम विरोध करते है तो धमकाते हैं। जंगल में मवेशी चराने जाएं तो मारपीट करते हैं। अतिक्रमणकारियों ने घास पर जहरीली दवा छिड़क दी, चरने गए हमारे कई मवेशी मर गए हैं।

वन समिति अध्यक्ष माणकलाल कोरकू ने बताया कि जंगल जो भी इंसान जाता है, भले ही मवेशी चराने जाए या जलाऊ लकड़ी लाने के लिए जाए, उन्हें भगा दिया जाता है। फॉरेस्ट वाले भी जाते हैं तो उन पर पत्थर फेंकते हैं। इन लोगों से हम ग्रामीणों को काफी समस्या है। ऐसे में तो गांव वाले भी अतिक्रमण करने लग जाएंगे। भिलाईखेड़ा के आदिवासी किसान गोपाल पाटिल ने कहा- हम गांव वालों का निवेदन है कि सरकार को जितने भी कड़े कदम उठाना है तो उठा लो, लेकिन जंगल से अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण के कारण जंगल में मवेशी चरने जाते हैं तो वो लोग पत्थर मारते हैं। किसी भी प्रकार से इन्हें रोका जाए या फिर ये लोग जहां से आए हैं, वहां वापस भेजा जाए।

● सिद्धार्थ पांडे

मप्र में विधानसभा चुनाव को अभी 3 साल का समय है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां मिशन 2028 की तैयारी में जुट गई हैं। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ ही प्रदेशभर में दौरा कर संगठन को सक्रिय बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस ने मांडू में दो दिनों तक अपने विधायकों को प्रशिक्षण देकर आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने का लक्ष्य बनाया है। यानि दोनों पार्टियों का टारगेट 2028 है।

टारगेट पर 2028

मप्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां मिशन मोड़ में नजर आ रही हैं। वैसे तो भाजपा पूरे साल कार्यक्रमों के माध्यम से अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है, वहीं अब कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को सक्रिय कर दिया है। अपनी चाल, चरित्र और चेहरा वाली लाइन से हटकर होर्डिंग-पोस्टर और सोशल मीडिया पर नेतागिरी का दिखावा करने वाले अपने कार्यकर्ताओं पर भाजपा नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सभी को संदेश दे दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अब इस पर अमल करने की रणनीति पर काम हो रहा है। दरअसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का पूरा फोकस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सरलता और सुचिता पर है। ऐसे में गाड़ियों से लेकर शहर में होर्डिंग-पोस्टर और सोशल मीडिया पर बेवजह दिखने वाले नेताओं की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा में चिंतन का दौर चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा की तैयारी है कि अनावश्यक रूप से कार्यकर्ता न तो गाड़ियों में हूटर लगाएं और न ही अनावश्यक रूप से पार्टी के बजाय खुद के चेहरे चमकाने पर जोर दें। भाजपा ऐसे नेताओं के **सोशल अकाउंट** खंगाल रही है। ताकि सूची तैयार कर उन्हें अध्यक्ष की मंशा से अवगत कराया जा सके। इस मामले को लेकर भाजपा सीधे तौर पर कुछ कहने से बच रही है, लेकिन प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा है कि सहजता भाजपा का मूल स्वभाव है। पार्टी का हर कार्यकर्ता इसे अमल करता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कार्यकर्ता या पदाधिकारियों की बैठकों में सरलता और सुचिता की लगातार हिदायत दे रहे हैं। सूत्रों की मानें तो नवागत प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में लगे हूटर से लेकर अनावश्यक पावर दिखाने वाले नेताओं के इस व्यवहार से असहज हैं। ऐसे कार्यकर्ता या पदाधिकारियों को सरलता और सुचिता का पाठ पढ़ाने के लिए उनकी सूची तैयार की जा रही है। नवागत प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इसी स्वभाव में रमे हैं। उनका अनुसरण हर कार्यकर्ता करेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का कहना है कि हेमंत खंडेलवाल सरल हैं। वह अपेक्षा कर रहे हैं कि कार्यकर्ता भी ऐसा करें। भाजपा तो अब विधायक-सांसदों का भी प्रशिक्षण करा चुकी है, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि होर्डिंग पर बड़ा फोटो लगाने से पद नहीं मिलेगा और न ही आपका भविष्य बनेगा। जिसने खुद की चिंता की, वो कही नहीं पहुंचा। पार्टी की चिंता करने वाला ही ऊंचाई पर पहुंचा है। आप अपनी चिंता छोड़ दें। फेसबुक, ट्विटर पर आप खुद की जगह सरकार की बात करें। सोशल मीडिया पर वो चीज डाले जिसकी समाज को जरूरत है।

गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाले युवा चाहिए, न कि होर्डिंग और सोशल मीडिया पर खुद को चमकाने वाले। खंडेलवाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सोशल मीडिया पर पार्टी और समाज के हित में बात करें, न कि अपनी व्यक्तिगत छवि चमकाएं। जिसने अपनी चिंता की, वह कहीं नहीं पहुंचा, लेकिन पार्टी की चिंता करने वाला हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचा है। खंडेलवाल का कहना है कि **कार्यकर्ता खुद** की चिंता छोड़ दें। आप काम पर ध्यान दें, आपकी चिंता पार्टी करेगी। मेरा आप सब से कहना है कि सोशल मीडिया पर खुद के अलावा हमारी पार्टी क्या कर रही है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं उसे शेयर

नेताओं को समाज हित में काम करने की जरूरत

इस मौके पर खंडेलवाल ने ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में दो नेताओं के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान और श्रेय लेने की राजनीति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में इस तरह की गुटबाजी तो होती रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि नेताओं को समाज हित में काम करने की जरूरत है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पदाधिकारियों की बैठकों में कई बार कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की सीख दे चुके हैं। गत दिनों हुई युवा मोर्चा की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि होर्डिंग में बड़ा फोटो लगाने से बड़ा पद नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विचारधारा वाली पार्टी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को समाज से जुड़ने की नसीहत दी जा रही है। कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि वे सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें, इससे पार्टी मजबूत होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में सादगी जरूरी है। हमारा उद्देश्य है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता सादगी से रहे और पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहे, लेकिन बदलते समय में तकनीक और इन्फ्रास्ट्रक्चर से समझौता नहीं किया जा सकता।

करें। आप कहां घूमने गए हैं इससे समाज को कोई लेना-देना नहीं हैं। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं वो पोस्ट करने से आपका इंप्रेशन खत्म हो रहा है। आप अपने सोशल मीडिया पर जो शेयर करेंगे उससे समाज में आपकी वैसी इमेज बनेगी।

वहीं मांडू में कांग्रेस के दो दिवसीय नव संकल्प शिविर में पार्टी ने 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अहम निर्णय लिए। कांग्रेस ने मप्र में बदलाव का नारा देते हुए हर विधानसभा सीट के सामाजिक, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर मंथन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों ने समूह बनाकर बेरोजगारी, महंगाई, किसान, ओबीसी आरक्षण, महिला सुरक्षा, जनजातीय मुद्दों, संगठन सृजन और जनगणना जैसे विषयों पर अपनी-अपनी रिपोर्ट दी। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी ने अब सत्ता में वापसी का संकल्प ले लिया है। विधायक दल की रिपोर्ट संगठन को सौंपी गई है। 10 विधायकों की कमेटियों का गठन किया गया है जो लगातार रणनीतिक काम करती रहेंगी। कांग्रेस संगठन सड़कों पर और विधायक सदन में भाजपा को घेरेंगे।

दरअसल, मप्र में कांग्रेस विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में अगले तीन साल का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एग्रेशन के साथ सियासत करेगी। राज्य में जनता से जुड़े मुद्दे कैसे उठाए जाएं, इसे लेकर रोडमैप बनाया गया है। विधायक दल ने मंथन के बाद संगठन को रिपोर्ट सौंपी है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, ओबीसी आरक्षण, महिला अपराध, किसान, युवाओं, आदिवासियों को केंद्र में रखकर काम करेगी। संगठन सड़कों पर तो विधायक सदन में भाजपा को घेरेंगे। कांग्रेस विधायकों के बाद प्रदेश के पदाधिकारी और संगठन सृजन में चुनकर आने वाले जिला अध्यक्षों को भी बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी जाएगी। चिंतन शिविर में राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के पक्ष को सही ठहराते हुए कांग्रेस ने इसे जन अधिकारों की बहाली का माध्यम बताया और कहा तेलंगाना मॉडल को मध्यप्रदेश में लाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही वन अधिकार कानून और पेसा एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू करने की

प्रतिबद्धता जताई गई। शिविर के दौरान कांग्रेस सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत, कोषाध्यक्ष अजय माकन, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया।

मांडू में कांग्रेस ने विचारधारा और संगठनात्मक दृष्टि से व्यापक रणनीति तैयार की। पार्टी ने शिविर को केवल संगठनात्मक मंथन का मंच नहीं, बल्कि भविष्य की ठोस योजना के रूप में पेश किया। कांग्रेस के 60 से अधिक विधायकों को 10-10 के छह समूहों में बांटकर जातिगत जनगणना, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण, वन अधिकार कानून, पैसा एक्ट, जनजातीय अधिकार, संगठन सृजन अभियान जैसे प्रमुख मुद्दों पर गहन चर्चा करवाई गई। प्रत्येक समूह ने अपने अनुभवों और सुझावों को साझा करते हुए प्रदेश के जमीनी हालात पर चिंतन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नव संकल्प शिविर की सफलता से भाजपा घबराई हुई है। मांडू में हमने जनसंकल्प लिया है, पंचमढ़ी में भाजपा की तरह हनीमून नहीं मनाया। भाजपा को डर है कि आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस उनके भ्रष्टाचार, विफल योजनाओं और जनविरोधी निर्णयों को उजागर करेगी और हम यह जरूर करेंगे। सिंघार ने कहा कि यह शिविर सिर्फ सत्र की तैयारी नहीं बल्कि प्रदेश के बदलाव की ठोस नींव है। कांग्रेस ने इस शिविर में एक रणनीतिक दस्तावेज भी तैयार किया है। जो आगामी जनसंपर्क अभियानों, संगठनात्मक विस्तार और जनता से संवाद का आधार बनेगा। कुल मिलाकर, कांग्रेस ने मांडू से 2028 की तैयारियों की शुरुआत करते हुए अपने राजनीतिक संघर्ष और वैचारिक स्पष्टता का प्रदर्शन किया है। पार्टी ने संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में वह सड़क से सदन तक भाजपा को घेरने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी।

कांग्रेस के इस नव संकल्प शिविर में विधायकों को सोशल मीडिया, डिजिटल इंटेलिजेंस का पाठ भी पढ़ाया गया। फेसबुक, शॉर्ट वीडियो, इंस्टा, यूट्यूब, एक्स की बारीकी सिखाई गई। आईटी सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने विधायकों को ट्रेनिंग दी। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में डिजिटल उपस्थिति जरूरी है और हर विधायक जनता से जुड़े मुद्दों को सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उठाएगा। कांग्रेस ने तय किया है कि पार्टी का डिजिटल सेल हर विधानसभा पर नजर रखेगा और जन मुद्दों से जुड़े कंटेंट को आगे बढ़ाएगा। साथ ही सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर किया जाएगा।

● **प्रवीण सक्सेना**

हर समाज, हर वर्ग के विकास के लिए काम

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मजबूत कर रहे हैं, हर समाज, हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमें उन्हें मजबूत करना है। जनजातीय समाज तरक्की करे, इसके लिए हमारी सरकार होना जरूरी है। मोर्चा कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच की कड़ी बनकर जनहितैषी योजनाओं का लाभ आमजन को दिलाएं। खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में जनजातीय समाज की अहम भूमिका है। समाज मप्र के बड़े क्षेत्र में निवास करता है। मैं भी आदिवासी बहुल बैतूल जिले का रहने वाला हूं। मुझे और मेरे परिवार को हमेशा जनजातीय समाज की सेवा करने का मौका मिला और जनजातीय समाज हमारे परिवार और भाजपा का पूरा सहयोग कर रहा है। इसलिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा की भूमिका पार्टी और समाज में महत्वपूर्ण है। आप अपनी भूमिका का निर्वाह जितनी सक्रियता के साथ करेंगे, भाजपा की जीत भी उतनी ही सुनिश्चित होगी। अनुसूचित जनजाति मोर्चा कार्यकर्ता समाज के नेता बनें, समाज को पार्टी से जोड़ने का काम करें।

सागौन के रूट-शूट बना रहे करोड़पति

मप्र के शहडोल संभाग को प्रकृति का वरदान मिला हुआ है। घने जंगल, वन्यप्राणी, नदियां, तालाब, झरने, पहाड़ियां यहां का मौसम सबकुछ इस संभाग को अलग बनाते हैं। संभाग का उमरिया जिला तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के चलते देश-दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता ही है। इसके साथ ही अब ये जिला सागौन की नर्सरी को लेकर भी अपनी एक खास पहचान बना रहा है। यहां तैयार किए गए सागौन की नर्सरी की डिमांड बहुत ज्यादा है। खासकर यहां के रूट-शूट बहुत फेमस हैं, जिससे इस जिले को अब एक अलग पहचान भी मिल रही है।

वन विकास निगम उमरिया ने इस बार लगभग 15 लाख रुपए के सागौन के पौधे रूट-शूट और पॉली पॉट तकनीक से तैयार किए हैं। जिसकी प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अच्छी खासी डिमांड है। वन विकास निगम उमरिया के डीएम अमित पटौदी ने बताया कि 5.62 लाख रुपए के सागौन के रूट-शूट और करीब 70 हजार पॉली पॉट तकनीक से तैयार सागौन के पौधे उमरिया जिले में लगाने के लिए भेजे गए हैं। 20 जून से 13 जुलाई के बीच में मप्र के डिंडोरी जिले में 17 हजार, इसके अलावा विंध्य क्षेत्र के रीवा और सीधी जिले में भी करीब 7.40 लाख सागौन के रूट-शूट भेजे गए हैं। किसी भी पौधे का जंगल तैयार करने के लिए जरूरी होता है कि अच्छी क्वालिटी के पौधे होने चाहिए। सागौन के पौधे तैयार करना इतना सरल काम नहीं होता है। उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और एक तकनीक के तहत ही उसके पौधे तैयार होते हैं। सागौन के पौधे लगाने के लिए सबसे फेमस तकनीक रूट-शूट है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले बेड़ तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इनमें सागौन के बीजों की बुवाई की जाती है फिर उसकी देखरेख की जाती है। करीब दो साल तक उसकी बारीकी से देखरेख करनी पड़ती है। दो वर्षों के बाद वो बीज एक स्वस्थ पौधा बन जाता है। इसके बाद इन स्वस्थ पौधों को उखाड़ लिया जाता है फिर तेज धार वाले औजार से उसकी कटाई की जाती है। ताकी उसमें कटाई के दौरान जड़ छिले नहीं। उसमें रूट और शूट दोनों होना चाहिए। रूट का मतलब जड़ और शूट का मतलब तना होता है।

जानकार बताते हैं कि सागौन के रूट-शूट को लगाने के लिए क्रोबार औजार का उपयोग किया जाता है। क्रोबार औजार एक लोहे की शबरीनुमा सरिया होती है, जिसमें 22 सेंटीमीटर पर एक क्रॉस बार लगा होता है। क्रोबार की सहायता से ही उस रूट-शूट को टाइट किया जाता है। रूट-शूट को टाइट करने के लिए क्रोबार से जहां पर हम रूट-शूट लगाते हैं, उससे लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्रोबार को दबाकर रूट-शूट की ओर घुमाया जाता है, जिससे वो रूट-शूट टाइट हो जाता है। इसी तरह से रूट-शूट को जमीन पर लगाया जाता है, जिससे सागौन के अच्छे पौधे तैयार हो जाते हैं, जो आगे चलकर एक बड़ा वृक्ष बनता है। सागौन के पौधे तैयार करने की रूट-शूट के अलावा एक तकनीक पॉली पॉट विधि भी है। इसमें जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है पॉली पॉट, मतलब पॉली बैग में तैयार किए गए पौधों को पॉली पॉट कहा जाता है। इसमें अलग-अलग साइज की पॉलीथीन आती है। उसमें मिट्टी, खाद, आदि भरकर बीज लगाए जाते हैं। या फिर पहले बेड़ में पौधा तैयार करके पॉली पॉट में रोपित कर दिए जाते हैं फिर उनकी देखरेख की जाती है। इन पौधों को लगाने के लिए बरसात पूर्व गड्डों की खुदाई कर ली जाती है और उसमें ये पौधे लगाए जाते हैं।

सागौन के उत्पादन में नंबर-1 है मप्र

सागौन के जंगलों के मामले में देश में मप्र नंबर-1 है। यहां के जंगलों में सागौन के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्रप्रदेश में भी सागौन के काफी जंगल पाए जाते हैं। मप्र में सागौन के जंगलों की बात करें तो बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी जैसे जगहों पर सागौन के जंगल पाए जाते हैं। इसके अलावा अब उमरिया जिले में भी सागौन के पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगवाया जा रहा है। हलांकि यहां पर प्राकृतिक तौर पर साल के जंगल सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अब सागौन भी तैयार किया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सागौन के जंगलों में आधा हिस्सा तो सिर्फ म्यामार में है। बाकी अब तो अलग-अलग विधि से इसे पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है।

सागौन के पौधों को बरसात के मौसम में पहली बारिश के बाद लगाना बिल्कुल सही होता है। जब जमीन गर्म हो, तभी इसे लगा देना चाहिए। सागौन के पौधे लगाने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि जहां भी लगाएं फिर चाहे रूट-शूट लगाएं या फिर पॉली पॉट से तैयार किए गए पौधे लगाएं, उस जगह पर पानी न रुकता हो। पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था हो। फिर समय-समय पर खाद डालते रहें और उसकी देखरेख करते रहें। सागौन का पौधा बहुत ही बहुमूल्य माना जाता है। एक बार अगर आपने सागौन के कुछ पौधे तैयार कर लिए मतलब आपने पैसों का एक खजाना तैयार कर लिया है। क्योंकि ये इमारती लकड़ी मानी जाती है। इससे कई तरह की बहुमूल्य चीजें बनाई जाती हैं। बाजार में सागौन की लकड़ियों की अच्छी खासी डिमांड है। सागौन के पौधों को तैयार करना बहुत आसान है। पिछले कुछ सालों में सागौन के कई पौधे उमरिया जिले में लगाए गए हैं और वो तेजी से ग्रोथ भी किए हैं। मतलब शहडोल संभाग का एटमॉस्फियर सागौन के जंगल के लिए बहुत बेहतरीन है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सागौन का पौधा एक तरह से कह सकते हैं कि ये बेशरम प्रजाति का है। कहीं भी आसानी से लग जाता है। बड़ी बात यह है कि इसे मवेशी भी नहीं खाते हैं। सागौन का पेड़ 80 से 100 फीट तक लंबा हो सकता है। माना जाता है कि 60 साल में ये पौधा मैच्योर होता है। हालांकि, सागौन का पौधा 25 साल बाद इमारती उपयोग के लायक हो जाता है।

● विकास दुबे

न अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, न ही सदस्य

मप्र में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने विभिन्न आयोगों का गठन किया है। लेकिन विडंबना यह है कि अधिकांश आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद सालों से खाली पड़े हैं और इसकी वजह से काम-काज में लेट-लतीफी चल रही है। गौरतलब है कि सरकारी सिस्टम से हताश लोगों के लिए आशा की किरण होते हैं आयोग। इसके विपरीत मप्र में कई आयोगों की हालात ये है कि उन्हें ही न्याय की दरकार है।

गौरतलब है कि राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति जैसे आयोगों का तो गठन ही नहीं हो सका है। सिस्टम अफसरों के भरोसे है। मानव अधिकार आयोग में लंबे समय से अध्यक्ष नहीं है। एकमात्र सदस्य को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात होती हैं। सियासत में भी चर्चा होती है, लेकिन इस वर्ग के लिए गठित आयोग की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। आयोग के पास न अमला है और न ही अपना दफ्तर। अध्यक्ष ने सरकार को पत्र लिखकर स्टाफ और अलग से दफ्तर के लिए भवन मांगा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि दिसंबर 2023 से वे अध्यक्ष हैं। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का अत्यावश्यक कार्य चल रहा है। ऐसे में आयोग में पूर्णकालिक सचिव की जरूरत है। विविध सलाहकार सहित सभी रिक्त पदों की पूर्ति की जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आयोग के गठन न होने पर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्पीड़न को रोकने प्रदेश में कई आयोग बनाए गए जो 2016-17 से भाजपा के कार्यकाल में निष्क्रिय हो चुके हैं। आयोग सिर्फ नाम के बचे हैं। स्थिति इतनी दयनीय है कि ये न तो पीड़ितों की आवाज सुन पा रहे हैं और न ही उनके लिए कोई ठोस कार्रवाई कर पा रहे हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द नियुक्तियां करे।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह आयोग एक कोर्ट की तरह काम करते हैं जिनके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। यह शिकायतों को सुनते हैं और बिना खर्च एवं बिना किसी कोर्ट, पुलिस को शामिल किए उसका निपटारा करते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष होता है और उसके पांच सदस्य। लगभग दर्जनभर स्टाफ किसी भी शिकायत की जांच करना, शिकायतकर्ता को संबल देना और उसके निष्पादन के लिए सरकार को आदेशित करता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार ने इन आयोगों का भट्टा बिठा दिया है, जो सामाजिक न्याय पर गहरा प्रहार है। उन्होंने कहा कि इन आयोगों की स्थिति इतनी दयनीय है कि ये न तो पीड़ितों की आवाज सुन पा रहे हैं और न ही उनके लिए कोई ठोस कार्यवाही कर पा रहे हैं। यहां तक कि राज्य के कुल आठ प्रमुख आयोगों में से केवल तीन-पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग में ही अध्यक्ष नियुक्त हैं, लेकिन इनमें भी सदस्यों की भारी कमी है। शेष पांच आयोग वर्षों से बिना अध्यक्ष और सदस्यों एवं बिना कर्मचारियों के संचालित हो रहे हैं। जैसे बिना जज के कोर्ट।

मप्र में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बने राज्य महिला आयोग की हालत खुद एक सवाल बन गई है। बीते 7 वर्षों से आयोग पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा है। आयोग में न अध्यक्ष हैं, न सदस्य, न ही कोई बेंच बैठ रही है और न ही सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। आयोग के नियमों के मुताबिक, किसी भी शिकायत पर 15 दिनों में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब पूरा आयोग ही ठप पड़ा हो तो न्याय की उम्मीद बेमानी लगती है। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित कार्यालय में सन्नाटा पसरा है- अध्यक्ष और सदस्यों के कक्ष पर ताले लटके हैं और नेम प्लेट को कागज से ढंक दिया गया है। कमलनाथ सरकार में आयोग का गठन हुआ था, लेकिन मार्च 2020 में सरकार के अल्पमत में आने और सत्ता परिवर्तन के बाद विवाद की स्थिति बनी। मामला कोर्ट पहुंचा। तबसे अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और न ही कोई सदस्य मनोनीत हुआ ऐसे में यहां न्याय पाने की आस लिए पहुंची महिलाओं को निराशा होती है। पीड़ितों की शिकायत लेकर काम की पूर्ति मानी जाती है। लंबित मामलों की संख्या 30 हजार से अधिक जा पहुंची है। प्रदेश का सूचना आयोग असहाय पड़ा हुआ है। आयोग में लबित मामलों की संख्या 20 हजार तक जा पहुंची है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 मुख्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त सहित तीन सूचना आयुक्त ही हैं। लंबित द्वितीय अपीलों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।

● हर्ष सक्सेना

शिकायतों के भार से बदे ये आयोग

प्रदेश में कई अन्य आयोग भी ऐसे हैं जो शिकायतों के भार से बदे हुए हैं। मप्र मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है। यह आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे है। यानी इकलौते सदस्य राजीव कुमार टंडन को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। सुनवाई के लिए कम से कम दो सदस्य होने चाहिए। बेंच नहीं लगने की वजह से आयोग में सिर्फ मानव अधिकार हनन से जुड़े मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों को नोटिस जारी किया जा रहा है। आयोग में रोजाना औसतन 8-10 मामलों में संज्ञान लिया जाता है। ज्यादातर मामले मीडिया रिपोर्ट के आधार पर होते हैं। एमपी नगर स्थित अनुसूचित जाति आयोग का दफ्तर खोजना आसान नहीं। फ्लैट में लग रहे आयोग तक पहुंचो तो पता चलता है कि न अध्यक्ष हैं और न ही सदस्य। कर्मचारियों ने बताया कि सचिव सीमा सोनी कार्यालय में हैं। सचिव सीमा कहती हैं कि यह सही है कि आयोग में अध्यक्ष-सदस्य की नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन आयोग में आने वालों को निराश नहीं लौटना पड़ता। सुनवाई हो रही है। आवेदन लेकर संबंधित जिलों के अफसरों को भेजते हैं। रिपोर्ट भी मांगी जाती है। जरूरत पड़ने वे स्वयं सुनवाई भी करती हैं। अनुसूचित जनजातियों को न्याय दिलाने अजजा आयोग का प्रावधान है। यह आयोग भी नाम का रह गया है।

संसद में हंगामा है बरपा...कामकाज अधर में लटका

सिंदूर, वोटर, धनखड़ जनता की नहीं फिकर

इस समय संसद और राज्यों की विधानसभाओं में मानसून सत्र चल रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि माननीय जनहित से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान का रास्ता निकालेंगे, लेकिन संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हंगामा बरपा हुआ है। यही हाल मप्र की विधानसभा सहित अन्य राज्यों की विधानसभा में देखने को मिल रहा है। हंगामे के कारण कामकाज अधर में लटके हुए हैं और जनता की फिकर किसी को नहीं है।

● **राजेंद्र आगाल**

संसद के मानसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच खींचतान के बाद जैसा हंगामा देखा जा रहा है, वह एक तरह से अपेक्षित था। जिस तरह कार्यवाही स्थगित की जा रही है, उससे एक बार फिर यही लगता है कि जनहित से जुड़े मसलों पर बातचीत के बजाय संसद अब सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की जगह बनती जा रही है। विपक्ष को लगता है कि सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक सदन में बहस के लिए मुद्दों का चुनाव करती है और ऐसे में जनहित तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों की उपेक्षा की जाती है। वहीं सरकार यह मानती है कि विपक्ष नाहक ही सदन को बाधित कर जरूरी कामकाज में अड़चन डालता है। इसमें दोराय नहीं कि जब तक किसी मुद्दे पर लोकसभा या राज्यसभा में बहस नहीं होगी, तब तक जनहित के सवाल उपेक्षित रहेंगे, लेकिन इस क्रम में ऐसी स्थिति पैदा होने को कैसे सही ठहराया जा सकता है कि सदन में विचार-विमर्श के बजाय एकतरफा बातचीत होने लगती है और उसी के आधार पर नियम-कायदे भी तय हो जाते हैं।

एक दौर वह भी था, जब संसद और राज्यों की विधानसभाओं की लाइब्रेरी सांसदों और विधायकों से गुलजार रहती थी। जनप्रतिनिधि जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए अपनी तैयारियां करते थे। सांसद नीलोत्पल बसु, गुरुदास दासगुप्ता, संघ प्रिय गौतम सहित बड़ी संख्या में ऐसे सांसद थे, जो अपने बड़े से बड़े काम छोड़कर संसद की बैठक में आते थे क्योंकि उनके लिए वही मंदिर था। आज भी ऐसे सांसदों की कमी नहीं है, जो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन दिन पर दिन होने वाले हंगामे ने उन्हें विवश कर दिया है। इन सतत् हंगामों के लिए कौन दोषी है और कौन निर्दोष, यह एक जटिल सवाल है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि संसद और विधानसभाओं की बैठकों में हंगामे को ही अपना धर्म मान लिया गया है?

सरकार और विपक्ष आमने-सामने

गौरतलब है कि करीब एक महीने तक चलने वाले मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से मुख्य रूप से पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण, मणिपुर के हालात और चीन के रुख आदि मसलों पर चर्चा कराने पर जोर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे बहस हुई। इस दौरान, जहां सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित तमाम नेताओं ने सरकार का पक्ष रखा, वहीं विपक्ष की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, गौरव गोगोई सहित तमाम सांसदों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। दो दिनों तक चली बहस के बाद भी संसद में हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

सरकार और विपक्ष के बीच संसद में आमने-सामने की बहस और सवाल-जवाब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर सरकार को लगता है कि वह विपक्ष की मांग के मुताबिक सभी विषयों पर बहस के लिए तैयार है, तब आखिर संसद में हंगामे की नौबत क्यों आती है? क्या ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकल सकता जिसमें सदन बाधित न हो और संसद का कामकाज सुचारू रूप से चले? विपक्ष अगर चर्चा की मांग करता है, तो सदन को सामान्य रूप से संचालित होने देना और जरूरी मुद्दों पर बहस को लोकतांत्रिक निष्कर्ष तक ले जाना आखिर किसकी जिम्मेदारी है?

देश और नागरिकों के हित से जुड़े व्यापक महत्व के सवालों पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं होगी तो और कहां होगी? मगर सरकार और विपक्ष जिन मुद्दों पर टकराव की मुद्रा में आ जाते हैं, उसमें यह कैसे तय होगा कि किस सवाल को बहस की प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए? सही है कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और उसके बाद की परिस्थितियां राष्ट्रीय महत्व का मसला है। इसी तरह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जिस तरह के सवाल उठे हैं, उस पर भी तत्काल बात होनी चाहिए। मणिपुर में भी लंबे समय से जिस तरह हिंसा के हालात बने हुए हैं, उसका समाधान भी तुरंत खोजने की जरूरत है। मगर क्या सदन में इसके लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित है? विडंबना है कि हंगामे की शोर में जरूरी मुद्दों पर बहस नहीं हो पाती और सदन स्थगित हो जाता है। इस संदर्भ में सदनों की कार्यवाही पर एक दिन के खर्च और उसके बेकार जाने के मसले पर भी काफी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सरकार और विपक्ष को मिलकर यह सोचने की जरूरत है कि बाधित सदन में जनहित के सवालों के लिए कितनी जगह बची है।

ऑपरेशन सिंदूर जारी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह भारत के खिलाफ किसी दुस्साहस की कल्पना करता है, तो उसे करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की कल्पना की तो, उसे करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक ओर भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस पाकिस्तान से मुद्दे आयात कर रही है। उन्होंने कहा, भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पाकिस्तान से मुद्दे आयात कर रही है। विपक्ष पर हमला तेज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को बस विरोध करने का बहाना चाहिए होता है, इसलिए आज पूरा देश उन पर हंस रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकी रो रहे हैं, उनके सरगना रो रहे हैं और उन्हें रोता देख कुछ लोग यहां भी रो रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के समय इन्होंने खेल खेलने की कोशिश की, नहीं चला। एयरस्ट्राइक के दौरान फिर खेला, फिर भी नहीं चला। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो नई रणनीति अपना ली- क्यों रोक दिया? वाह रे बयान बहादुरों! तुम्हें तो विरोध के लिए बहाना चाहिए। इसलिए आज पूरा देश तुम पर हंस रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बताया कि कैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें 9 मई की रात फोन कर पाकिस्तानी हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया, तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

कार्यवाही कम, हंगामा अधिक

वर्ष 2006 में जब तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा टीवी की शुरुआत की थी, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह देश सदन के अंदर सदस्यों का ऐसा आचरण देखेगा, जो लोगों को दुखी भी करेगा और शर्मिंदा भी। लेकिन देश देख रहा है कि संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही कम चलती है और हंगामा अधिक होता है। एक

ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे वार-पलटवार

संसद के मानसून सत्र के छठे दिन दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री सहित तमाम नेताओं ने अपना पक्ष रखा, वहीं विपक्ष ने सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े किए। चर्चा का केंद्र तीन मुद्दों पर रहा। पहला- क्या पहलगाम हमला खुफिया तंत्र की विफलता थी? दूसरा- युद्धविराम क्यों हुआ? और तीसरा क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इसे खुफिया तंत्र की विफलता बताया और गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा, मैं पूछती हूं, नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की नहीं? गृहमंत्री की नहीं? रक्षामंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नहीं? प्रियंका गांधी ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि उसने बैसरन घाटी में नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। प्रियंका गांधी के आरोपों से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले पर जवाब दिया और कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता दिखाई थी। प्रियंका गांधी ने कहा, पहली बार भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध होते-होते रुक गया और इसका ऐलान ट्रंप करते हैं। लेकिन सरकार जवाब नहीं देती कि युद्ध क्यों रुका। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की बात नहीं मानी और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, वो ट्रंप के साथ लंच खा रहा था। क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे? अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान हुआ, तो इसमें छुपाने में क्या है? राजनाथ सिंह ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा, तो फिर क्यों नहीं कह देते कि जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचा।

घटना याद आ रही है। उप्र विधानसभा की बैठक हंगामे के बाद स्थगित हो गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लगातार 9 बार विधायक चुने जा चुके उदल व समाजवादी नेता और विधायक रवींद्रनाथ तिवारी चिंतित मुद्रा में एक कक्ष में बैठे थे। हाथ में उन प्रश्नों का बंडल था, जो उस दिन विधानसभा की बैठक में पूछे जाने थे। जब इन दोनों विधायकों से पूछा कि आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं तो रवींद्रनाथ तिवारी ने कहा कि आज कई सवाल लगे हैं, लेकिन अब हंगामा हो गया है। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि प्रश्नों की तैयारी करते हैं, लेकिन हवा ऐसी बदली कि सदन की बैठकों में उन लोगों का बोलबाला हो गया, जिन्हें न तो संसदीय परंपराओं की जानकारी है, ना जनता के दुख-दर्द से कोई मतलब। सदन के अंदर होने वाला हंगामा अखबारों की हेडलाइन बनता है। चैनलों में भी उन्हीं के करतब छाए रहते हैं। जमीनी मुद्दे किनारे कर दिए गए हैं तो फिर रात-रात भर जागकर जनहित से जुड़े मुद्दों पर माथापच्ची क्यों हो?

अब नहीं होती लंबी बहस

लोकसभा और राज्यसभा में मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ। सत्तापक्ष और विपक्ष की भूमिकाएं बदलने के साथ उनका रुख भी बदलता रहा है। लगता ही नहीं कि यह वही संसद है, जिसमें डॉ. राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्रजीत गुप्त, सोमनाथ चटर्जी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, चतुरानन मिश्र, मधु दंडवते और लालकृष्ण आडवाणी जैसे विपक्षी दिग्गज लंबी-लंबी बहसों में भाग लेते थे और सत्तापक्ष की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, प्रणब मुखर्जी, वसंत साठे, एस बी चव्हाण जैसे दिग्गज चुटीले जवाब भी देते थे। संसद और विधान मंडलों में हंगामे का सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को होता है तो वह है जनता। विपक्ष के पास सदन की बैठक ही सबसे बड़ा मारक हथियार है। प्रश्न प्रहर और शून्य प्रहर में उठने वाले मुद्दे तमाम समस्याओं का निदान लेकर आते हैं। उप्र विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित बताते हैं कि वह पहली बार चुनाव जीतकर आए थे और एक गांव में पुलिस अत्याचार का मुद्दा सदन में उठाया था। उसी दिन जब शाम को वह अपने क्षेत्र लौट रहे थे तो देखा कि उस गांव में पुलिस का भारी जमावड़ा है। उन्होंने पूछा तो पुलिस के आईजी ने बताया कि आपने सदन में यह मुद्दा उठा दिया है, इसलिए मुझे आना पड़ा।

हंगामा भी दो तरह का होता है। एक सदन के अंदर किसी बात को लेकर दो पक्षों में वाद-विवाद बढ़ जाए तो वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंग माना जा सकता है। लेकिन जब राजनीतिक दलों के कार्यालयों में बैठकर अपने ही सांसदों और विधायकों से नारे लिखवाए जाएं, बैनर बनवाए जाएं और यह रणनीति बने कि कैसे किसको जवाब देना है तो यह पता चलता है कि हम किन लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर बढ़ रहे हैं। संसद की बैठक चलाने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों पर है, लेकिन सरकार पर कहीं ज्यादा। दूसरी तरफ विपक्ष को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि संसद में अपने मुद्दों के उठाने के अपने अधिकार को हाथ से न जाने दे। इससे तो सत्तापक्ष को ही लाभ होता है। संसद और विधानसभा में प्रश्न प्रहर में जो प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर देने के लिए मंत्रियों को तैयारी करनी पड़ती है। प्रश्न में उठाई गई समस्या को हल करवाना पड़ता है, लेकिन हंगामा होने पर मंत्री अपनी फाइल लेकर मुस्कुराते हुए सदन से बाहर चले जाते हैं और सदस्य ठगे से महसूस करते हैं। हंगामा और शोर-शराबा करने वाले कहते हैं कि हंगामा भी तो जनहित के कारण हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग शायद भूल रहे हैं कि संसद और विधानसभाएं चर्चा के लिए बनी हैं।

संवाद खत्म न हो

वैसे विशेष परिस्थितियों में सदन में गरमा-गरमी, हंगामा हो जाना और सदस्यों का वेल में जाना लोकतांत्रिक है लेकिन यह सीमित समय के लिए और बहुत जरूरी होने पर होना चाहिए। जब हम केवल इसी को अपना हथियार बना लेंगे तो चर्चा और संवाद खत्म हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि एक ऐसी आदर्श रूपरेखा तैयार की जाए, जिसमें असहमति होने पर गुस्सा दिखाने की गुंजाइश हो लेकिन सदन के कामकाज में बाधा डालने और जनता के हितों के

ऊपर अपनी राजनीति चमकाने की इजाजत ना हो। वरना लोकतंत्र के ये मंदिर उन लोगों के नाम से पहचाने जाने लगेंगे, जो हंगामा करते हैं काम नहीं होने देते।

धनखड़ का इस्तीफा

मानसून सत्र के पहले ही दिन जिस तरह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया, यह मामला भी सत्र के दौरान विवाद का विषय बना हुआ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा ने उनका उपयोग कर उन्हें पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। दरअसल, धनखड़ जिस तरह रातोंरात भाजपा नेताओं के निशाने पर आए, माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। जगदीप धनखड़ अच्छी तरह समझते होंगे कि अचानक भाजपा के निशाने पर क्यों आ गए। उनका हटाया जाना काफी हद तक पार्टी की विचारधारा की जड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जेपी नड्डा की कही हुई पार्टी की सक्षमता से जुड़ा हुआ है। उनके इस्तीफे में जो मेडिकल कारण बताया गया है, उसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। यह साफ है कि उन्होंने दबाव में आकर इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे की एक वजह नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को धनखड़ के न्यायपालिका के खिलाफ बयानों से असहजता थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? 2014 में मोदी सरकार द्वारा लाया गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कानून तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उस समय वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने इसे अनिर्वाचितों की तानाशाही कहा था, याद है? तब से लेकर अब तक भाजपा के सीनियर मंत्री और नेता देश की सबसे ऊंची अदालत पर सवाल उठाते रहे हैं। इसी साल अप्रैल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर धार्मिक युद्ध भड़काने और तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सिविल वॉर यानी गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया था। भाजपा के रणनीतिकारों की ओर से एक और तर्क ये दिया गया है कि धनखड़ सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने लगे थे, जिससे सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन इसके लिए उनके पास सिर्फ एक ही उदाहरण है- जब धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में किसानों से किए वादे पूरे न होने को लेकर सरकार से सवाल पूछे थे। उनका कहना है कि धनखड़ ऐसा शिवराज चौहान से कैसे कह सकते थे? ये सहानुभूति दिल को छूने वाली है, खासकर तब जब खुद शिवराज सिंह चौहान को मप्र में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया।

संसद में प्रत्येक मिनट के लिए 2.5 लाख खर्च

वर्तमान सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ और दो प्रमुख मुद्दे, जिनके कारण दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है (राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा में अधिक) बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जिसे विपक्ष ने सत्तारूढ़ गठबंधन को मदद करने का प्रयास बताया है, तथा विपक्षी दलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग, जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया थी। संसद के प्रत्येक सदन को प्रतिदिन छह घंटे तक उत्पादक होना चाहिए (भोजनावकाश के एक घंटे को छोड़कर) और, 2012 में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल के अनुसार, सत्र के दौरान संसद को एक मिनट चलाने पर 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है या लोकसभा और राज्यसभा के लिए 1.25 लाख रुपए का खर्च आता है। ये आंकड़े अब एक रूढ़िवादी अनुमान हैं, क्योंकि ये एक दशक से भी अधिक पुराने हैं, लेकिन अद्यतन आंकड़ों के अभाव में, हम आगे की गणना के लिए इन्हीं का उपयोग करेंगे। मानसून सत्र में तीन दिन हो चुके हैं, यानी हर सदन को 18 घंटे काम करना चाहिए था। हालांकि, गैर-लाभकारी संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, स्थगन के कारण राज्यसभा में 4.4 घंटे और लोकसभा में मात्र 0.9 घंटे या 54 मिनट ही काम हुआ है। इसका अर्थ यह है कि व्यवधानों के कारण करदाताओं को राज्यसभा के लिए 10.2 करोड़ रुपए (816 मिनट का नुकसान, 1.25 लाख रुपए से गुणा) तथा लोकसभा के लिए 12.83 करोड़ रुपए (1,026 मिनट का नुकसान, 1.25 लाख रुपए से गुणा) का नुकसान हुआ है। इस प्रकार, केवल तीन दिनों के व्यवधान से करदाता नागरिकों को 23 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

धनखड़ ने उस मौके पर किसानों के प्रति चिंता जताने से पहले सरकार की जमकर तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था, मैंने पहली बार भारत को बदलते देखा है, भारत कभी इतनी ऊंचाइयों पर नहीं था, जब ये सब हो रहा है, तो किसान क्यों परेशान हैं? धनखड़ की ये बात जनता को लुभाने जैसा लग रही थी। वैसे भी, यही एक मौका था जब उन्होंने सरकार को लेकर कुछ ऐसा कहा जो हल्की-फुल्की आलोचना मानी जा सकती है, लेकिन अब ये तर्क दिया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान की पीड़ा को 7 महीने बाद याद किया और उपराष्ट्रपति को हटाने का फैसला कर लिया।

शायद शिवराज सिंह चौहान इस इज्जत को पाकर खुशी से रो पड़ेंगे? या शायद वे खुद भी इस अचानक हुए बदलाव से हैरान होंगे। एक और वजह जो बताई जा रही है, वो ये कि धनखड़ ने सरकार से बिना सलाह लिए राज्यसभा में विपक्ष का वह प्रस्ताव पेश कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने की बात थी। सरकार चाहती थी कि ये सर्वदलीय प्रस्ताव पहले लोकसभा में पेश हो। लेकिन इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है? धनखड़ ने सिर्फ विपक्ष के प्रस्ताव का जिक्र किया था, जैसा कि किसी भी सभापति को करना चाहिए। उन्होंने उसे मंजूरी नहीं दी थी। इसी वजह से अब सरकार कह रही है कि वे पहले लोकसभा में प्रस्ताव लाएंगे। सरकार चाहती तो यही बात धनखड़ से सीधे मिलकर कह सकती थी, उन्हें हटाने की क्या जरूरत थी? एक और आरोप ये है कि धनखड़ विपक्ष के उस पुराने प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें जस्टिस शेखर यादव को उनके कथित नफरत भरे भाषण के लिए हटाने की मांग थी, लेकिन सोचिए अगर एक जज के खिलाफ लाए गए बाद के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में स्वीकार किया जा रहा है, तो फिर पहले से लंबित प्रस्ताव पर चुप कैसे रहा जा सकता था?

मुद्दे खूब उठे... अमल कितना?

मप्र के मानसून सत्र में इस बार विपक्ष ने जनहित के कई मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने जहां सदन के बाहर कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा किया, वहीं सदन के अंदर सरकार पर सवालों की झड़ी लगाई। विधानसभा के मानसून सत्र में अभी तक जनहित के मुद्दे तो खूब उठाए गए, लेकिन उन पर अमल कितना होगा यह तो भविष्य में पता चलेगा।

स्कूलों की मनमानी

विधानसभा में किताबों के वितरण और निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठा। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा कि इस साल किताब का प्रकाशन कराकर अप्रैल के पहले वितरण करने की व्यवस्था की है। अगले साल इस व्यवस्था में और सुधार किया जाएगा। अजय सिंह ने कहा कि निजी स्कूल साफ-साफ कह रहे हैं कि आपको इसी केंद्र से किताबें खरीदना है। ड्रेस खरीदना है। लूट मची हुई है। नियम बहुत बन जाते हैं, पर इसको ध्यान में रखना होगा कि अभिभावक से लूट न हो। उन्होंने यहां तक कहा कि मंत्री जी के भी नाती-पोते स्कूलों में पढ़ने जाएंगे तो उन्हें भी निजी स्कूलों की लूट का शिकार बनना पड़ेगा। मंत्री ने इस पर कड़े से कड़े नियम लागू करने और बच्चों के हित में फैसला लेने की बात कही।

कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने स्कूली बच्चों के बस्ते के बोझ का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि नियम सब बने हैं लेकिन उसका पालन भी होना चाहिए। जो पोर्टल बना है, उसमें शिकायत पर कार्रवाई न होने के लिए कहां शिकायत करना है? उसकी जानकारी भी नहीं है। एनसीईआरटी की किताबें पहली कक्षा से ही अनिवार्य करना चाहिए। बार-बार उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, ताकि अभिभावकों पर बार-बार किताबें खरीदने का बोझ न आए। विधायक अजय सिंह ने कहा कि पहले बड़े की किताबों से छोटा भाई पढ़ लेता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हर साल किताब बदलती है। अगर विद्यार्थी नई किताब नहीं खरीदते तो अभिभावकों को परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा। हम भावी पीढ़ी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अगर एनसीईआरटी की किताब लागू करने की अनिवार्यता नहीं है तो भी क्या प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती कि एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएं।

झूठे मुकदमे पर हंगामा

वहीं विधानसभा में कांग्रेस विधायकों पर झूठे मुकदमे दर्ज होने का सवाल भी उठाया गया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने वाणिज्य कर विभाग से संबंधित पत्रों को पटल पर रखने का काम शुरू कर दिया। इस पर कांग्रेस विधायक भड़क गए और सदन से वॉक आउट कर दिया। कांग्रेस विधायक चंदा गौर ने फरार आरोपी को नहीं पकड़े जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि छतरपुर पुलिस लाइन में दर्ज अपराध में पिछले 15 साल से आरोपी फरार हैं। सरकार अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। इस पर मंत्री शिवाजी पटेल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, आरोपी पर 8 हजार का ईनाम रखा है। लगातार अलग-अलग स्थानों पर तलाशी की गई है, आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। इस पर विधायक ने कहा कि पुलिस ही पकड़ ले तो ईनाम की राशि हम उसे दे देंगे, लेकिन पुलिस आरोपी को तो पकड़े। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जिस प्रकार सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पुलिस पर दबाव बनाकर केस बनवाए जा रहे हैं, ये स्पष्ट है कि भाजपा जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपको सदन के सदस्यों को संरक्षण देना पड़ेगा। नहीं तो हमें इनके विधानसभा क्षेत्रों में घेराव और आंदोलन करना पड़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ेगी तो सरकार जिम्मेदार होगी। नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरान कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा, सेना पटेल और आरिफ मसूद के मामले भी उठाए।

ड्रग माफिया को मंत्रियों का संरक्षण

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भोपाल में ड्रग्स और रेप के मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा- ड्रग्स का मामला पहली बार सामने आया था, तब उपमुख्यमंत्री से जुड़े लोगों का नाम उछला था। अब दूसरा केस आने पर मंत्री विश्वास सारंग के साथ ड्रग माफिया की फोटो सामने आ रही हैं। स्पष्ट है कि ड्रग माफियाओं को भाजपा नेता और मंत्रियों का संरक्षण है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यहां केवल आश्वासन देकर घोषणाएं की जा रही हैं। यदि इन्हें पुरस्कार दिया जाए आश्वासन और घोषणाओं में, तो पहला पुरस्कार मिलेगा। आज की ही बात है, हर चीज में आश्वासन दिए जा रहे हैं। अगर किसी ने यह सवाल पूछा कि कितनी घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ने की हैं तो उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कमलनाथ ने कहा कि यह आज न्याय का प्रश्न है। यह ओबीसी का प्रश्न नहीं है। मैं मानता हूं कि यह सामाजिक न्याय का प्रश्न है। इस पर कांग्रेस अपनी आवाज उठाती रहेगी। ओबीसी आरक्षण का आधा-अधूरा कानून लाने वाले मुख्यमंत्री के बयान पर कमलनाथ ने कहा- मैंने जो किया था, वह कोई छिपकर नहीं किया था, यह मामला तो आज पब्लिक में है।

विधानसभा में 2356 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

विधानसभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 के पहले अनुपूरक बजट को सदन में रखा। 2356 करोड़ के प्रस्ताव में प्रदेश में बारिश के कारण उखड़ी सड़कों के सुधार और नई सड़कों के निर्माण को लेकर मोहन यादव सरकार ने अपने पहले अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। वहीं पुलिस और कानून व्यवस्था, नगरीय विकास और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर भी मोहन सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गृह विभाग के लिए प्रस्तावित अनुपूरक बजट में केंद्र और राज्य में पुलिस बल की प्रतिपूर्ति के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही सरकार अपराध और अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था के लिए उपकरणों की खरीदी करेगी, जिसके लिए 57 करोड़ रुपए के अनुदान की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा कर उसे मंजूरी दी गई। लोक निर्माण विभाग के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें विशेष केंद्रीय सहायता योजना में बड़े पुलों का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपए, मुख्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए 40 करोड़ रुपए और नव से वित्त पोषण कर सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट की जरूरत बताते हुए अनुपूरक बजट में मांगे गए हैं। वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिए यूनिटी माल निर्माण करने 142 करोड़ के बजट की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है।

टीआरएफ आतंकी संगठन घोषित

पहलगाम में जब आतंकी हमले में निर्दोषों का रक्त बहा, आहें एवं चीखें गूंजी, जिसने न केवल देश एवं दुनिया को झकझोर दिया था, बल्कि यह संकेत भी दे दिया कि आतंकवाद की जड़ें अब भी जीवित हैं और उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और सीमा-पार समर्थन प्राप्त है। लेकिन इस बार एक बड़ा परिवर्तनकारी एवं प्रासंगिक कदम अमेरिका की ओर से सामने आया है, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मुखौटा इकाई द रेजिस्टेंट फ्रंट (टीआरएफ) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया, इस तरह टीआरएफ की पहचान और आतंक के विरूद्ध वैश्विक एकजुटता का नया अध्याय लिखा गया है।

यह कदम केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि आतंक के विरूद्ध वैश्विक मंच पर एक रणनीतिक संदेश है कि अब छद्म युद्ध और पनपते आतंक के विरूद्ध निर्णायक कार्यवाही का युग आ गया है। अमेरिका का यह कदम भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर के अंतरराष्ट्रीय प्रयास इस बात के द्योतक हैं कि आतंकवाद से निपटने के मोर्चे पर भारत सफल हो रहा है। अमेरिका के इस फैसले ने न सिर्फ टीआरएफ के आतंकी चेहरे से बेपर्दा किया है, बल्कि पाकिस्तान की उन नापाक हरकतों को भी बेनकाब कर दिया, जिन्हें वह खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताकर छिपाता आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे भारत-अमेरिका के बीच मजबूत आतंकवाद-रोधी सहयोग का प्रमाण बताया है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग की जरूरत पर बल दिया है।

टीआरएफ दिखने में एक स्थानीय कश्मीरी संगठन होने का भ्रम देता है, लेकिन असल में यह लश्कर-ए-तैयबा और उसके सरगना हाफिज सईद की पुरानी साजिश का नया चेहरा है। पाकिस्तान-समर्थित आतंकी संगठनों को नया नाम एवं नए रूप में प्रस्तुत करना पाक की एक साजिश एवं सोची-समझी रणनीति है, ताकि दुनिया के सामने वह अपने दामन को पाक-साफ दिखा सके। एक और विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि पाक ने इसे इस तरह पेश किया जैसे यह कश्मीर का स्थानीय संगठन हो। यह जगजाहिर है कि कई बड़े आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती से संचालित किए जा रहे हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिद्दीन प्रमुख हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार ये सवाल उठे और पाक को आतंक पोषित स्वीकार्य किया जाने लगा। उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने रणनीति बदली और आतंकी संगठनों के नाम भी बदलने शुरू कर दिए। टीआरएफ इसका एक उदाहरण है। इसका गठन 2019 के अनुच्छेद-370 के निरस्तीकरण के बाद हुआ और इसका उद्देश्य भारत में आतंकी घटनाओं को स्वदेशी विद्रोह की आड़ में अंजाम देना है। पहलगाम हमला भारत के उस प्रयास को चुनौती देता है जो वह पर्यटन और विकास के माध्यम से कश्मीर को मुख्यधारा में लाने के लिए कर रहा है। जब भी कश्मीर में शांति की बहार आती है, ऐसे आतंकी संगठन हिंसा का तूफान लेकर आते हैं। टीआरएफ ने सोशल मीडिया, इंटरनेट और कूटनीतिक शब्दजाल का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को कश्मीरी प्रतिरोध आंदोलन के रूप में पेश करने की कोशिश की, जबकि उसके तार रावलपिंडी और आईएसआई के आतंकवाद समर्थन तंत्र से सीधे जुड़े हैं। मगर, अमेरिका की ओर से इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना इस बात का सबूत है कि आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के इरादों को किसी छद्म नाम की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता।

अमेरिका द्वारा टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना भारत की एक बड़ी राजनयिक एवं कूटनीतिक सफलता है। यह दिखाता है कि भारत की तीक्ष्ण एवं ताकतवर विदेश नीति अब केवल घटनाओं की निंदा तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण की रणनीति पर आधारित है। जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्तावों को भी बल देती है। भारत पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद के विरूद्ध वर्षों से चेतावनी देते हुए दुनिया को आतंकमुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर विभिन्न देशों को आतंक के खिलाफ एकजुट करने के प्रयास तेज किए हैं।

● रजनीकांत पारे

आतंकवाद के विरूद्ध जीरो टोलरेंस पॉलिसी

आज आवश्यकता है कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक और शांति-प्रिय राष्ट्र एक मंच पर एकजुट होकर आतंकवाद के विरूद्ध जीरो टोलरेंस पॉलिसी अपनाएं। किसी भी राष्ट्र को, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, आतंकियों की शरणस्थली बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करना पहला कदम है, अब इसकी जड़ों को नष्ट करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। पाकिस्तान सरकार, सेना और आतंक के नापाक गठजोड़ पर जब तक सभी देश एकमत नहीं होंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचेगी। सवाल यह भी है कि जब पाकिस्तान आतंकी संगठनों का खुलेआम समर्थन करता रहता है तो उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट में डालने से परहेज क्यों किया जा रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के ताजा कदम के बाद एफएटीएफ और दूसरी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां टीआरएफ की फंडिंग की जांच करेंगी। पहलगाम का हमला एक बार फिर हमें चेतावनी देता है कि आतंकवाद केवल सुरक्षा का संकट नहीं, बल्कि सभ्यता, शांति और मानवता का अपमान है। हमें अब शब्दों से आगे बढ़कर संकल्प और कार्यवाही की ओर बढ़ना होगा। भारत को अब केवल प्रतिकार नहीं, बल्कि निर्णायक प्रहार की नीति अपनानी चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी एक ऐसे भारत में सांस ले सके जहां कश्मीर केवल खूबसूरती का पर्याय हो, आतंक का नहीं। भारत को वैश्विक मंचों पर टीआरएफ को बेनकाब करने की मुहिम जारी रखनी चाहिए, ताकि इस संगठन को फिर फन उठाने का मौका न मिले।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है कि 75 साल का मतलब रिटायर हो जाना, लेकिन ये तो उनके शब्द हैं ही नहीं। वे तो आरएसएस के दिवंगत नेता मोरोपंत पिंगले के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन करते हुए उनके एक वक्तव्य का उल्लेख कर रहे थे। स्पष्ट है कि इसके आधार पर यह कहना ठीक नहीं होगा कि संघ प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी को कोई राजनीतिक संदेश दे रहे थे। वैसे भी यदि मोदी 75 साल के होने वाले हैं तो खुद मोहन भागवत भी। संघ प्रमुख ने मोरोपंत पिंगले का स्मरण करते हुए यह भी कहा कि जब आपको 75 साल का होने पर शाल ओढ़ाया जाए तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। मोहन भागवत की ओर से जो कुछ कहा गया, उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वे किसके रिटायर होने को रेखांकित करना चाह रहे थे-राजनीतिक लोगों के अथवा गैर-राजनीतिक लोगों के। यह पहली बार नहीं है जब राजनीति से रिटायर होने की उम्र को लेकर कोई चर्चा छिड़ी हो। ऐसा पहले भी होता रहा है। अतीत में कई नेता 75-80 के बाद स्वेच्छा से राजनीति से रिटायर भी होते रहे हैं। ऐसे अनेक **नेता या तो समाजसेवा** में जुटे अथवा अध्ययन में। अब ऐसे नेता दुर्लभ ही हैं। ऐसे नेताओं के उदाहरण अधिक हैं जो रिटायर होने का नाम नहीं लेते।

राजनीति अथवा जीवन के किसी अन्य क्षेत्र से रिटायर होने की कोई उम्र सीमा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। यदि व्यक्ति विशेष सक्रिय है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पा रहा है और उसकी लोकप्रियता भी बनी हुई है तो वह अपना काम करते रह सकता है। राजनीति और अन्य क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं भी, जो 75-80 के बाद भी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। इसके साथ यह भी सही है कि कुछ नेता ऐसे भी हैं, जो राजनीति अथवा सत्ता का मोह छोड़ नहीं पाते। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई नेता राज्यपाल बने और फिर सक्रिय राजनीति में लौट आए। इसी तरह कुछ नेताओं ने खुद की राजनीतिक सक्रियता कम करने के पहले परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया। अपने देश में

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि नेताओं को 75 की उम्र में रिटायर हो जाने और युवाओं के लिए जगह खाली करने के बारे में सोचना चाहिए। आप यह मत सोचने लग जाइए कि उन्होंने कोई अवांछित बात कह दी है। वैसे कोई प्रतिक्रिया देने में सावधानी बरतना लाजिमी है, क्योंकि भाजपा-संघ रिश्तों के मामलों में नरेंद्र मोदी हमेशा अपवाद रहेंगे।

रिटायरमेंट का सवाल

व्यक्ति का प्रदर्शन उसकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर

मूलतः किसी व्यक्ति का प्रदर्शन उसकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। वास्तव में, उससे भी अधिक, यह उसकी मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, स्वस्थ लोगों में, मस्तिष्क का एक हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, उम्र बढ़ने से प्रभावित होता है। यह अध्ययन बताता है कि हर दस साल में पांच प्रतिशत मानव स्मृति खो जाती है, 30 वर्ष की आयु के बाद, व्यक्ति का प्रदर्शन धीरे-धीरे कम होने लगता है, और जैसे-जैसे व्यक्ति 70 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, ये प्रभाव अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। जैसे-जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, मस्तिष्क में श्वेत कोशिकाओं की कार्यक्षमता कम होती जाती है। इसीलिए भारत में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। बेशक, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में, राज्य सरकार के कर्मचारी की आयु 62 वर्ष है।

कई दल ऐसे हैं, जिनमें दूसरी-तीसरी पीढ़ी के बेटे-बेटियां, नाती-पोते आदि राजनीतिक रूप से सक्रिय और प्रभावी हो चुके हैं। ऐसा विकसित लोकतांत्रिक देशों में कम ही देखने को मिलता है। यह तथ्य है कि अपने देश में परिवारवाद की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इससे भी विचित्र यह है कि अब उसका बचाव किया जाने लगा है। वंशवादी राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं को पुष्ट करने का काम नहीं करती। अपने देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के नेता भी युवा कहलाते हैं और राजनीति में युवाओं की वैसी भागीदारी नहीं है, जैसी होनी चाहिए।

मोदी 17 सितंबर को 75 के हो जाएंगे, और इससे छह दिन पहले भागवत भी 75 के हो जाएंगे। इन संदर्भों के मद्देनजर भागवत के बयान को मोदी के लिए किसी संकेत के रूप में लेना उसमें कुछ ज्यादा पढ़ लेने जैसा होगा। गौर करने वाली बात यह है कि मराठी में दिए इस भाषण में भागवत ने सिर्फ 75 की उम्र में रिटायर होने वाली बात हिंदी में कही थी! 2005 में संघ प्रमुख सुदर्शन से मेरी दो किस्तों में बातचीत हुई थी, जिसमें सुदर्शन ने तब 77 के हो चुके आडवाणी और 80 के हो चुके वाजपेयी से युवाओं के लिए जगह खाली करने को कहा था। मैंने उन्हें याद दिलाया था कि वाजपेयी ने अपने रिटायर होने की अफवाहों को यह कहकर खारिज किया है कि न टायर्ड हूं, न रिटायर्ड हूं। उस समय भाजपा पर अटल-आडवाणी की जोड़ी की पकड़ मजबूत थी और उनकी कुर्सियों का कोई दावेदार नहीं था, इसलिए सुदर्शन की आलोचना हुई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। भाजपा-संघ के नजरिए से उनकी गलती सिर्फ यह थी कि उन्होंने गलत समय पर वह बयान दिया था। इससे पिछले साल ही पार्टी आम चुनाव में हार गई थी और उसे उस समय उत्तराधिकार के किसी संघर्ष में उलझना नहीं था। लेकिन उनके बयान ने रास्ता साफ कर दिया था। संभावित उत्तराधिकारियों की एक पूरी कतार उभरने लगी- राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और सबसे उल्लेखनीय, नरेंद्र मोदी। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व को लेकर अमेरिकी शैली की होड़ की शुरुआत करवा दी। 2012 में मोदी उस होड़ में आगे निकल गए।

विकसित देशों में भी उम्रदराज नेताओं की चर्चा

यह स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी उम्रदराज नेताओं के मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो रही है। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के प्रमुख दावेदार जो बाइडेन 2025 में 83 साल के हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप 79 साल के हैं, जो अमेरिका में सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र से दस साल ज्यादा है। उस समय राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन की बढ़ती उम्र की आलोचना तब हुई जब अमेरिकी विशेष वकील रॉबर्ट हार ने बाइडेन की फाइलों के प्रबंधन की साल भर चली जांच पर अपनी रिपोर्ट में उन्हें कमजोर याददाश्त वाला बूढ़ा आदमी बताया। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को गलत बताया। एक और रिपब्लिकन नेता, चक ग्रासली, 90 साल की उम्र में अमेरिका के सबसे उम्रदराज सीनेटर रहे जबकि एक और सीनेटर, बर्नी सैंडर्स, 84 साल के हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में कार्यरत जे मुरलीधरन के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो उम्र कोई मुद्दा नहीं होनी चाहिए। लेकिन, इस मुद्दे पर भी मतभेद हैं।

आप भाजपा-संघ को पसंद करते हों या नहीं, आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में उनका एचआर सिस्टम (मानव संसाधन व्यवस्था) सबसे मजबूत और योग्यतापरक है। भारत के राजनीतिक इतिहास में जितनी पार्टियां उभरीं, उनमें भाजपा ही ऐसी है, जिसमें न्यूनतम दलबदल हुआ है। कल्याण सिंह या येदियुरप्पा सरीखे कुछ नेता पार्टी से अलग हुए, लेकिन वापस भी लौटे। अलग होने वाले कुछ नेता बियाबान में खो गए, जैसे शंकरसिंह वाघेला या बलराज मधोक आदि। उन्हीं दशकों में कांग्रेस कई बार टूटी और कभी-कभी तो ऐसा लगा कि इससे टूटे गुटों के नाम में कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए वर्णमाला के अक्षर भी पूरे नहीं पड़ेंगे। जनता पार्टी, समाजवादी या लोक दल का भी यही हश्र हुआ।

भाजपा में कम-से-कम शीर्ष स्तर पर पारिवारिक उत्तराधिकार का भी कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। इसके जाने-माने संस्थापकों और वरिष्ठों के कई वंशज पार्टी में प्रमुख पदों पर बैठे हैं, लेकिन सत्ता हस्तांतरण से ज्यादा यह किसी के बच्चे को जगह देने जैसा मामला रहा। आप देख सकते हैं कि अटल-आडवाणी के दौर में भी काफी युवा मुख्यमंत्रियों को चुना गया- वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, नरेंद्र मोदी। इन सबकी औसत उम्र करीब 49 साल थी। युवा प्रतिभा की पहचान और उसे मजबूती देने का यह चलन भाजपा के अध्यक्ष के चयन के मामले में और उल्लेखनीय दिखता है। 2002 में वेंकैया नायडू 53 साल की उम्र में भाजपा अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह 54 की उम्र में, नितिन गडकरी 48 की उम्र में तो अमित शाह 49 की उम्र में अध्यक्ष बने। जबकि इस पूरी अवधि में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी रहीं। बीच में बहुत थोड़े समय के लिए राहुल गांधी अध्यक्ष बने और अब मल्लिकार्जुन खरगे हैं, जो 80 के हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस में कई युवा प्रतिभाएं मुरझा गईं। इन दोनों पार्टियों के एचआर सिस्टम पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

भाजपा में इस सिस्टम का 2014 के बाद भी पालन किया गया है। जेपी नड्डा ने 59 की उम्र में पार्टी की कमान संभाली। उसके नए मुख्यमंत्रियों पर नजर डालिए- योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, डॉ. मोहन यादव, विष्णुदेव साय, मोहन चरण मांझी, बिप्लब देब, हिमंत बिस्वा सरमा, मनोहरलाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस, प्रमोद सावंत, पुष्कर सिंह धामी, रेखा गुप्ता- इन 12 नेताओं ने जब कुर्सी संभाली तब उनकी औसत उम्र 51 साल थी।

कांग्रेस ने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कुछ युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन यह कर्नाटक में सिद्धारमैया पर ही अटकी हुई है। उल्लेखनीय यह भी है कि संघ स्वयं अपनी सलाह पर अमल करता है। अब तक उसके सरसंघचालकों की अधिकतम उम्र 78 साल ही रही है। हेडगेवार और गोलवलकर का क्रमशः 51 और 67 की उम्र में ही निधन हो गया था। सभी सरसंघचालक युवावस्था में ही शीर्ष तक पहुंचे और भागवत की तरह सबका कार्यकाल लंबा रहा। हकीकत यह है कि तमाम अफवाहों और कानाफूसियों के बावजूद भाजपा के अंदर किसी ने ऐसे किसी नियम का मुद्दा नहीं उठाया है कि 75 की उम्र रिटायर्ड होने की उम्र है। इसके बारे में कानाफूसी आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि को मार्गदर्शक मंडल यानी संन्यास में भेजने के औचित्य के रूप में ही की गई थी। इसी के साथ कलराज मिश्र और नजमा हेपतुल्ला सरीखे नेता मंत्री बने रहे। बाद में उन्हें राज्यपाल बना दिया गया।

पिछले लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी को 75 की उम्र पार करने के बाद भी मथुरा से शायद यह जताने के लिए उम्मीदवार बनाया गया कि पार्टी में 75 की उम्र वाला कोई नियम लागू नहीं है। एकमात्र औपचारिक बयान आनंदीबेन पटेल का है, जिन्होंने 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का यह कारण बताया था कि मैं 75 की हो चुकी हूं। लेकिन यह निश्चित रूप से मोदी के लिए कोई मिसाल नहीं है। मोदी 2029 का चुनाव तो निश्चित रूप से लड़ना चाहेंगे। तब उनकी उम्र केवल 79 साल होगी, जितनी आज ट्रम्प की है। बाकियों को उनके फैसले या संकेत का इंतजार करना पड़ेगा, चाहे भाजपा के अंदर उम्मीदवार चुनने की कोई गुप्त प्रक्रिया क्यों न शुरू हो चुकी हो।

मुद्दा यह है कि राजनीतिक नेताओं को एक निश्चित उम्र में सेवानिवृत्त होकर युवाओं को मौका देना चाहिए। वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और युवाओं की गतिशीलता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन चुनावी टिकट आवंटन में यह बात नजर नहीं आती। कई उम्रदराज नेता कुर्सी, सत्ता और धन-दौलत को थामे रखने के मोह में रहते हैं। एक विचार यह भी है कि राजनीतिक दल टिकट वितरण के दौरान 30-45 वर्ष की आयु के युवक-युवतियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दें। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये राजनीतिक सुधार असंभव नहीं हैं।

● **विपिन कंधारी**

देश में मतदाताओं, प्रत्याशियों और दलों की विशाल संख्या, चुनावों की बारंबारता, प्रक्रियाओं की जटिलता, तकनीकी-प्रशासकीय चुनौतियां, सांप्रदायिक और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता आदि को समायोजित कर अत्यधिक मेहनत से संपन्न की जाने वाली कठिन चुनाव प्रक्रिया पर नेता और राजनीतिक दल एक मिनट में कालिख पोत देते हैं। यह अक्षम्य अपराध है।

बेसुरा राग हानिकारक

मतदाता सूची के सत्यापन पर शोर

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के पहले चुनाव आयोग ने राज्य में मतदाता सूची के सत्यापन अर्थात् पुनरीक्षण की जो पहल की, उस पर कांग्रेस, राजद समेत अनेक विपक्षी दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया। इन दलों ने यह बताने की कोशिश की कि चुनाव आयोग कोई अनुचित, अनावश्यक और असंवैधानिक काम कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मोदी सरकार पर भी तमाम आरोप लगाए। उनके हिसाब से चुनाव आयोग मतदाता सूची का सत्यापन मोदी सरकार के कहने पर कर रहा है और उसका इरादा किसी न किसी प्रकार भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाना है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की इस पहल को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हुई तथाकथित हेराफेरी से भी जोड़ा। वह बार-बार यह घिसा-पिटा आरोप दोहरा रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए धांधली करवाई। इन आरोपों का चुनाव आयोग ने विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन राहुल गांधी और उनके साथ कई विपक्षी नेता सच का सामना करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। साफ है कि उनके साथ कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं कि उनकी राजनीतिक जमीन कमजोर हो रही है और इसके लिए वे चुनाव आयोग पर दोष मढ़कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। मतदाता सूची का सत्यापन कोई नई बात नहीं है।

भारतीय लोकतंत्र और संविधान प्रारंभ से ही अनेक झंझावातों से गुजरा है। शुरू में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा, शरणार्थी-पुनर्वास, औपनिवेशिक मानसिकता, पाकिस्तान एवं चीन विवाद आदि से विदेशी विद्वानों को लगता था कि भारत में लोकतंत्र और संविधान ढह जाएगा। भारत की जनता, सरकार और विपक्ष ने उन्हें गलत साबित किया। आज स्थिति विचित्र है। विपक्षी दल सतारूढ़ भाजपा-राजग को अपदस्थ करने हेतु न केवल उस पर आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं, वरन देश की संवैधानिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और संविधान को ही लांछित करने का प्रयास करते हैं। यह लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार करने जैसा है। संविधान, संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक प्रक्रियाएं लोकतंत्र की आत्मा हैं।

विपक्षी दल इन पर लगातार आक्रामक हैं। नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता संविधान की प्रति लहराकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे संविधान खतरे में है और उन्हें उसे बचाना है। संविधान में संशोधन करने और उसके खतरे में होने में बहुत फर्क है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि सरकार-संसद संविधान में बदलाव या संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल-ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जो नेता संविधान की दुहाई देते हैं, वे स्वयं संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। इसमें सभी दलों के नेता शामिल हैं। साफ है कि किसी के भी द्वारा संविधान नष्ट या उसके खतरे में होने और लोकतंत्र के लिए संकट खड़े हो जाने की बात करना भ्रम फैलाना और संविधान की अस्मिता पर आक्रमण जैसा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बार संविधान को केवल बदलने का ही नहीं, वरन नष्ट करने का भी प्रयास किया।

1959 में प्रधानमंत्री नेहरू ने केरल में नंबूदरीपाद की निर्वाचित वामपंथी सरकार को अकारण भंग कर अनुच्छेद-356 का मनमाना इस्तेमाल किया। जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने हेतु अनुच्छेद-352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया तथा लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर हजारों नेताओं एवं बेगुनाह लोगों को मीसा और डीआईआर जैसे कठोर कानूनों के अंतर्गत जेल भेज दिया। इनमें अपील, दलील और वकील का प्रविधान ही नहीं था। अनेक दलों के नेता, जिन्हें कांग्रेस ने आपातकाल में जेलों में ठूंस दिया था, वे भी मोदी विरोध के चलते आज उसी कांग्रेस के साथ खड़े दिखते हैं। आपातकाल में अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। उसी दौरान कांग्रेस ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कुछ बड़े बदलाव किए और ऐसे प्रविधान जोड़े, जिसे संविधान-निर्माताओं ने अस्वीकार कर दिया था। इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय तक को नहीं छोड़ा और तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तियों की उपेक्षा कर न्यायमूर्ति एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था।

विपक्ष काफी समय से संवैधानिक संस्थाओं और खासकर चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। चूंकि चुनाव ही सत्ता की सीढ़ी है, इसलिए लोकसभा चुनाव में परास्त होने और अनेक राज्यों में अप्रासंगिक होने से चुनाव आयोग पर आरोप तथा लांछन लगाना विपक्ष के लिए काफी आसान हो गया है। कभी वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों और निर्णयों पर अंगुली उठाता है, कभी उसे भाजपा के इशारे पर काम

करने वाला बताता है, कभी ईवीएम, मतदाता सूची में अनियमितता, डाटा देने में विलंब, दलीय पक्षपात आदि का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग की छवि नष्ट करने का प्रयास करता है। अनेक राज्यों में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार आदि के अवैध घुसपैठियों ने फर्जी तरीकों से आधार, पैन, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज प्राप्त कर कई निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता-सूचियों में अपना नाम अंकित करा लिया है। यह लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि केवल भारतीय नागरिकों को ही मत देने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने इस पर अपना रुख सख्त करते हुए सभी राज्यों में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का निर्णय लिया है। बिहार में वह ऐसे लोगों की पहचान संबंधी पहल कर चुका है, पर विपक्ष को इस पर आपत्ति है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी। न्यायालय ने आयोग की इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। देखना है कि न्यायालय इस पर क्या अंतिम निर्णय लेता है?

राहुल गांधी तो विदेश में भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। गत अप्रैल में उन्होंने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भारतीय चुनाव प्रणाली पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया और विशेष रूप से महाराष्ट्र में मतदाता सूची में अनियमितताओं का जिक्र किया। जब नेता-प्रतिपक्ष ही लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर विदेश में ऐसे अनर्गल आरोप लगाएगा, तो न केवल भारतीय लोकतंत्र की वैश्विक छवि खराब होगी, वरन जनता के मन में भी शंका उत्पन्न होगी। देश में मतदाताओं, प्रत्याशियों और दलों की विशाल संख्या, चुनावों की बारंबारता, प्रक्रियाओं की जटिलता, तकनीकी-प्रशासकीय चुनौतियां, सांप्रदायिक और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता आदि को समायोजित कर अत्यधिक मेहनत से संपन्न की जाने वाली कठिन चुनाव प्रक्रिया पर नेता और राजनीतिक दल एक मिनट में कालिख पोत देते हैं। यह अक्षम्य अपराध है।

संभव है कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ अधिकारी, कर्मचारी किसी निर्वाचन क्षेत्र में गलती करें, कुछ क्षेत्रों में जाने-अनजाने कोई त्रुटि हो, कुछ मतदाता सूचियों में कहीं अनियमिताएं भी दिखें, लेकिन चुनाव आयोग उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करता है और चिह्नित लोगों को विधि अनुसार दंड भी देता है, लेकिन विपक्ष द्वारा संविधान, संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को लांछित करना अनुचित और अवांछनीय है। यदि विपक्षी दलों ने लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति आक्रामक रवैया नहीं छोड़ा, तो जनता की आस्था लोकतंत्र और संविधान में घट सकती है जो लोकतंत्र, सत्तापक्ष और विपक्ष सभी के लिए हानिकारक होगी।

इससे विचित्र और हास्यास्पद और कुछ नहीं कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल एक ओर जोर-शोर से यह दावा करने में लगे हैं कि उनके गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 295 सीटें मिल रही हैं और दूसरी ओर उनके नेता मतगणना में गड़बड़ी की निराधार आशंकाएं जताकर भ्रम फैलाने में लगे हैं। भ्रम फैलाने की इसी कोशिश के तहत कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह अनर्गल दावा कर दिया कि मतगणना को प्रभावित करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने देश के 150 जिलों के जिलाधिकारियों को फोन किया है।

उन्होंने यह बेतुका आरोप लगाते हुए यह समझा होगा कि इससे उन्हें एक फर्जी नैरेटिव खड़ा करने में मदद मिलेगी, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें यह नोटिस जारी कर उनका खेल खराब कर दिया कि अपने आरोपों के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करें। स्पष्ट है कि वह ऐसा करने से रहे। चुनाव आयोग को ऐसे अनर्गल आरोपों के खिलाफ और अधिक सख्त रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेता उसे बदनाम करने का सुनियोजित अभियान छेड़े हुए हैं। इसी के तहत मतदान प्रतिशत के अंतरिम और अंतिम आंकड़ों को लेकर व्यर्थ की चीख-पुकार मचाई गई। इसके बाद यह हल्ला मचाया जाने लगा कि मतगणना के तौर-तरीकों में बदलाव किया जा रहा है। यह भी अफवाह फैलाई गई कि प्रत्याशियों के एजेंटों को मतगणना स्थल के करीब नहीं फटकने दिया जाएगा। जब इससे बात नहीं बनी तो यह कहा जाने लगा कि चुनाव आयोग ने पुरानी परंपरा का परित्याग करते हुए डाक मतपत्रों को बाद में गिनने का फैसला किया है। इसे तूल देने के लिए विपक्षी नेता चुनाव आयोग के दरवाजे तक भी पहुंच गए, लेकिन यह आरोप भी हवा-हवाई ही साबित हुआ, क्योंकि आयोग ने यह स्पष्ट किया कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले की तरह होगी।

विपक्षी नेताओं की इन हरकतों से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि वे अपनी संभावित हार का ठीकरा चुनाव आयोग, मीडिया आदि पर फोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक्जिट पोल के नतीजों को न केवल अस्वीकार कर दिया, बल्कि उन्हें भाजपा प्रायोजित भी करार दिया। एक्जिट पोल को लेकर कांग्रेस इतनी दुविधाग्रस्त थी कि पहले उसने टीवी चैनलों पर होने वाली चर्चा का बहिष्कार करने का फैसला किया और फिर फजीहत होती देखकर उसमें शामिल होने का निर्णय लिया। यह वही कांग्रेस है जिसने कुछ माह पहले तेलंगाना के एक्जिट पोल नतीजों को खुशी-खुशी स्वीकार किया था और यह उम्मीद जताई थी कि नतीजे उन्हीं के अनुरूप रहेंगे। इस बार विपक्षी दलों को न तो एक्जिट पोल पर भरोसा है और न चुनाव आयोग पर। हैरानी नहीं कि नतीजे आते ही वे जनता पर भी भरोसा करना छोड़ दें। यदि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो उसके दुर्दिन खत्म होने में और भी अधिक समय लगेगा।

● इन्द्र कुमार

22 साल पहले हुआ था मतदाता सूची का सत्यापन

बिहार में ही इसके पहले 2003 में मतदाता सूची का सत्यापन हुआ था। अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी मतदाता बढ़े हैं। बिहार के लाखों लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर जाते हैं और कुछ तो वहीं स्थाई रूप से बस जाते हैं। इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ से पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ-साथ झारखंड और बिहार भी प्रभावित हैं। मतदाता सूची के सत्यापन से न केवल बिहार के वैध-वास्तविक मतदाताओं का पता चलेगा, बल्कि इसकी भी जानकारी हो सकेगी कि कहीं अवैध बांग्लादेशी बिहार में मतदाता तो नहीं बन गए हैं? आखिर जब वे बंगाल में बन सकते हैं तो बिहार में भी इसकी आशंका है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का सत्यापन निष्पक्ष चुनाव की बुनियादी शर्त है।

फोर्स पर ड्रोन से नजर...

केंद्र सरकार का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन मिशन-2026 को फेल करने अब नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी ने भी नई रणनीति बनाई है। इसका जिक्र नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी की तरफ से जारी 22 पन्नों के बुकलेट में किया गया है। बुकलेट के जरिए देश के कई राज्यों के नक्सलियों को मिशन 2026 को फेल करने के लिए नक्सल सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो की बनाई गई रणनीति पर ट्रेनिंग लेने को कहा गया है। इसमें लंबी यात्राएं, भूखे रहना और फोर्स का घेरा तोड़ने समेत कई रणनीतियां शामिल हैं। नक्सल सेंट्रल कमेटी की बुकलेट में लिखी साजिश के मुताबिक, नक्सलवाद खत्म करने के सरकारी मिशन को नाकाम करने के लिए नक्सली हाईटेक ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब नक्सलियों की क्या प्लानिंग है? क्या वो फोर्स पर कोई बड़ा हमला करने वाले हैं? इस पर अभी संशय बना हुआ है।

वहीं छत्तीसगढ़ में जवानों के मूवमेंट पर नक्सली ड्रोन से नजर रख रहे हैं। 2018 से नक्सलियों के पास करीब 10 ड्रोन हैं, जिनकी रेंज 3 किलोमीटर है। इन ड्रोन्स को उड़ाकर वह जवानों की मौजूदगी देखते हैं। कम जवान हों तो हमला करते हैं, ज्यादा हों तो भाग जाते हैं। पुलिस को नक्सलियों के ड्रोन की जानकारी 7 साल बाद लग सकी है। सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि पुलिस ने नक्सलियों के ठिकानों से 23 फरवरी 2025 को एक ड्रोन भी जब्त किया है। एनआईए इसकी जांच में शामिल है। आखिर नक्सलियों के खिलाफ एनआईए से छत्तीसगढ़ पुलिस को क्या जानकारी मिली है? ड्रोन सप्लाई के तार कहां-कहां से जुड़े है?

दरअसल, 23 फरवरी को बस्तर के सुकमा जिले के गुंडराजगुडेम जंगल से पुलिस अफसरों ने सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के ठिकाने से दैनिक सामग्री के साथ ड्रोन बरामद किया था। अफसरों ने इस बात की पुष्टि की है। सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि लंबे समय से गुंडराजगुडेम जंगल में पुलिस कैंप और उसके आसपास के इलाकों में संदिग्ध ड्रोन देखे जाते थे। इसके बाद टीम ने मुखबिर के बताए ठिकानों पर जाकर जांच की, तो दैनिक सामग्री के साथ ड्रोन और उसके कुछ पार्ट्स मिले थे। यह पहली बार हुआ कि अफसरों ने ड्रोन को बरामद किया। सुकमा एसपी के मुताबिक गुंडराजगुडेम जंगल से जिस ड्रोन को जब्त किया है, उस ड्रोन में कोई सामान ले जाने (दवा, बारूद, बम) की क्षमता नहीं है। इस ड्रोन की रेंज 3 किलोमीटर दायरे की है। जैसा ड्रोन पुलिस अफसरों ने बरामद किया, वैसा ड्रोन कार्यक्रमों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

नेशनल इन्वेस्टिंगेशन एजेंसी (एनआईए) से छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जून 2024 में नक्सलियों द्वारा ड्रोन इस्तेमाल किए जाने का इनपुट मिला था। एनआईए ने छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को यह इनपुट तेलंगाना पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सलियों के तीन सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद दिया था। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अनुसार, ड्रोन सप्लाई करने और नक्सलियों को ट्रेनिंग देने के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपियों में से एक छत्तीसगढ़ के बीजापुर का रहने वाला है। इन आरोपियों ने तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को ड्रोन सप्लाई किए थे। नक्सली ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी खबरें पहले भी आती रही हैं। 2019, 2020 और 2023 में ड्रोन देखे जाने की खबरें वायरल हुईं, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की। 2019 में केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में किसी भी संदिग्ध ड्रोन को मार गिराने के निर्देश भी जारी किए थे।

एनआईए ने 29 जून को दिल्ली से नक्सलियों को ड्रोन सप्लाई करने वाले आरोपी को पकड़ा था। मथुरा निवासी आरोपी विशाल सिंह ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वह पिछले सात साल से घने जंगलों में ड्रोन की सप्लाई और ट्रेनिंग दे रहा था। अधिकारियों ने पुष्टि की कि सीपीआई (माओवादी) उत्तरी क्षेत्र ब्यूरो (एनआरबी) को एक्सपर्ट बनाने के मुख्य आरोपी विशाल सिंह ने बिहार के छकरबंदा-पचरुखिया वन क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन के नेताओं को ड्रोन दिए थे।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मामले की छानबीन कर रही है और विशाल सिंह की सीपीआई (माओवादी) से कथित रूप से जुड़े संपर्कों की जांच कर रही है। एजेंसी की ओर से तलाशी के दौरान जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और डाटा की बारीकी से जांच की जा रही है, जिससे संगठन की रणनीतियों और गतिविधियों का खुलासा हो सके। इससे पहले अगस्त 2024 में एनआईए ने एक अन्य आरोपी अजय सिंघल उर्फ अमन को गिरफ्तार किया था, जो माओवादी संगठन के हरियाणा और पंजाब इकाई का प्रमुख माना जाता है।

● रायपुर से टीपी सिंह

बस्तर में मारे गए 426 से ज्यादा नक्सली

बस्तर में 1 जनवरी 2024 से जून 2025 तक हुई अलग-अलग मुठभेड़ों में 426 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस के मुताबिक, इनमें 2024 में 217 नक्सली और पिछले 6 महीने में 200 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। वहीं नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के नाम से जारी इस बुकलेट में लिखा है कि सालभर में नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर और नक्सल संगठन के महासचिव बसवा राजू समेत सेंट्रल कमेटी के 4 सदस्य, स्टेट कमेटी के 16 सदस्य मारे गए हैं। इन 357 में 136 महिला नक्सली भी मारी गई हैं। सबसे ज्यादा दंडकारण्य में 281 नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों के बुकलेट के मुताबिक लगातार हो रही क्षति के बाद अब नक्सल संगठन के लड़ाके कुछ बारीकियों को सीख रहे हैं। जैसे मुठभेड़ के दौरान कमान संभालना, नए तरीके और युद्धाभ्यास, घेरा तोड़ने की तकनीक, कई घंटों और कुछ दिनों तक भूख सहन करना और लंबी यात्राएं करना, इसका अभ्यास किया जा रहा है। नक्सल केंद्रीय कमेटी का कहना है कि, 2024 से लेकर अब तक हुए नुकसान की समीक्षा की गई है। सेंट्रल कमेटी ने पहले कुछ रणनीतियां बनाई थीं, जिस पर काम नहीं होने से संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। अब सरकार के मिशन 2026 को फेल करने राजनीतिक और सैन्य की रणनीतियां बनी हैं। इस पर काम किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में बदल रही राजनीति!

महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार और विपक्ष के तेवर पिछले दिनों से बदले-बदले नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को धन्यवाद दिया। ये धन्यवाद कॉफी टेबल बुक में की तारीफ के लिए था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं, दुश्मन नहीं हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गत दिनों अपने जन्मदिन पर जारी एक कॉफी टेबल बुक में एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे वैचारिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार एक बड़े दिल वाले और सीनियर नेता हैं। उनकी टिप्पणियां मेरे लिए अमूल्य हैं।

84 वर्षीय पवार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब वे फडणवीस को देखते हैं, तो उन्हें वह समय याद आता है जब वे स्वयं 1978 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। पवार जब मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी उम्र सिर्फ 38 वर्ष थी, जिससे वे राज्य के शीर्ष पद पर आसीन होने वाले सबसे कम उम्र के राजनेता बन गए थे। उन्होंने कहा कि फडणवीस की राज्य प्रशासन पर उनकी मजबूत पकड़ है। मजाकिया अंदाज में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने शरीर की तुलना फडणवीस से करते हुए कहा कि भारी होने की समानता कभी भी कड़ी मेहनत करने में बाधा नहीं बनी है। मुझे आश्चर्य है कि वे थकते कैसे नहीं हैं। शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुक में अपने लेख में फडणवीस को एक अध्ययनशील और लोयल राजनेता बताया है, जिन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को मजबूत करने में सफलता प्राप्त की है, जो कभी कांग्रेस का गढ़ था। शिवसेना (यूबीटी) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने लिखा है कि फडणवीस के पास राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने का मौका है और उन्होंने उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। महाराष्ट्र के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में 44 साल की उम्र में पहली बार बड़ा पद संभाला था, जिससे वह पवार के बाद महाराष्ट्र के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए।

महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से राजनीति के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पिछले दिनों विधान भवन में उद्धव की वापसी को लेकर बात कही थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई थी। यही कारण है कि महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा देशभर में हो रही हैं। राजनीतिक जानकारों की मानें तो इस समय कुछ न कुछ तो पक रहा है, जिसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के वरिष्ठ नेता और विधायक आदित्य ठाकरे की मुंबई के एक ही होटल में एक साथ मौजूदगी राजनीतिक गलियारों में नए गठजोड़ को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार, फडणवीस और आदित्य ठाकरे अलग-अलग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए होटल पहुंचे थे और उनकी आपसी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि, उनकी एक ही स्थान पर उपस्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चा गर्म हो गई है, खासकर ऐसे समय में जब पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकातें हो चुकी हैं। इससे दो दिन पहले ही विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कक्ष में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि भाजपा और शिवसेना (ठाकरे गुट) के बीच एक बार फिर से समीकरण बन सकते हैं। उस मुलाकात को लेकर सफाई देते हुए फडणवीस ने कहा था, मैंने उद्धव ठाकरे द्वारा लिखी गई किताब हिंदी सक्ती हवीच कशाला पढ़ी थी और इसी क्रम में उनसे मुलाकात हुई। किसी से मिलना गठबंधन की पुष्टि नहीं करता।

हालांकि, इस सबके बीच सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल उस समय हुई जब देवेंद्र फडणवीस ने सार्वजनिक मंच से उद्धव ठाकरे को सत्ता में आने का रास्ता खुला होने की बात कही। उन्होंने कहा था, उद्धवजी, 2029 तक आपके पास सत्ता में आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर आप सरकार में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। हम अलग तरीके से बातचीत करेंगे। ठाकरे गुट की शिवसेना आज भी हमारी मित्र पार्टी है। इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सभागृह में हुई बातों को सौहार्दपूर्ण भावना से लिया जाना चाहिए। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह घटनाक्रम महज संयोग नहीं है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से फिलहाल इसे सिर्फ औपचारिक या अनौपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से समीकरण तेजी से बदलते रहे हैं, उसे देखते हुए इन मुलाकातों को नजरअंदाज करना आसान नहीं।

● **बिन्दु माथुर**

2019 से भाजपा-ठाकरे गुट में दूरी

भाजपा और ठाकरे गुट के बीच संबंध 2019 विधानसभा चुनावों के बाद टूट गए थे, जब शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी। उसके बाद से दोनों दलों के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे हैं, लेकिन अब हालिया घटनाओं ने नए राजनीतिक समीकरणों की संभावना को जन्म दे दिया है। क्या यह फिर से भाजपा-शिवसेना (ठाकरे गुट) की नजदीकियां हैं, या महज एक संयोग? इसका उत्तर आने वाला समय देगा। फिलहाल, महाराष्ट्र की राजनीति में इस घटनाक्रम से हलचल बढ़ गई है। 5 जुलाई को जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल के बाद एक साथ एक मंच पर साथ आए और हाथ मिलाया था। उसके 5 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की एक मुलाकात दो घंटों के लिए बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में भी हो चुकी थी। उसके बाद ही फडणवीस को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान में नरमी दिखाई देनी शुरू हुई। अब ये आगे बहुत कुछ राजनीतिक हलचल के भी संकेत दे रही है।

गरीबों का राशन डकार गए कर्मचारी

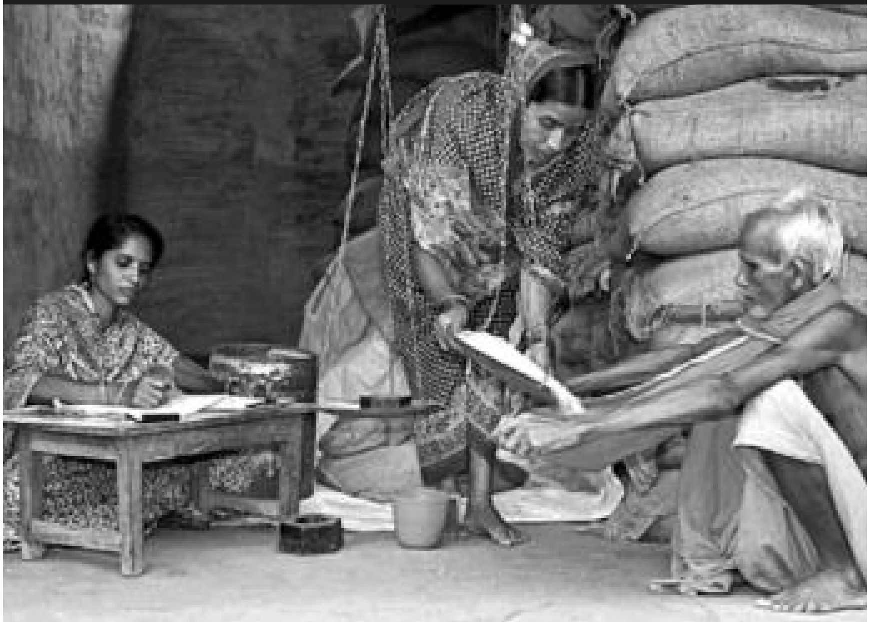

राजस्थान के 83 हजार सरकारी कर्मचारी-अधिकारी 5 साल में गरीबों का करोड़ों रुपए का गेहूं खा गए। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे अपात्रों से 82 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई है। योजना को आधार से लिंक करने के बाद जब पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। लाखों रुपए की सैलरी उठाने वाले ही गरीबों का राशन डकार रहे हैं। प्रदेश के 40 जिलों के 83 हजार 679 अधिकारी-कर्मचारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया गया है। इस मामले में दौसा जिला टॉप पर है, जहां 7 हजार से ज्यादा सरकारी अधिकारी-कर्मचारी राशन उठा रहे थे। भरतपुर द्वितीय और उदयपुर द्वितीय में एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं मिला है। इन सरकारी कार्मिकों ने गेहूं दो रुपए किलो में लिया था, लेकिन इसे सरकार ने गेहूं की बाजार कीमत 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति देती है। हालांकि, कैग की आपत्ति के बावजूद वसूली गई 82 करोड़ से ज्यादा की यह राशि केंद्र सरकार को लौटाई नहीं गई है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी और चौमूं में एक दर्जन से अधिक ऐसे सरकारी शिक्षक हैं, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठाया है, जबकि वे इसके पात्र नहीं थे। इनमें से एक हैं ग्रेड थर्ड शिक्षक रामफूल। वह बस्सी का रहने वाला है। रामफूल ने 4 साल तक 2 रुपए प्रति किलो की दर से गरीबों का राशन उठाया। अब उससे बाजार दर 27 रुपए किलो के हिसाब से करीब 1 लाख रुपए की वसूली की गई है। अलवर जिले के राजगढ़ में सरकारी कर्मचारी हरिराम मीणा ने पात्र नहीं होने के बावजूद गरीबों को मिलने वाला गेहूं उठा लिया। विभाग ने पहले नोटिस दिया और लगभग डेढ़ लाख रुपए की रिकवरी की है। हजारीलाल राजगढ़ का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है। लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो गेहूं ले रहा था। रिकॉर्ड के अनुसार हजारीलाल ने करीब 65 किलो गेहूं लिया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पहले नोटिस दिया उसके बाद रिकवरी की।

खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी कार्मिकों के पात्र बनकर गेहूं उठाने की शिकायतों के बाद साल 2020 में राज्य सरकार ने जिला रसद अधिकारियों से जांच कराई थी। तह तक जांच के लिए योजना को आधार से लिंक किया गया। इसके बाद जांच में महीने की लाखों रुपए सैलरी उठाने वालों के नाम सामने आए। विभाग के निर्देश पर आधार से वैरिफिकेशन के बाद ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों से वसूली शुरू की गई। 2020 से मई 2025 तक करीब 82 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सरकार बीपीएल, एपीएल, स्ट्रीट वेंडर्स, समेत कुछ अन्य वर्ग को मुफ्त अनाज गेहूं देती है। इससे जुड़े हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूं 2 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह दिया जाता है। यह अधिनियम 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार के समय लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के हर गरीब व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा की गारंटी देना था।

राजस्थान में भरतपुर द्वितीय और उदयपुर द्वितीय ही ऐसे जिले हैं, जहां का एक भी अधिकारी-कर्मचारी की लिप्तता सामने नहीं आई है। गरीबों के गेहूं डकारने वालों में दौसा सबसे टॉप जिला है। यहां करीब 8 हजार सरकारी कर्मचारी ऐसे पाए गए जो इस योजना का गलत तरीके से लाभ ले रहे थे। बांसवाड़ा इस मामले में दूसरे नंबर पर है। खास बात यह है कि 82 करोड़ से ज्यादा की राज्य सरकार ने जो वसूली की है, वह राशि भारत सरकार की है। यह राशि वित्त विभाग में अटकी हुई है। कैग की आपत्ति के बावजूद यह राशि राज्य सरकार ने अभी तक भारत सरकार को नहीं दी है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के मुताबिक, राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में 4 करोड़ 46 लाख 61 हजार 960 लोगों के लिए गेहूं का आवंटन केंद्र सरकार से होता है। वर्तमान सूची में 4 करोड़ 34 लाख 98 हजार लोग गेहूं ले रहे हैं। हाल ही में सरकार ने नए नाम भी जोड़े हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों से वसूली लगातार की जा रही है। इस मामले में नोटिस भी जारी किए गए हैं। बकाया जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पैसा भारत सरकार को देंगे या नहीं? सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा- यह हमारे और भारत सरकार के बीच का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 किलो गेहूं टाइम पर मिल रहा है और उच्च गुणवत्ता का गेहूं मिल रहा है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

गिवअप स्कीम में 23 लाख लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा

गिवअप अभियान के तहत अब तक 23 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाया है। राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2024 को यह अभियान शुरू किया था ताकि जो लोग अब सक्षम हैं, वे योजना से बाहर हो जाएं ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि राज्य में 4.46 करोड़ लोग ही इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अपात्र लोग योजना का लाभ उठा रहे थे। अकेले जयपुर जिले में ही 2 लाख लोगों ने योजना से नाम हटाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिन 27 लाख लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, वे भी योजना से स्वतः बाहर हो गए। सुमित गोदारा ने बताया कि पात्र लोगों को योजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 26 जनवरी से खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से शुरू किया था, तब से लेकर अब तक 51 लाख नए लाभार्थी योजना में जोड़े जा चुके हैं।

उप्र भाजपा में सियासी तपिश

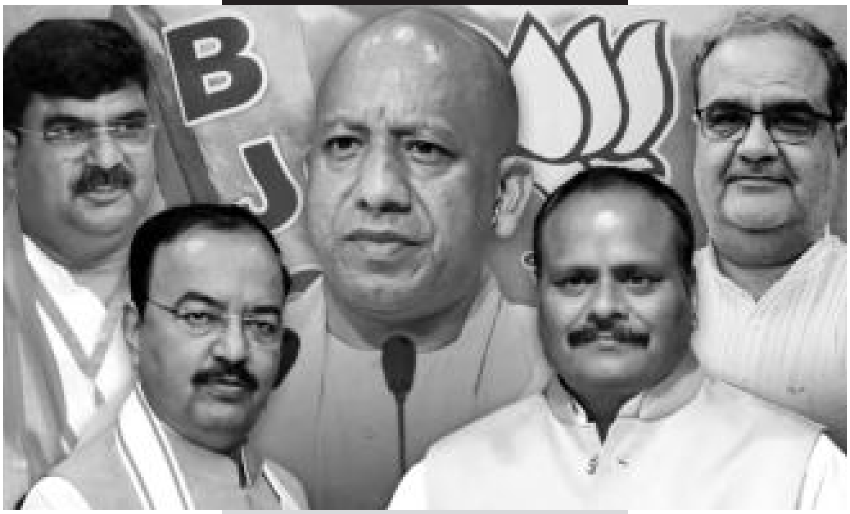

उप्र में भाजपा की सियासत एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी भाजपा हाईकमान से मिल चुके हैं। इस तरह भाजपा टॉप थ्री नेताओं की दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मिलने पर राज्य में सियासी तपिश बढ़ गई है और इसको लेकर सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत दिनों दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले। इससे पहले उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने दिल्ली में ही अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। केशव और पाठक के बाद मुख्यमंत्री योगी की भाजपा के टॉप थ्री नेताओं से मुलाकात ने सूबे की सियासी तपिश को काफी बढ़ा दिया है, जिसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जाने लगे हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका उप्र में लगा था, जिससे उसकी सीटें ही नहीं घटी थी बल्कि सियासी समीकरण भी गड़बड़ा गया था। भाजपा शीर्ष नेतृत्व प्रदेश संगठन से लेकर सत्ता के समीकरण में सियासी बदलाव करने की पटकथा लिखी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का प्रधानमंत्री मोदी से करीब एक घंटे की मुलाकात करना, इसके दूसरे ही दिन पश्चिमी उप्र में मुख्यमंत्री योगी, केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के एक मंच पर नजर आना भाजपा की सियासत के लिए अहम माना जा रहा है। उप्र में भाजपा अभी तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकी। भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल इस साल के शुरू में खत्म हो गया है और नए अध्यक्ष को लेकर सियासी मंथन के बीच पहले केशव, उसके बाद पाठक और अब मुख्यमंत्री योगी का भाजपा नेतृत्व से दिल्ली में मुलाकात को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सूबे के तीनों ही नेताओं ने दिल्ली में भाजपा हाईकमान से मुलाकात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपनी पसंद और नापसंद की राय भी रख दी है।

सूत्रों के मुताबिक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद उप्र अध्यक्ष का फैसला करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उप्र का मामला बहुत पेंचीदा हो गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी हाईकमान कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इस वजह से जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिश्तों का भी ख्याल रखा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ केशव और पाठक के साथ उसके सियासी संतुलन को देखा जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और फिर उप्र के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा। मतलब ये है कि उप्र भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में कई सारे पेंच हैं। नए अध्यक्ष की जाति को लेकर मंथन किया जा रहा है। पूर्वांचल से मुख्यमंत्री योगी हैं तो फिर पश्चिमी उप्र, अवध से अध्यक्ष बनाकर क्षेत्रीय बैलेंस बनाने का प्रयास है। उप्र के नेताओं की मुलाकात के पीछे की वजह प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाने की है।

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान उप्र में उठाना पड़ा है। उप्र की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 33 सीटें मिली हैं जबकि सपा 37 और कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 की तुलना में भाजपा की 34 सीटें कम हो गई हैं और 8 फीसदी वोट शेयर भी घटा है। अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण से भाजपा की सीटें ही नहीं घटी बल्कि पार्टी का जातीय समीकरण भी गड़बड़ा गया है। इसीलिए भाजपा उप्र की टॉप थ्री लीडरशिप के साथ चर्चा करके नए अध्यक्ष के नाम को फाइनल करना चाहती है, जिसके चलते ही मुलाकातों का दौर जारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को गैर-यादव ओबीसी वोटों खासकर पटेल, कुर्मी, सैनी और शक्य बिरादरी का एक बड़ा तबका भाजपा से छिटक गया था। निषाद पार्टी से गठबंधन के बाद भी मल्लाह जाति के एक हिस्से ने सपा को वोट किया था। इसके अलावा दलित वोट भी सपा से दूर हुआ है। ऐसे में भाजपा हाईकमान सूबे में पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की कवायद में है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष की कमान ओबीसी समुदाय के हाथों में देने की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

समन्वय बनाने का प्लान

उप्र में भाजपा की लीडरशिप में सियासी अदावत की खबरें मीडिया में आए दिन आती रहती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्ते दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के साथ अच्छे नहीं हैं। पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ भी योगी का वही संबंध है। ऐसे में पहले केशव प्रसाद का दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात करना और उसके बाद उप्र गवर्नर से लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करना। इसके बाद बृजेश पाठक दिल्ली आए और उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात की और उसके दो दिन बाद मुख्यमंत्री योगी दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह से मिले। उप्र भाजपा के टॉप थ्री नेताओं का दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से अलग-अलग मिलना और उसके बाद एक मंच पर साथ नजर आना, साफ है कि इस तरह से भाजपा ऑल इज वेल का सियासी संदेश देने की कवायद कर रही है। पिछले दिनों अमित शाह और योगी की बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला है और अब उप्र के नेताओं के बीच उसी तरह का समन्वय बनाने का तानाबाना बुना जा रहा है। उप्र के भाजपा नेताओं की दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात के पीछे सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाने की स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने नाराज पार्टी नेताओं का चिट्ठा खोलकर रख दिया, क्योंकि भाजपा और सहयोगी दलों के कई नेताओं ने पिछले दिनों खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुफ्त योजनाएं, विकास और कानून-व्यवस्था प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरे हैं। नीतीश कुमार मुफ्त बिजली और रोजगार के वादे कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं और तालिबान से इसकी तुलना कर रहे हैं।

मुफ्त योजनाओं की सियासत

लोकलुभावन घोषणाएं या फ्रीबीज अब चुनावी राजनीति का स्थायी हिस्सा बन चुकी हैं। दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सफलता पाने के बाद अब यह ट्रेंड बिहार में भी पूरी मजबूती से उभरकर सामने आया है, हालांकि नीतीश कुमार पहले फ्रीबीज देने के खिलाफ रहे थे, लेकिन बिहार में चुनावी दस्तक के साथ ही नीतीश कुमार ने फ्रीबीज की सौगातों की बौछार कर दी है। नीतीश कुमार की सरकार लंबे समय से छात्रों को साइकिल, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, नल-जल योजना जैसी योजनाओं के जरिए ग्रामीण और शहरी गरीब तबकों को साधने में लगी है। इन योजनाओं ने उन्हें सुशासन बाबू की छवि दी। अब चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने सौगातों की बौछार कर दी है। 1 अगस्त से राज्य के लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है।

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी जमीन पर पकड़ मजबूत करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बिहार में चुनाव की दस्तक के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार फ्रीबीज का ऐलान कर रहे हैं और नई-नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। वहीं, हर रोज हो रही हत्याओं ने सरकार की नींद उड़ा दी है। राज्य में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति की तुलना विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तालिबान से की है और लालू प्रसाद यादव के शासन में लगे जंगलराज के आरोप का जवाब दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 5 बार बिहार दौरा कर चुके हैं और गत दिनों मोतिहारी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया चुनावी नारा लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने राजद पर जोरदार हमला करते हुए गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की तरक्की पूरब भारत के विकास की नींव है। उन्होंने कहा कि बनाएंगे नया बिहार, फिर से एनडीए सरकार। केंद्र सरकार ने न केवल बजट में बिहार के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था, बल्कि अब और कई कल्याणकारी योजनाओं का लगातार शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों की घटनाएं, राजनीतिक गठजोड़, नीतियों की घोषणाएं और लगातार हो रहे अपराध यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि इस बार के चुनाव में मुख्य फोकस तीन प्रमुख मुद्दों पर रहने वाला है फ्रीबीज (लोकलुभावन घोषणाएं), विकास और कानून व्यवस्था यानी अपराध। नीतीश ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार अगले 5 वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करेगी, जिसमें से अब तक करीब 50 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि विद्यालयों में रिक्तियों की गणना कर टीआरई-4 परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की नई भर्ती शीघ्र शुरू की जाए। इस बहाली में 35 प्रतिशत आरक्षण बिहार की महिलाओं के लिए तय किया गया है।

इसके साथ ही नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया है, जिससे 1.11 करोड़ लाभार्थी सीधे प्रभावित होंगे। नीतीश की रणनीति स्पष्ट है- महिला मतदाताओं और जीविका दीदियों के दम पर चुनावी जमीन मजबूत करना। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटें मिली थीं, जिसे इसी महिला समर्थन का परिणाम माना गया। वहीं, विपक्षी दल, खासकर आरजेडी और तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हर बेरोजगार को भत्ता, महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवा रोजगार गारंटी जैसी घोषणाएं कर इस चुनावी विमर्श को और मजबूत किया है। तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री रहते 10 लाख नौकरियों की योजना शुरू की थी, जिसे वह अब फिर से मुद्दा बना रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं। दूसरी ओर, बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासन के दौरान एनडीए जंगलराज का आरोप लगाता रहा है। एडीए की पार्टियां कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्व सरकार की आलोचना करती रही हैं, लेकिन केवल जुलाई में ही बिहार में दर्जन से अधिक हत्या के आरोप लगे हैं। इन हत्याओं को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहा है।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं और कानून-व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं। नीतीश कुमार को लाचार और बीमार करार दे रहे हैं। राज्यभर में हत्याओं और हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर बिहार को तालिबान बनाने का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले, पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में विक्रम झा नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस महीने की शुरुआत में, जाने-माने व्यवसायी गोपाल खेमका की भी इसी तरह दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद शहर में एक रेत व्यापारी की उसके घर के बाहर हत्या कर दी गई। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मोदी-नीतीश सरकार बेबस है और अपराधी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन पर कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए लिखा कि कर-संरक्षित गुंडे और अपराधी बेलगाम हैं। इस तरह से विपक्ष के निशाने पर नीतीश सरकार है और विपक्षी नेता कानून-व्यवस्था पूरी तरह से बेहाल होने का आरोप लगा रहे हैं।

● **विनोद बक्सरी**

थाईलैंड-कंबोडिया जंग का स्पॉन्सर चीन

धरती पर जंग का एक और नया फ्रंट खुल चुका है। दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देशों की जंग शुरू हो चुकी है। ये दो देश हैं थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पुराना सीमा विवाद है, लेकिन इस विवाद के जंग में बदलने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस जंग का प्रायोजक है चीन। चीन को एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है और इसके लिए वो थाईलैंड का इस्तेमाल कर रहा है। 24 जुलाई की सुबह शुरू हुई जंग में अब तक 14 लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देश एक-दूसरे पर एमएलआरएस यानी मल्टीपल लॉन्च्ड रॉकेट सिस्टम हमले कर रहे हैं। थाईलैंड लड़ाकू विमानों से भी हमले कर रहा है। इस जंग के शुरू होने के पीछे क्या कारण है और चीन इससे क्या हासिल करना चाहता है? दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है, इससे पहले मई के महीने में भी दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी, लेकिन तब मामला इतना ज्यादा विध्वंसक नहीं हुआ था। 24 जुलाई की सुबह दोनों देशों की सेनाओं के बीच इन्फैंट्री और आर्टिलरी की जंग शुरू हुई और थाईलैंड की वायुसेना के हमले भी शुरू हो गए। थाईलैंड के सुरिन प्रांत और कंबोडिया के ओडर मेंची प्रांत की सीमा पर विवाद शुरू हुआ।

दोनों देशों के बीच इस संघर्ष की वजह वही पुरानी है। एक 1100 साल पुराना शिव मंदिर जिसे प्रेह विहेयर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को 9वीं सदी में खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने भगवान शिव के लिए बनवाया था। लेकिन वक्त के साथ यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवाद, राजनीति और सैन्य ताकत का अखाड़ा बन गया है। कंबोडिया ने सीमा पर स्थित शिव मंदिर के पास थाईलैंड के सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो वहीं कुछ घंटे बाद थाईलैंड ने 6 एफ-16 से ताबड़तोड़ जवाबी अटैक किया। दोनों देशों के बीच 2008 से 2011 के बीच जंग हो चुकी है। थाईलैंड को अमेरिका का करीबी तो कंबोडिया को चीन का करीबी माना जाता है। थाईलैंड के पास अमेरिका और यूरोपीय देशों के अत्याधुनिक हथियार हैं। हथियार के मामले में चीन का मित्र कंबोडिया थाईलैंड से काफी पीछे है। हालांकि, चीन के पड़ोस में होने का फायदा जंग में उसे मिल सकता है, लेकिन चीन ने अब तक खुलकर किसी भी देश का साथ नहीं दिया है। चीन दोनों देशों से इस मामले में सुलह की अपील कर रहा है। चीन नहीं चाहता है कि ऐसी नौबत आए, जब उसे किसी एक का पक्ष लेने पर मजबूर होना पड़े। थाईलैंड भले ही अधिकांश हथियार अमेरिका से खरीदता हो, लेकिन चीन उससे सीधी दुश्मनी तब भी मोल नहीं लेता है।

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग की नई शुरुआत साल 2008 में हुई थी। दोनों की सीमा पर एक 9वीं सदी का शिव मंदिर है। इसे कंबोडिया ने अपने नाम से यूनेस्को की सूची में शामिल करा लिया, जिसे थाईलैंड ने गलत बताया। कहा जाता है कि इस शिव मंदिर की स्थापना खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने की थी। थाईलैंड का कहना है कि यह मंदिर उसके हिस्से में है, जिसे कंबोडिया अपने नाम से कराना चाहता है। दोनों के जंग में पिछले 17 साल में 42 लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देश एक-दूसरे पर पहले गोलीबारी का आरोप लगा रहे हैं। गोलीबारी के बाद जंग भड़कती गई और दोनों देशों की सेना तीन प्रांतों में आमने-सामने आ गई। दोनों देशों में अपनी सीमाओं को सील कर दिया। ये जंग एक हजार साल पुराने एक मंदिर पर दावेदारी को लेकर शुरू हुई है। ये मंदिर कंबोडिया की आमदनी का बड़ा जरिया है। इसे देखने लाखों पर्यटक हर साल कंबोडिया आते हैं। इसके साथ साथ अंकोरवाट जैसे विश्व धरोहरों को देखते हैं। दो देशों के विवाद अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और विवाद ही सुपरपावर्स का बाजार बन जाते हैं। यही इस युद्ध में होने की आशंका बढ़ गई है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के इन देशों में अमेरिका और चीन अपना-अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटे हैं। थाईलैंड को अमेरिका का सामरिक समर्थन है। उसके पास एफ-16 अमेरिकी लड़ाकू विमान हैं। कंबोडिया के साथ चीन खड़ा है जो उसका सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है और सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करता है। थाईलैंड अमेरिकी हथियारों का बाजार है। चीन कंबोडिया को अपने हथियार बेचता है, लेकिन चीन के हित दोनों देशों से जुड़े हैं। चीन का वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट दोनों देशों से होकर गुजरता है। चीन चाहता है कि थाईलैंड में अमेरिका का प्रभाव घटाया जाए। चीन ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, लेकिन कंबोडिया को जंग के लिए हथियार भी वही दे रहा है।

अब तक की रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि जंग कंबोडिया ने शुरू की है और बिना चीन की मदद के कंबोडिया जंग नहीं छेड़ सकता है। सामरिक स्तर पर दोनों देशों की तुलना करें तो कंबोडिया थाईलैंड से बहुत कमजोर है और यही संकेत कि इतनी कमजोर हालत में उसने जंग छेड़ी है, तो इसके पीछे चीन हो सकता है। जंग अगर शांत भी होती है तो आने वाले समय में दोनों देश एक-दूसरे के लिए खतरा बने रहेंगे। ऐसी हालत में अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। डिफेंस बजट बढ़ाने का मतलब है कि थाईलैंड को या तो अमेरिकी हथियार खरीदने होंगे जो कि महंगे हैं या फिर चीन से सस्ते हथियार खरीदने होंगे। दूसरी तरफ कंबोडिया को भी हथियार खरीदने होंगे, जिससे वो चीन का कर्जदार बनेगा। इससे दोनों देशों में चीन का वर्चस्व बढ़ना तय है। इसीलिए जिनपिंग युद्ध के प्रायोजक हैं, ताकि आपदा को अवसर में बदला जा सके।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

कौन ज्यादा ताकतवर?

किसी देश की शक्ति 3 पैमाने पर मापी जाती है। पहला उसकी संख्या कितनी है। दूसरा उसके पास हथियार किस तरह के हैं और तीसरा देश आर्थिक तौर पर कितना ताकतवर है? थाईलैंड कंबोडिया से तीनों ही मामले में काफी आगे है। थाईलैंड की जनसंख्या 7.1 करोड़ है। यह आंकड़ा 2023 का है। वहीं कंबोडिया की आबादी सिर्फ 2 करोड़ के आसपास है। थाईलैंड के पास सैनिकों की संख्या भी कंबोडिया से काफी ज्यादा है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक, थाईलैंड के पास 3.6 लाख सक्रिय सैनिक हैं। कंबोडिया के पास 2.2 लाख सैनिक हैं। थाईलैंड के पास रिजर्व के रूप में 2 लाख सैनिक भी हैं, लेकिन कंबोडिया के पास ऐसा कुछ नहीं है। थाईलैंड का रक्षा बजट 5 अरब डॉलर का है, जबकि कंबोडिया का रक्षा बजट 1 अरब डॉलर से भी कम है। कंबोडिया का रक्षा बजट 84 करोड़ डॉलर है। क्रय शक्ति के मामले में भी कंबोडिया से थाईलैंड काफी आगे है। पर्यटन के लिए मशहूर थाईलैंड के पास हथियारों का जखीरा है।

खतरनाक होगा टैरिफ का दांव

शातिर गजनवी की मशहूर गजल का मतला है-गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। पुतिन और ट्रंप के बीच हाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। हां, बात केवल इतनी ही नहीं है। 2013 की मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतिस्पर्धा को लेकर मॉस्को गए ट्रंप ने रूसी अरबपतियों और राष्ट्रपति पुतिन की खातिरदारी से अभिभूत होकर कहा था कि वे पूर्व राष्ट्रपति ओबामा से भी अधिक प्रभावशाली हो चुके हैं। पुतिन का रंग उन पर इतना गहरा चढ़ा कि राष्ट्रपति बनने के बाद 2018 के हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में उन्होंने अपने खुफिया तंत्र के खिलाफ पुतिन का पक्ष लेते हुए यह मानने से इनकार कर दिया कि रूस ने अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ी कराई थी।

पुतिन के साथ अपने खास रिश्ते का दम भरते हुए उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति बनने के 24 घंटों के भीतर युद्धविराम करा देंगे। जब वह नहीं हुआ तो उन्होंने रूस के प्रतिबंध हटाने और क्रीमिया को रूस के भाग के रूप में मान्यता देने जैसे प्रलोभन देकर पुतिन को मनाने की कोशिशें कीं। जंग का ठीकरा जेलेंस्की के सिर फोड़ा, उन्हें तानाशाह बताते हुए व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने बुरा-भला कहा। उन्होंने यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद रोक ली और बिना शर्त बातचीत के लिए राजी किया।

युद्ध विराम के लिए ट्रंप ने पुतिन के साथ छह बार फोन-वार्ताएं कीं, परंतु पुतिन न केवल बात लटकाते रहे, बल्कि हर बातचीत के बाद बड़े-बड़े हमले करते रहे। इस महीने की बातचीत के बाद ट्रंप का पुतिन से मोहभंग हो गया और उन्होंने कहना शुरू किया कि वे उनसे नाखुश हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वे पुतिन से निराश हैं, पर हताश नहीं। उन्होंने यूक्रेन को नाटो के माध्यम से अधुनातन रक्षा प्रणाली और मिसाइलें देना शुरू करने का ऐलान किया और पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे 50 दिनों के भीतर युद्ध विराम के लिए राजी नहीं हुए तो रूसी माल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ जैसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। नाटो महासचिव मार्क रूटा ने तो चीन, भारत और ब्राजील को सीधे ही कह दिया कि या तो तीनों मिलकर पुतिन को युद्ध विराम के लिए राजी करें, अन्यथा अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाएं। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं और अमेरिकी सीनेट रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने वाले प्रस्ताव की तैयारी कर रही है।

रूस प्रतिदिन लगभग 70 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है, जिसका 47 प्रतिशत चीन खरीदता है और 38 प्रतिशत भारत। रूस इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उसके तेल की बिक्री बंद होने से दुनिया में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर चीन और भारत पर तो पड़ेगा ही, यूरोप और अमेरिका भी उससे अछूते नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ेगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। इससे रूस का नुकसान तो तब होगा जब चीन, भारत और ब्राजील तेल खरीदना बंद करेंगे। हालांकि तेल की कीमतें बढ़ने से रूस को फायदा होना तुरंत शुरू हो गया है। वैसे भी पुतिन को लगता है कि ट्रंप की धमकी गीदड़भभकी के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए पुतिन ने यूक्रेन पर 700 ड्रोन और दर्जन भर मिसाइलों से बड़ा हमला किया। अमेरिकी चेतावनी के जवाब में रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जखारोवा ने भी कहा कि अल्टीमेटम, ब्लैकमेल और धमकियां हमें मंजूर नहीं हैं। हम अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। रूसी शेयर बाजार में भी घबराहट की जगह तेजी दिखाई दी। ट्रंप का पुतिन से मोहभंग होना तो समझ में आता है, परंतु आर्थिक प्रतिबंधों के जिस हथियार से बाइडन कुछ हासिल नहीं कर पाए तो उसी को दोबारा चलाने का मकसद क्या हो सकता है? सुप्रसिद्ध इतिहासकार युवाल नोआ हरारी के अनुसार ट्रंप किलेबंदी की मानसिकता से काम करते हैं। उनकी नीतियों में किसी न किसी ठोस प्राप्ति का स्वार्थ छिपा रहता है।

यूक्रेन की सैनिक मदद के लिए उन्होंने नाटो को माध्यम बनाया, ताकि यूक्रेन को हथियार मिल जाएं और उन्हें नाटो के जरिए उनके दाम। ट्रंप दावा कर चुके हैं कि चीन के साथ सैद्धांतिक रूप से व्यापार सौदा हो चुका है, परंतु उस दावे को तीन हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन सौदे पर मुहर नहीं लग पाई है। उन्होंने भारत के साथ भी सौदा हो जाने का संकेत दिया है। अलबत्ता औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है कि इन्हीं व्यापार सौदों को मनमुताबिक और जल्दी निपटाने के लिए रूसी तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी जा रही हो। वरना यह बात पुतिन भी जानते हैं और ट्रंप भी कि शी जिनपिंग भी ट्रंप की धमकी में आकर रूस से तेल लेना बंद नहीं करने वाले। वे टैरिफ जंग में भी नहीं झुके, क्योंकि चीन के पास दुर्लभ खनिजों, चुंबकों और सेमीकंडक्टरों का ब्रह्मास्त्र था। उसके साथ आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को ही सौदा पटाना पड़ा।

● सुश्री नित्या

पुतिन को पीछे हटाना संभव नहीं

ट्रंप समझ चुके हैं कि सवा लाख से अधिक सैनिकों और अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा चुके पुतिन को बातों और धमकियों से पीछे हटाना संभव नहीं है। न ही वे इस अंतहीन लड़ाई में यूक्रेन के लिए अमेरिकी खजाना खोलने को तैयार हैं। इसलिए उन्होंने नाटो के जरिये हथियार बेचने का रास्ता चुना है, ताकि यूक्रेन अपनी रक्षा करते हुए रूसी सेना और रक्षा तंत्र को इतनी चोट पहुंचाता रहे कि एक दिन पुतिन थककर बातचीत के लिए विवश हो जाएं। दूसरी ओर, पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन की सैनिक और खुफिया शक्ति और रक्षा उद्योग को तबाह कर उसे ऐसे नाकाम राज्य में बदल देना है जहां रूसी हमलों के भय से कोई निवेश न करे और वह रूस पर आश्रित होकर रह जाए। इस खेल में भारत को कूटनीतिक निपुणता के साथ चीन के साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि ट्रंप उसी की सुनते हैं जिसके पास पलटवार की क्षमता होती है। चीन के पास पलटवार के लिए दुर्लभ खनिज हैं और रूस के पास तेल और अनाज। ऐसे में भारत को अपनी कूटनीति पर दांव लगाना होगा।

महिलाओं में स्वरोजगार बढ़ा

हाल की कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि देश में महिलाओं में स्वरोजगार बढ़ा है। एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी 37 प्रतिशत हो गई। यह बढ़त मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रमुख कारण महिलाओं के आत्मनिर्भर होने और किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना समझा जाता है। इन स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को पिछले 10 वर्षों में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सशक्त किया गया है।

उप्र के अमरोहा जिले का गजरौला ब्लॉक इन तथ्यों की पुष्टि कर रहा है। यहां पिछले दो वर्ष से दीदी की दुकान पहल के अंतर्गत चयनित एसएचजी की महिलाओं को व्यवसाय एवं उद्यमशीलता में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कई उद्यमी दीदी अपनी दुकान चला रही हैं। बी-एबल फाउंडेशन की एक परियोजना के तहत इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसमें उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संगठित एसएचजी से इन महिलाओं को चुना गया। अन्य महिलाएं भी इस पहल का हिस्सा हैं, जो किसी एसएचजी से नहीं जुड़ी हुई हैं। दीदी की दुकानों की खास बात यह है कि परचून और रोजमर्रा के राशन के सामान के साथ-साथ इनमें महिलाओं की जरूरतें संबंधी वस्तुएं भी मिलती हैं। इन दुकानों में सैनेटरी नैपकिन भी उपलब्ध हैं, जिन्हें लड़कियां, महिलाएं बिना हिचक खरीदती हैं। इन दुकानों पर रंग-बिरंगी चूड़ियां, राखियां, सिलाई-कढ़ाई आदि के सामान भी खूब मिलते हैं। एक दीदी की दुकान में फ्रिज होने से कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत और डेरी का सामान भी मिलता है। कई दुकानों में गिफ्ट आइटम भी बिकते हैं। इन दुकानों को कुछ निजी कंपनियों ने अलमारी, रैक और काउंटर टेबल अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व-सीएसआर के तहत उपलब्ध कराए हैं।

कई उद्यमी दीदी महीने में 20 से 25 हजार रुपए कमा लेती हैं। इस पहल के अंतर्गत दीदियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया है कि वे हर प्रकार का सामान अपनी दुकानों पर रखें, ताकि गांव वालों को न तो साप्ताहिक हाट-बाजारों पर निर्भर रहना पड़े और न ही शहर पर। इस योजना से सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि महिलाएं आगे आकर दुकानों का कारोबार संभाल रही हैं, जो एक जमाने तक सिर्फ पुरुषों का ही व्यवसाय माना जाता था। इससे कई प्रकार की लैंगिक रूढ़िवादिताएं बदली हैं। अब न केवल महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त हो रही हैं, बल्कि उनकी सामाजिक गतिशीलता में भी बदलाव आया है। स्वयं सहायता समूहों और उद्यमता से सशक्त हो रही महिलाएं बताती हैं कि उन्हें एक नई पहचान मिली है और अब उनकी भी एक आइडेंटिटी है। यह एक बड़ा बदलाव है। तमाम रिसर्च बताती हैं कि इस तरह की पहल से महिलाओं के आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि एक दीदी बताती हैं कि पहले वे अपने घर से बाहर नहीं निकलती थीं, पर अब उनकी दुकान गांव का एक अहम लैंडमार्क बन गई है।

यदि किसी को ऑनलाइन या डाक से कुछ मंगवाना हो तो वह दीदी की दुकान के पते पर पहुंच जाता है। इस तरह ये दीदियां सिर्फ गांव की जरूरतें ही नहीं, बल्कि एक प्रकार से गांव की आकांक्षाओं और आर्थिक सशक्तिकरण की ब्रांड एंबेसडर जैसी बन गई हैं। इस प्रोजेक्ट को यूनिसेफ की भी मदद मिल रही है। जैसे प्रत्येक माह सबसे अधिक बिक्री करने वाली दीदी को बैटरी से चलने वाला एक पंखा यूनिसेफ के सौजन्य से भेंट किया जाता है। अगले कुछ महीनों में यूनिसेफ और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से इस प्रोजेक्ट को और राज्यों में शुरू किया जाएगा, जिसमें कम्प्यूटर दीदी सेंटर्स की भी शुरुआत होगी। अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे झारखंड आजीविका की दीदी की दुकान, बिहार में दीदी की रसोई। कर्नाटक में नारी उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए सहगल फाउंडेशन के अंतर्गत अमृत स्टाल चलाए जा रहे हैं, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित हैं। महिला उद्यमिता की ऐसी योजनाएं लैंगिक समानता एवं सतत विकास लक्ष्य पांच के तहत सुचारू रूप से अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर और काम हो सकता है।

अभी बी-एबल फाउंडेशन इन सभी दीदियों को व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता आदि की ट्रेनिंग देता है, लेकिन इस पर और काम किया जा सकता है। महिलाओं को और अधिक डिजिटल प्रशिक्षण दिलवाया जा सकता है। इन दुकानों पर खिलौने रखे जा सकते हैं, जिससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाओं को और मजबूती मिले। हस्तशिल्प और वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट के ऐसे उत्पाद भी इन दुकानों पर रखे जा सकते हैं, जिनकी ग्रामीण इलाकों में मांग हो। महिलाओं को अधिक लोन सुविधाओं से जोड़ा जाना चाहिए। एक अहम मुद्दा जंक फूड से जुड़ा है। इन दुकानों पर मोटे अनाज से बने पौष्टिक खाद्य पदार्थ रखे जा सकते हैं।

● ज्योत्सना अनूप यादव

तनाव का प्रबंधन करें!

कामकाजी महिलाओं को कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने की ज्यादा जरूरतों के कारण तनाव होने की ज्यादा संभावना होती है। अगर आप तनावग्रस्त, अभिभूत या नियंत्रण से बाहर महसूस करती हैं, तो खुद को थोड़ा आराम दें। तनाव प्रबंधन के कुछ बेहतरीन तरीके हैं, सहारा ढूंढना, सामाजिक रूप से जुड़ना, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना और भरपूर नींद लेना। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अपने लिए समय निकालें और उस दौरान अपने तनाव को बाहर निकालें। साथ ही, कार्यस्थल पर अपने अधिकारों के बारे में जानें, जैसे कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के अपने अधिकार और व्यावसायिक खतरों से बचाव के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल का आपका अधिकार। जरूरत पड़ने पर, एचसीएल हेल्थकेयर क्लिनिक में लाइफ कोच से मिलें, जिनसे आप पूरी गोपनीयता के साथ अपनी निजी चिंताएं साझा कर सकती हैं और अपने जीवन को खुशहाल और तनाव-मुक्त बनाने के लिए जरूरी मार्गदर्शन और सहायता ले सकती हैं। यह परीक्षण अलग-अलग मुद्राओं में किया जाता है और हर महिला को इसे करने का तरीका पता होना चाहिए। इससे आपको स्तन में किसी भी गांठ या अन्य असामान्यता का शुरुआती चरण में ही पता लगाने में मदद मिल सकती है ताकि आप समय रहते आगे की कार्रवाई कर सकें।

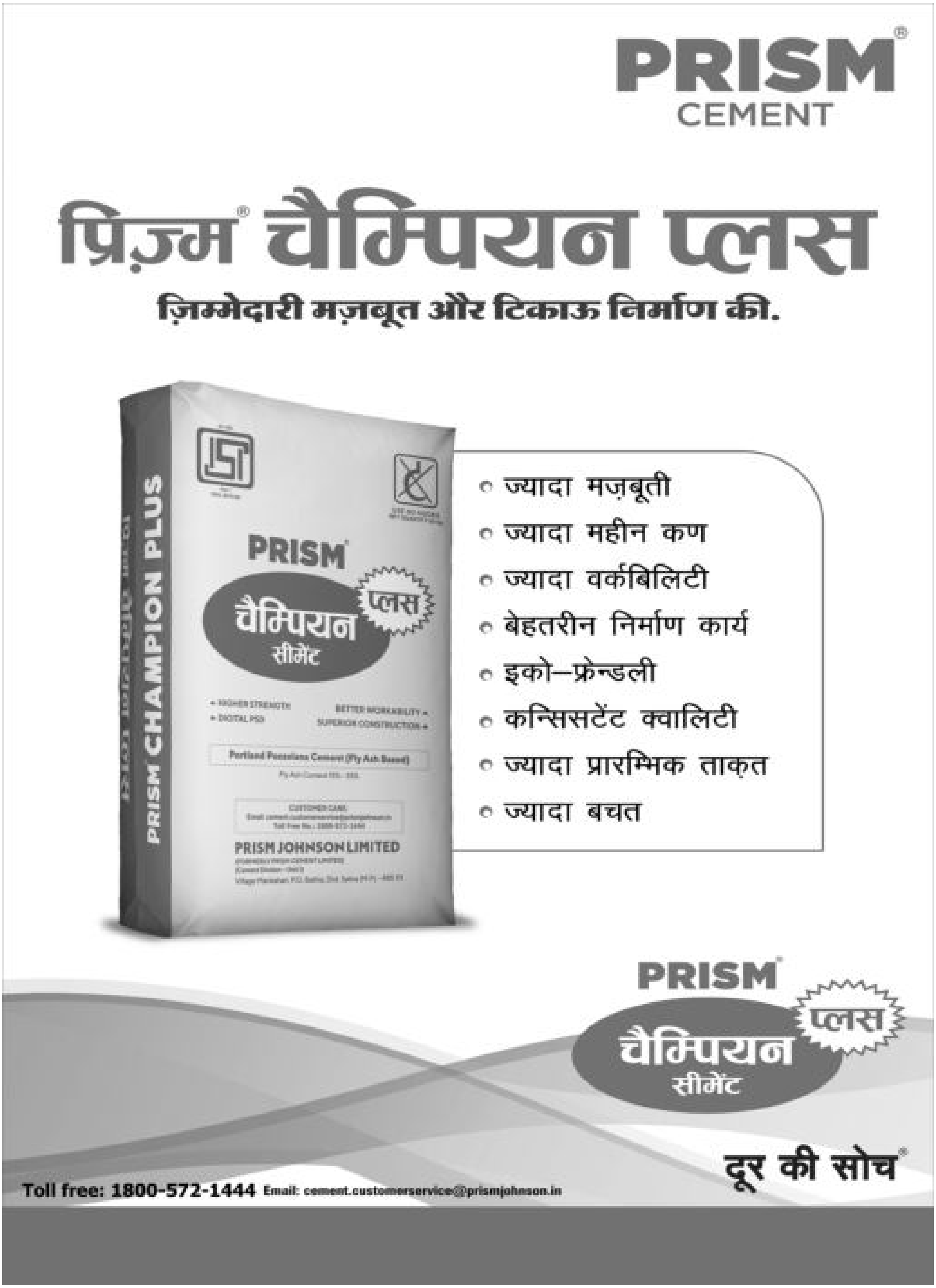
PRISM
CEMENT
प्रिज़्म चैम्पियन प्लस
ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.
PRISM CHAMPION PLUS
PRISM
चैम्पियन
प्लस
सीमेंट
PRISM JOHNSON LIMITED
ज्यादा मज़बूती
ज्यादा महीन कण
ज्यादा वर्कबिलिटी
बेहतरीन निर्माण कार्य
इको–फ्रेन्डली
कन्सिसटेंट क्वालिटी
ज्यादा प्रारम्भिक ताकत
ज्यादा बचत
PRISM
चैम्पियन
प्लस
सीमेंट
दूर की सोच
Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

अरमान

मां! मुझे नौकरी मिल गई है। सुदेश की यह बात सुनकर उसकी मां शीला मारे खुशी के उछल पड़ी। शीला ही क्यूं घर के सारे सदस्य बेहद प्रसन्न और रोमांचित थे। कोई रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मित्रों को फोन करके अपनी खुशी शेयर करता, तो साथ में मुंह मीठा कराने का सिलसिला भी चलता रहा। रात्रि के भोजन के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा तो सपनों की उड़ान आरंभ हो गई। सुदेश को लेकर हर किसी की आशाएं थीं, सपने थे।

बातों ही बातों में सुदेश की मां ने कहा– सुदेश की शादी में मैं तो दहेज में जी-भर के पैसे लूंगी, अपने हर अरमान पूरा करूंगी। आखिर सुदेश को सरकारी नौकरी जो मिली है। इतने धूमधाम से शादी करूंगी कि सारा शहर देखेगा। सबके लिए कपड़े, गहने, घर के सामान और भी बहुत कुछ।

दादी! तो क्या आप चाचू को बेचेंगी? शादी का मतलब बेचना होता है क्या? तभी अपनी दादी की गोद में बैठी रुचि बोल उठी।

बहू ने बेटी को चुप कराने का प्रयास किया पर वह तपाक से बोल उठी– आपने ही तो बताया था कि जब हम कुछ बेचते हैं तो बदले में पैसे मिलते हैं।

अचानक माहौल में सन्नाटा छा गया था।

– आकांक्षा यादव

साथ भले ही, नहीं रहो तुम

प्रेम नहीं केवल है तुमसे,
छाया तुम्हारी प्यारी है।
साथ भले ही, नहीं रहो तुम,
तुमसे हमारी यारी है।।
वाद-विवाद में नहीं है पड़ना।
राही हैं हम, नहीं है अड़ना।
तुम्हारी बात ही ऊपर मानी,
हमको नहीं है, ऊपर चढ़ना।
आकर्षित हम नहीं है केवल,
तुम्हारी आन भी प्यारी है।
साथ भले ही, नहीं रहो तुम,
तुमसे हमारी यारी है।।
आदत भले ही भिन्न-भिन्न हैं।
भले वियोग में आज खिन्न हैं।
जब भी तुम्हें जरूरत होगी,
नहीं दूर हैं, नहीं भिन्न हैं।
हमको कोई शौक नहीं है,
तुम्हारी शान ही प्यारी है।
साथ भले ही, नहीं रहो तुम,
तुमसे हमारी यारी है।।
प्रदर्शन की, तुम हो खिलाड़ी।
तुम्हारे आगे, हम हैं अनाड़ी।
नए-नए नित तुम्हारे शौक हैं,
हम हैं पुराने, चढ़ें न गाड़ी।
कर्म के पथिक, हम तो ठहरे,
तुमरी राह ही न्यारी है।
साथ भले ही, नहीं रहो तुम,
तुमसे हमारी यारी है।।

– डॉ. संतोष गौड़ राष्ट्रप्रेमी

अकेलापन

रमोला शादी होकर ससुराल आई। वह एक आईटी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थी। पति शलभ भी इंजीनियर थे। घर में सास-ससुर, देवर, ननद सब थे और सबके साथ थी बुजुर्ग दादी सास। सब अपने कामों में व्यस्त रहते। रमोला शलभ सुबह निकलते रात तक घर आते। ससुरजी की फैक्ट्री थी वह सुबह चले जाते दोपहर में सासुजी भी फैक्ट्री चली जाती। ननद मोना और देवर रचित भी कालिज। घर पर रह जाती दादी सास और गृह सेविका राधा। आज छुट्टी थी रमोला बाहर घर की बगिया में लैपटॉप पर काम कर रही थी। दादी सास उसके पास आकर बैठ गईं। वह बोली बहू यह क्या है। रमोला बोली अम्मा यह लैपटॉप है। आप सीखेंगी क्या। अम्मा बोली– हां मेरा मन करता है, मेरे पास पूरे दिन कोई नहीं रहता। रमोला ने दूसरे दिन अम्मा को लैपटॉप लाकर दिया और उनका एकाउंट बनाया और यूट्यूब पर भी एकाउंट बना दिया। प्रतिदिन ऑफिस से आकर उनको चलाना सिखाने लगी। घर में किसी को पता नहीं लगा। बस सब सोचते आजकल अम्मा अपने कमरे में ही क्यों रहती हैं पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि राधा उनके साथ ही रहती थी। एक दिन मोना ने जैसे ही यूट्यूब खोला देखा राधा ढोलक बजा रही है और अम्मा बहुत सुंदर भजन गा रही हैं और उनके बहुत संख्या में फोलोवर्स भी हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और बाहर सब डाइनिंग टेबल पर थे आकर सबको दिखाया। रमोला मंद-मंद मुस्करा रही थी। अम्मा जब बाहर आई तब शलभ बोला– अम्मा आप बहुत छिपी रूस्तम निकली। अम्मा ने रमोला के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर कहा– तुमको मेरी चिंता नहीं थी। बस मेरी बहू ने मुझे सिखाया और मेरे अकेलेपन का दर्द महसूस किया। सबको बहुत पछतावा हुआ कि बुजुर्ग कितना अकेलापन महसूस करते हैं।

– डॉ. मधु आंधीवाल

श्रीलंका में होगी भारत-पाक भिड़ंत

आगामी एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्वकप 2025 की मेजबानी 12 सालों बाद भारत को मिली है। लेकिन पिछले महीने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को भारत में खेलने से मना कर दिया था। ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में कराने का फैसला लिया गया है। इस मॉडल के अनुसार पाकिस्तानी टीम सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी। इस महाकुंभ का आगाज 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले से होगा तो वहीं सबसे बड़ा हाईवोल्टेज मुकाबला यानी भारत-पाकिस्तान का आमना-सामना 5 अक्टूबर को होगा जो श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा।

एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्वकप 2025 का बिगुल बज चुका है। भारत को इस टूर्नामेंट की मेजबानी दी गई है लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तान ने भारत आने से मना कर दिया। ऐसे में टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में कराने का फैसला लिया गया है। इस मॉडल के अनुसार पाकिस्तानी टीम सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होने वाले इस महाकुंभ में 8 टीमें भाग लेंगी और कुल 31 मैच खेले जाएंगे। विश्वकप का आगाज मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले से होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारत बनाम पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले की हो रही है। अगर पाकिस्तान की महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो 29 अक्टूबर को होने वाला पहला सेमीफाइनल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर टीम फाइनल में भी पहुंचती है तो खिताबी मुकाबला भी कोलंबो में ही होगा। पाकिस्तान नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंचती है तो पहला सेमीफाइनल 2 नवंबर को गुवाहाटी में और फाइनल बेंगलुरु में खेला जाएगा। आयोजकों ने हाइब्रिड मॉडल को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। आईसीसी द्वारा जारी सूची के अनुसार 5 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान का आमना-सामना होगा। यह मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। हमेशा की तरह इस बार भी दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबले में रोमांच और भावनाओं का जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। दर्शकों और खेल प्रेमियों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि भारत-पाकिस्तान का मुकाबला क्रिकेट जगत में सबसे चर्चित और देखे जाने वाले मैचों में से एक है।

विश्वकप में भारतीय महिला टीम के प्रदर्शन की बात करें तो भारत एक बार भी न तो टी-20 न ही वनडे विश्वकप का खिताब नहीं जीत पाई है। भारत ने अब तक 18 विश्वकप में हिस्सा लिया है इनमें 10 वनडे और 8 टी-20 शामिल हैं। टीम 9 बार नॉकआउट स्टेज में भी पहुंची लेकिन कभी अनुभव की कमी तो कभी बड़े मैच का प्रेशर भारत के आड़े आ गया। टीम को 6 बार सेमीफाइनल और 3 बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2017 से इंडिया विमेंस टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ टॉप-3 टीमों में शामिल रही। भारत ने तब से 7 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 6 के नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई। हालांकि, प्रेशर के कारण टीम को 5 में हार का सामना करना पड़ा, जिनमें 3 बड़े फाइनल शामिल रहे। 2 मुकाबले जीते भी लेकिन दोनों सेमीफाइनल थे। टी-20 विश्वकप में तो भारत एक भी नॉकआउट मैच नहीं जीत सका है। ऐसे में इस बार भारत के पास अपनी मेजबानी में खिताब जीतने का सुनहरा अवसर है। गौरतलब है कि इस बार टीमों को ग्रुप में नहीं बांटा गया है। सभी मुकाबले राउंड-रॉबिन फॉर्मेट यानी सभी टीमें एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी। लीग चरण के बाद अंक तालिका में शीर्ष 4 टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी, जहां दो सेमीफाइनल खेले जाएंगे। फिर फाइनल में नई चैम्पियन का फैसला होगा। इस टूर्नामेंट में 28 लीग मैच और तीन नॉकआउट मुकाबले पांच स्थानों बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और कोलंबो में खेले जाएंगे। वहीं पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में और दूसरा 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा। फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच से करेगा। जबकि बांग्लादेश के खिलाफ 26 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेलेगा। पाकिस्तान के सभी मैच हाइब्रिड मॉडल पर श्रीलंका में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच हुए हाइब्रिड समझौते के अनुसार पाकिस्तान की टीम अपने सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू कोलंबो में खेलेगी। इनमें बांग्लादेश से 2 अक्टूबर, इंग्लैंड 15 अक्टूबर, न्यूजीलैंड 18 अक्टूबर, दक्षिण अफ्रीका 21 अक्टूबर और श्रीलंका 24 अक्टूबर के खिलाफ मैच शामिल हैं। मौजूदा चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया अपना अभियान 1 अक्टूबर को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू करेगी। इसके बाद 8 अक्टूबर को कोलंबो में पाकिस्तान से भिड़ेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड का मुकाबला 22 अक्टूबर को इंदौर में होगा।

● आशीष नेमा

महिला विश्व कप में हिस्सा लेने वाली टीमें

भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में न्यूजीलैंड में महिला विश्वकप के फाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद मौजूदा चैम्पियन के रूप में इस आयोजन में प्रवेश किया है। वह अपने ताज को बचाने के भरकस प्रयास करेगी। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है जिसने सबसे ज्यादा सात बार चैम्पियन का ताज पहना है। 2025 के टूर्नामेंट का फॉर्मेट 2022 जैसा ही होगा, जिसमें आठ टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे से खेलेंगी और शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। मेजबान भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका ने सीधे क्वालीफाई किया था। आखिरी दो स्थान पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस साल की शुरुआत में लाहौर में हुए क्वालीफायर में हासिल किए। वेस्टइंडीज इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, वह क्वालीफायर में बांग्लादेश से नेट रन-रेट के आधार पर पिछड़ गई थी।

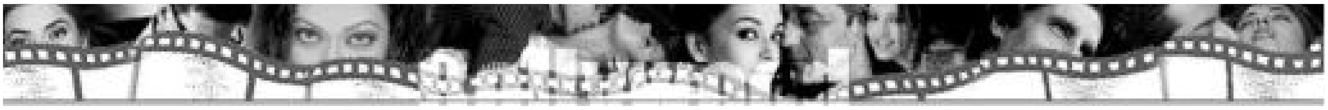

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी वो सितारा थी, जिसके पास जाने की ख्वाहिश हर एक दर्शक करता था, लेकिन उनके आसपास होना फिल्म स्टार्स के लिए भी मुश्किल होता था। वे एक अजीब सी खामोशी में घिरी दिखतीं, लेकिन पर्दे पर इतनी बोल्ड-बिंदास थीं कि 28 साल बड़े सुपरस्टार की हीरोइन बनी और फिर उसके बेटे के साथ रोमांस किया। एक्ट्रेस के अफेयर के बारे में हर कोई जानता था। पर्दे पर सगे देवर के साथ टूटकर रोमांस किया। वे जिन्हें राखी बांधती थीं, उन्हें अपना पति बना लिया। श्रीदेवी की जिंदगी की तरह उनकी लव स्टोरी भी बड़ी अनूठी थी।

...जब शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई ये अभिनेत्री

पर्दे पर देवर की बनी हीरोइन, बाप-बेटे संग किया रोमांस

अनिल कपूर के साथ दी हिट फिल्में... श्रीदेवी को जब मिस्टर इंडिया के लिए साइन किया गया, तो वे बोनी कपूर और उनके परिवार के करीब आईं। पर्दे पर देवर अनिल कपूर के साथ उनका रोमांस सुपरहिट रहा, जिनके साथ लाडला, लम्हे जैसी यादगार फिल्में दीं। दूसरी ओर, प्रोड्यूसर बोनी कपूर को अपना मुंहबोला भाई बना लिया और उनकी पत्नी मोना शौरी की करीबी दोस्त बन गईं।

श्रीदेवी की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तो लगता कि उनका जन्म ही सुपरस्टार बनने के लिए हुआ था। उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म मूंदरू मुदीचू में रजनीकांत से ज्यादा फीस मिली थी, जो तब सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। रजनीकांत के साथ उनका करीबी रिश्ता था। श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगभग 50 साल लंबे करियर में हर बड़ा मुकाम हासिल किया। उनके साथ स्क्रीन शेयर करने पर बड़े-बड़े सितारे गर्व महसूस करते थे। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने गुलाब से भरा ट्रक भेजकर श्रीदेवी को फिल्म खुदा गवाह में काम करने के लिए मनाया था।

श्रीदेवी ने 28 साल बड़े सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ फिल्म नाका बंदी में रोमांस किया, तो फिल्म सल्तनत में सनी देओल की महबूबा बनीं। धर्मेंद्र ने यमला पगला दीवाना के ट्रेलर लॉन्च पर कहा था, मैंने नाका बंदी में उनके साथ काम किया। वे प्यारी इंसान थीं और एक महान आर्टिस्ट थीं। उन्होंने अदाकारी से हर एक दिल को छुआ, लेकिन उनका दिल आखिरकार एक शादीशुदा मर्द पर आया, जिसे वे शुरू में अपना मुंहबोला भाई मानती थीं। कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ जब श्रीदेवी रिलेशनशिप में थीं, तब वे बोनी कपूर को राखी बांधती थीं और उनकी पत्नी मोना शौरी की सहेली थीं, लेकिन फिल्ममेकर की फीलिंग श्रीदेवी के लिए बिल्कुल अलग थी।

शादीशुदा होने के बावजूद श्रीदेवी के दीवाने हुए बोनी कपूर

बोनी कपूर शादीशुदा होने के बावजूद श्रीदेवी के प्यार में दीवाने थे, जिनके मैरिज प्रपोजल से श्रीदेवी हैरान रह गई थीं। उन्होंने करीब 6 महीने तक बोनी से बातचीत नहीं की थी। श्रीदेवी को मनाने में बोनी कपूर को 5-6 साल लग गए थे। कहते हैं कि जब श्रीदेवी मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, तब बोनी कपूर के करीब आईं। शादी से पहले ही उनके प्रेग्नेंट होने की खबरें सामने आईं, तो उन्हें घर तोड़ने वाली महिला का टैग मिला। प्यार में मजबूर दोनों ने किसी की नहीं सुनी और 2 जून 1996 में एक मंदिर में शादी कर ली, जिससे बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना शौरी को गहरा सदमा लगा। श्रीदेवी ने 24 फरवरी 2018 को दुबई में अंतिम सांस ली। वे तब 54 साल की थीं।

राज कपूर की वो फिल्म... जिसके लव ट्रायंगल ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस

राज कपूर दर्शकों की नब्ज पहचानते थे, ये कहना गलत नहीं होगा। उनकी फिल्मों की कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। ऐसी कुछ कहानी राज कपूर की 61 साल पहले आई फिल्म में नजर आई थी। फिल्म के लव ट्रायंगल ने तो दर्शकों का दिल ही जीत लिया था। साल 1964 में आई इस फिल्म ने कमाई के मामले में सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। साल 1964 में आई राज कपूर की उस फिल्म का नाम है संगम। इस फिल्म में राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला लीड रोल में नजर आई थीं। ये पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई थी। संगम के कई गाने थे, जो सभी के सभी हिट साबित हुए थे। राज कपूर और वैजयंती माला के साथ राजेंद्र कुमार तीनों सुपरस्टार की तिकड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया था।

80 लाख की फिल्म ने कूट डाले थे 8 करोड़

संगम के लव ट्रायंगल की आज भी मिसाल दी जाती है। संगम 3 घंटे 58 मिनट की फिल्म थी। फिल्म का बजट 80 लाख रुपए था, जबकि फिल्म ने 8 करोड़ की शानदार कमाई की थी।

माधुरी दीक्षित की वो फिल्म, जो फ्लॉप हुई तो एक्ट्रेस पर फूटा सारा ठीकरा

माधुरी दीक्षित ने जिस बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता था उसी साल उनकी एक फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। वह बड़े सुपरस्टार संग नजर आई थीं। इसके बावजूद फ्लॉप का ठीकरा सिर्फ उनके सिर फोड़ा गया था।

साल 1997 में उनकी एक ऐसी फिल्म आई थी, जिसमें उन्होंने सुपरस्टार के साथ रोमांस किया था। मगर फिल्म फ्लॉप हो गई और डायरेक्टर ने उन पर ही ठीकरा फोड़ दिया था। जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया था। ये फिल्म थी कोयला। जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान नजर आए थे। इस फिल्म को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। कहते हैं कि कोयला के फ्लॉप होने से राकेश रोशन का दिल टूट गया था।

फिल्म फ्लॉप होने से निराश थे राकेश रोशन

एक पुराने इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने बताया था कि राकेश रोशन कोयला के फ्लॉप होने से काफी निराश थे। वह अंदर तक सहम गए थे। जबकि उन्होंने फिल्म में सबसे बड़े सुपरस्टार्स को लिया था।

चोरों के नवाचार

कई तरह के चोर होते हैं। कुछ चोर बौद्धिक होते हैं तो कुछ शारीरिक श्रम को महत्व देते हैं। कुछ अपनी मेहनत से अपने ही पास इकट्ठी सामग्री की चोरी कर फर्रियां बनाते हैं और नई-नई जगह छुपाकर परीक्षा देने पहुंचते हैं।

पर आज अखबार की तीन खबरों ने वाचाल मन को शांत किया। जो कि बहुत दिनों से व्याकुल था कि मानव तकनीक के आगे हार मान गया है और अपना प्राकृत चौरय कर्म नहीं कर रहा। वह भूल गया कि तकनीक तो अभी इक्कीसवीं सदी में आई है वह तो न जाने कितनी शताब्दियों पूर्व से चोरी में माहिर है। ताजमहल तक को उसने चोरी से बनाया है। शाहजहां ने जब बनाया होगा उसे तो उसने भी नहीं सोचा होगा कि कैसे बनवाएं? उसने यह कल्पना भी नहीं की होंगी कि इतनी सारी बेगमों, और अर्ध बेगमों (अर्थ समझें) के होते हुए भी एक ही बेगम की याद में मकबरा क्यों हो? वह तो धन्य हो अंग्रेजों का जिन्हें उसमें यह बातें नजर आई और उन्होंने इसे मोहब्बत का प्रतीक बनाकर एक तरह से अपने रक्तरंजित शासन में थोड़ी सी मानवीयता, वह भी मुगलों की बनाई चीजों की चोरी कर अपने फायदे के लिए की। जो भी मजबूत किले, सालारजंग हो या कोलकाता संग्रहालय सभी अंग्रेजों ने नहीं दूसरे शासकों ने बनवाए। और तो और इन अंग्रेजों की कामचोरी भी ऐसी की एक भी महल, या किला कभी पहाड़ों अथवा खाइयों के बीच नहीं बनवा पाए। सारे हमारे ही राजपूतों, चोल, चालुक्यो, गुप्त और मौर्यवंश के ही काम में लिए। उनका काम ही यही था भारत की प्राकृतिक, उर्वरा भूमि संपदा को लूटना। चाहे रेशम, मसाले, हीरे-मोती हो या हमारे प्राचीन स्थल। ताजमहल की चोरी भी मुगलों ने ऐसे की कि हमारी पुरातत्व महत्व के सिरोही के पास जैन मंदिर और छतरियां हो या फिर हो मध्यप्रदेश के खजुराहो, उज्जैन के प्राचीन महल, दक्षिण में हम्पी, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर वहां के शिल्प की बारीकियों को लेकर ताजमहल बनाया। मध्य में याद आ गया तो ईरानी, अफगानी ढंग से भी चांद, तारे, फूल पत्तियां बना दी। उस चोरी के काम से बनी इमारत को जिसकी अस्सी प्रतिशत दीवारें कोरी पड़ी हैं, आजादी के बाद के इतिहासकारों ने मोहब्बत की मिसाल बनाकर पेश किया। यह भी नहीं सोचा कि अनगिनत बीवियों और औरंगजेब जैसे अत्याचारी पुत्र, जिसने शाहजहां को कैद में ही मरवा दिया का क्या वास्ता इस मकबरे से?

तकनीक से चोरी की खबर थी कि शर्ट के बटन में डिवाइस थी और पास में कार में सेटअप लिए बैठा बंदा पेपर हल करवाता। चोरी, पर इतनी मेहनत से? सोचो पेपर हाथ में आया, फिर प्रश्न पढ़े जाएं परीक्षा भवन के पूर्ण शांत माहौल में। वह भी एक नहीं पचास वह भी विकल्प सहित। फिर वह उत्तर बताए बाहर वाला सोचो जहां एक मिनिट से भी कम में प्रश्न हल करना होता है वहां इस सारी क्रिया में प्रश्न ही तीन मिनट में हल होता वह भी यदि बाहर वाला खुद होशियार होता। दूसरा पीछे बैठा तो और भी होशियार वह अंदाजे से पर्चियां बना लाया और वह भी मोजे के नीचे। अब इतना होशियार होता कि भांप जाता यह प्रश्न आएंगे तो वैसे ही हल कर लेता। तो तुक्के मारे। एक-दो दिखे तो अब उनके उत्तर के लिए तीसरी बार वॉशरूम गया। इस बार दो मिनिट बाद दबे पांव परीक्षक भी गया और वहां रंगे हाथों यह और दो और पकड़े। सभी की जेब से सारे नोट अपने पास लेकर परीक्षक ने त्वरित न्याय किया। साथ ही तीनों का भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया।

मैंने गौर किया कि चोरों की सोच मजबूरी और मनोविज्ञान क्या होता है, एक घर में चोरी करने घुसना इतना आसान नहीं होता। हिम्मत लगती है, शक्ति लगती है और सबसे जरूरी बात अनुकूल समय देखा जाता है। कोई घुसते देख ले तो आपको मार-मार के लाल कर दे। यह कोई सैफ अली खान का घर थोड़े ही है कि आधी रात को चोर छुपा मिल जाए तो उससे बातचीत की जाती है फिर नेगोशिएट होता है कि यहां-यहां और धीरे-धीरे मारना। फिर सारा मामला निपटाकर खुद ही ऑटो में अस्पताल निकलना पड़ता है। इतने सारे बचकाने कर्म तो चोर ने भी नहीं सोचे होंगे। ऊपर से हमारे मोहल्ले के टुच्चे लोगों तक के यहां सीसीटीवी कैमरे और वहां बड़े लोगों की बिल्डिंग तक में पीछे और दाएं-बाएं अंदर कोई कैमरा नहीं? मानो चोर को साथ ही अंदर लेकर गए और उसे टाइम टेबल दिया कि इतने बजे यह-यह करना है। दूसरे चोर सोचते होंगे कोई अपुन से भी मांडवली में यह काम करवाले।

ऐसा बावला हुआ कि यह भी भूल गया कि चोरी का उद्देश्य दिखाना था तो इतनी देर में कुछ तो उल्टा-पुल्टा किया होता। पर नहीं सब गोविंदा के अपने रिवॉल्वर से अपने ही ऊपर फायर करने जैसा मासूम काम निकला। अभी देखना दो-चार और आएंगे जिनकी कार में, जिम में, बेडरूम में कोई घुसा होगा और उन्हीं के एक्शन बोलने पर काम करेगा। फिर यह सुरक्षित उसे निकलने का रास्ता भी देंगे, वह भी सीसीटीवी कैमरों वाला।

तो चोरी करना बहुत खतरनाक काम है पर सड़क पार करने से जितना नहीं। क्योंकि वहां तो कब, कोई सी भी तेज, कानफोडू आवाज की बाइक पलक झपकते ही आपको उड़ा देगी। उससे बचकर निकले तो बिना आवाज किए तेज रफ्तार से आती कारें आपको ईश्वर के पास पहुंचा देंगी।

आजकल एक चोरी रोज हो रही की कोई कविता की पंक्तियां या पूरी कविता ही ले उड़ें (यह कविता शब्दों की है नारी न समझना) और उसे अपने नाम से फेसबुक पर लगा दे। शाम तक दस अन्य लोग हमारी कविता है का दावा कर दें। अब सच्चा कौन? यह तो कविता ही बताएगी। वह बताती भी है जब आगामी दिनों में कोई सिरफिरा महादेवी वर्मा, नीरज या शिवओम अम्बर की मूल पंक्तियां ढूंढकर वहीं पोस्ट कर देता है। तब वह दस दावेदार पता नहीं कहां गायब?

एक नवाचार टीवी एंकर, संपादक रोज करते हैं, न्यूज चोरी। किसी चैनल पर रिपोर्ट चली कि हरियाणा, महाराष्ट्र में भाजपा हार रही तो दोपहर और शाम तक उसकी काट में भाजपा जीत रही के इतने आंकड़े आ जाते हैं कि गिनना मुश्किल। और दोनों ही नकली।

ऊपर से एंकर का इतना आत्मविश्वास की लाइव कैमरे के सामने झूठ का अंबार खड़ा कर रहा। प्रवक्ता भी पूरी जिम्मेदारी के साथ झूठ को सच की तरह बोल रहा। चार्वाक होते तो आज अपने वंशजों को देख गर्व करते।

आजकल रुपए की चोरी नहीं गिनी जाती क्योंकि रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। आज तो चोर घर में घुसकर पहले रसोई और फ्रिज देखता है। फिर वहां से केक, पिज्जा, मिठाई खाता है। फिर मोबाइल फोन ढूंढता है। बेटी और पत्नी के लिए दो-तीन क्रीम और एक चोर तो नीकैप, घुटने के दर्द का स्प्रे भी ले गया।

● **डॉ. संदीप अवस्थी**

ANU SALES
CORPORATION
We Deal in
Pathology & Medical
Equipment
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
1 2 3 • 17 18 19 20 • 33 34 35 36 37 • 45 46
Dispensation
Aspiration
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687